ھاؤس کے بیٹھنے کا دن نہیں تھا اور یہ چانس کی بات ہے کہ ہم بیٹھ رہے ہیں اور گورنمنٹ نے ابھی تک ان باتوں کو کلیر نہیں کیا - جس کے بارے میں ہم نے سوال کیا تھا اور یہ چیز کافی افسوس ناک ہے - اگر آج پنجاب کا بل نہیں ہوتا تو شاید میں چپکے سے کچھ نہیں کہتا کیونکہ میں دکھی ہوں کہ اس طرح سے —اپوزیشن کو دبایا جا رہا ہے اور اپوزیشن کی بات کو نہیں سنا جا رہا ہے - اگر اپوزیشن غلط ہے تو اس کا فیصلہ ان کے خلاف آئیگا تو میں دکھی تو ہوں لیکن میں اپنا پروٹسٹ نوٹ کراتا ہوں کہ جو سرکار کا اٹیچوڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے ہیلپ فل نہیں ہے اپوزیشن والوں کے لئے - میں اس سمے واک آوٹ تو نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے پنجاب بل سے دل چسپی ہے - اور اس پر کچھ کہنا ہے شاید حکومت اسے درست کرے اور اسکی خامیاں دور کرے -

†[श्री अब्दुल गनी (पंजाब) : आपने हुक्म दिया था कि मेसर्ज़ अमी चन्द प्यारे लाल को जो लाइसेंस जारी किया गया था उसके बारे में गवर्नमेंट को इत्तला देनी चाहिए थी। चूंकि आज हाउस के बैठने का दिन नहीं था और यह चांस की बात है कि हम बैठ रहे हैं और गवर्नमेंट ने अभी तक इन बातों को क्लीयर नहीं किया। जिसके बारे में हमने सवाल किया था और यह चीज काफ़ी अफ़सोसनाक है। अगर आज पंजाब का बिल नहीं होता तो शायद मैं चुपके से कुछ नहीं कहता क्योंकि मैं दुखी हूं कि इस तरह से अपोज़िशन को दबाया जा रहा है और अपोज़िशन की बात को नहीं सुना जा रहा है। अगर अपोज़िशन गलत है तो उसका फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आएगा। तो मैं दुखी तो हूं लेकिन मैं अपना प्रोटेस्ट नोट कराता हूं कि जो सरकार का एटीच्यूट है वह अच्छा नहीं है, हेल्पफुल नहीं है, अपोज़िशन वालों के लिए। मैं इस समय वाक आउट तो नहीं करता हूं क्योंकि मुझे पंजाब बिल से दिलचस्पी है और इस पर कुछ कहना है शायद हुकूमत इसे दुरुस्त कर ले और इसकी खामियां दूर कर ले।]

श्री सभापति : मैंने कहा है...

شری عبدالغنی : آپ نے کہا ہے اور دو برس تک انہوں نے جواب نہیں دیا ہے -

†[**श्री अब्दुलगनी :** आपने कहा है और दो बरस तक उन्होंने जवाब नहीं दिया है।]

SHRI M. P. BHARGAVA (Uttar Pradesh) : Mr. Chairman, Sir, to put the records straight I want to say that nobody from the Treasury Benches or from this side gave any assurance that matters will be allowed to be raised for an hour.

MR. CHAIRMAN : Now, let me proceed to the debate.

THE PUNJAB REORGANISATION BILL, *1966—contd.*

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI JAGANNATH RAO) : Sir, may I make a submission ? The Business Advisory Committee has allowed four hours for the passage of this Bill and we have spent four hours yesterday. May I request you to fix a time by which all stages of the Bill should be completed ? There is the other Bill also.

t[ ] Hindi transliteration.

MR. CHAIRMAN : I would like all stages of this Bill to be finished before we adjourn in the afternoon. The second Bill could be taken up in the afternoon. We have to finish both the Bills.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया (मध्य प्रदेश) : सभापति जी, आपका कहना ठीक है, लेकिन ये जितने संशोधन हैं और जितने सदस्यों के नाम अभी आपके पास हैं उस हिसाब से यह संभव नहीं मालूम होता है कि यह इतनी जल्दी हो जायेगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार करें। यदि जल्दी हो सके तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जैसी स्थिति देखें उसके अनुसार कार्य करें तो अच्छा होगा।

MR. CHAIRMAN : I wish to finish both the Bills by five o'lcock today. As a matter of fact, the time allotted was in consultation with all Members of the Parties in the Business Advisory Committee and we have taken much more than that. We are allowing even more, but there should be a limit. By this afternoon, five o'clock, we have to finish both the Bills. If you take more time on this., you have to give less time to the other Bill.

Mr. Patil. In the light of these observations. I hone vou will be brief.

श्री उद्धवराव साहेबराव पाटिल (महाराष्ट्र) : सभापति महोदय, जिस समस्या पर इस समय विचार हो रहा है उसका सिलसिला दस बारह साल से जारी है। भारत देश में जो प्रांत अंग्रेजों ने बनाये थे वे मुख्तलिफ भाषाओं को एक जगह ले कर के बनाये गये थे और वे उनके हित के लिये थे। इस सरकार ने आज तक भी राज्यों का पुनर्गठन भाषा के सिद्धांत पर करना माना नहीं है। इस विधेयक को पढ़ने के बाद भी मैं यह कहूंगा कि आज भी इस सरकार की नीति भाषा को आधार मान कर पुनर्गठन करने की नहीं है। जब 1952 में दक्षिण में, आन्ध्र प्रदेश में यह मांग उठी कि आंध्र एक भाषा का राज्य हो, मद्रास हो, मैसूर हो और महाराष्ट्र हो तो मैं खास कर किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहता लेकिन नहीं मालूम क्यों उत्तरी इंडियन्स को इस भाषा के बारे में इस सिद्धांत को मानने में हिचकिचाहट उस वक्त भी थी और आज भी वे इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। उनमें कोई गलतफहमी है। सन् 1924 में कांग्रेस ने इस सिद्धांत को माना था कि इस देश में जो मुख्तलिफ भाषाएं हैं जिनकी बड़ी तारीफ है, जिनमें बहुत बड़ा साहित्य है, जिनका इतिहास है और जिनको कांस्टिट्युशन के शैड्युल में रखा गया है, उनके आधार पर प्रांत बनाये जायें। लेकिन भाषा के आधार पर, भाषा की बुनियाद पर, सूबे बनाने के लिये या प्रांत बनाने के लिये इस सरकार ने हमेशा हिचकिचाहट की है और माना नहीं है। दक्षिण में लोगों को काफी आन्दोलन करना पड़ा और महज इस वजह से कि केन्द्रीय सरकार ने यह गलत नीति अपनाई है कि भाषा के आधार पर प्रांत नहीं बनेंगे। इस नीति को बदलने के लिये कम से कम 12 साल तक हर प्रांत में आंदोलन होते रहे। सन् 1955-56 में जब स्टेट्स रिआर्गेनाइज़ेशन के लिये फ़ज़ल अली कमीशन मुकर्रर किया गया तो उस वक्त भी भाषा का आधार न मानते हुये मुख्तलिफ ऐसी समस्याएं पैदा हो गई उस कमीशन की रिपोर्ट से और इस हुकूमत की नीति से कि उस वक्त भी महाराष्ट्र और गुजरात को एक बनाने की कोशिश की गई और पंजाब को भी वैसे का वैसा रखा गया। फिर आज हम सन् 1966 में आ कर के पंजाबी सूबा बना रहे हैं। चार साल तक नेताओं में जदोजहद रही, आंदोलन रहा, हालात बिगड़ते रहे, दिलों में एक दूसरे के बारे में प्रेम के बजाय द्वेष पैदा हुआ और तब कहीं आ कर के यह विधेयक आया है।

मैं यह समझने से कासिर हूं कि केन्द्रीय सरकार इस भाषा के आधार पर प्रांत बनाने के लिये क्यों तैयार नहीं होती। अब यह बात दिमाग से निकाल देनी चाहिये कि हिन्दुस्तान में या भारत में कोई प्रांत बनने के बाद अपने को आज़ाद मान लेगा या कोई प्रांत हिन्दुस्तान में केन्द्रीय सत्ता के खिलाफ बगावत करेगा, बीसवीं सदी में यह नामुमकिन है किसी प्रांत

के लिये कि वह अपना संरक्षण या डिफेंस कर सके। आज डिफेंस की इतनी टैकनीक बढ़ गई है कि भारत जैसे बड़े देश को भी डिफेंस के लिये भीख मांगनी पड़ती है, कहीं रशिया से, कहीं अमेरिका से, और उसके लिये इतना खर्चा करना पड़ता है कि जो प्लानिंग का तजुर्बा रखते हैं वही इसका अन्दाज लगा सकते हैं। ऐसी हालत में चार करोड़, दो करोड़ या एक करोड़ की आबादी वाले किसी प्रांत को विज्ञान बढ़ा कर के अपना विकास करना नामुमकिन है। इस केन्द्रीय सत्ता या भारत की एक फेडरल स्टेट रहते हुये सब का विकास होगा, सब की तरक्की होगी, यह अहसास, यह फीलिंग हर प्रांत में, हर राज्य में है। इसके बावजूद भी शक क्यों किया जाता है कि हम भाषा को आधार मान कर कुछ करेंगे तो झगड़े होंगे। असल में इस सरकार की नीति ही ऐसी रही है जिससे झगड़े हुये हैं। इसके लिये मैं केन्द्र को ही जिम्मेदार ठहराऊंगा कि मुख्तलिफ भाषाओं में अगर झगड़ा हुआ है तो इस केन्द्रीय सरकार की गलत नीति की वजह से हुआ है। कांग्रेस ने 1924 में जो नीति अख्तियार की थी कि हर भाषा का प्रांत दिया जायेगा, उसको हुकूमत को सीधे सीधे मान लेना चाहिये था क्योंकि उसकी भी एक अहमियत थी। अगर हमारे देश में जमहूरियत या लोकशाही गांवों तक जानी है तो राज्यों की असेम्बली में जो कुछ कारोबार हो वह वहीं की भाषा में होना चाहिये, वरना पढ़े लिखे 2 फीसदी लोग ही असेम्बली, पार्लियामेंट और राज्यों के कारोबार में हिस्सा लेंगे और 98 फी सदी लोग ऐसे होंगे जिनको उससे कोई वास्ता नहीं होगा। यही वजह है कि पहले जब कभी भारत पर बाहरी हमला हुआ और किसी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया तो उसका पूरे हिन्दुस्तान पर कब्जा हो जाता था क्योंकि अवाम को यह कभी अहसास नहीं रहा कि यह राज्य हमारा है, यह समाज हमारा है। अगर जमहूरियत हम मानते हैं, अगर लोकशाही हम मानते हैं तो हर गांव में यह अहसास होना चाहिये कि यह राज्य हमारा है, यह समाज हमारा है, यह अर्थतंत्र हमारा है और इसके लिये यह जरूरी है कि हर प्रांत की भाषा राजभाषा होनी चाहिये। हिन्दी ज्यादा से ज्यादा प्रांतों में कारस्पांडेंस की, सम्बन्ध रखने की भाषा होनी चाहिये, लेकिन यह चीज उत्तरी इंडियन्स को पता नहीं क्यों पसन्द नहीं आती है। इसमें कोई झगड़े का सवाल नहीं है। हर भाषा का एक इतिहास है, साहित्य है और वह धर्म और संस्कृति का आधार रही है। विभिन्नता में भी एकता भारत में रही है और इस सिद्धांत और इस दृष्टि से अगर हम इस देश को देखेंगे तो ये झगड़े नहीं होंगे।

इस बिल को पढ़ने के बाद मुझे आज भी यह शक है कि हुकूमत की नीति में कोई फर्क आया है। गवर्नमेंट ने जो बाउंड्री कमीशन मुकर्रर किया और उसको जो टर्म्स आफ रिफ्रेंस दिये गये उसी से इस हुकूमत की क्या नीति है, यह मालूम हो जाता है। भाषा सोशल और कल्चरल इंटेग्रिटी के लिये है और अगर इस बुनियाद पर यह कमीशन कायम होता तो शायद आज ये झगड़े न होते, लेकिन यह चीज नहीं की गई। उस कमीशन को दीगर टर्म्स आफ रिफ्रेंस दिये गये जैसे ऐडमिनिस्ट्रेटिव कनविनिएंस देखी जाय, इकोनामिक वैल-बीइंग देखी जाय और इसके साथ और चीजें जो उसमें रखी गई उसकी वजह से इस बिल पर इस सदन में कोई खुश नहीं है। न उस साइड के और न इस साइड के सदस्य यह मानते हैं कि भाषा के आधार पर ये पंजाबी सूबा और हरियाना प्रांत बनेंगे। कितने हिन्दी बोलने वाले इलाके पंजाब में आये हैं और कितनी पंजाबी बोलने वाले इलाके हरियाना और दूसरे प्रांत में आये हैं। फिर भी यह कैसे बनाया जा रहा है यह मेरी समझ में नहीं आता है। अगर वहां पंजाबी सूबे में पंजाबी राजभाषा होने वाली है, तो उनकी अपनी यूनिवर्सिटी होनी चाहिये, उनका ऐडमिनिस्ट्रेशन पंजाबी में चलना चाहिये, हाई कोर्ट पंजाबी में चलना चाहिये। अब जैसे मैं मराठी भाषी हूं तो मेरी भी यह ख्वाहिश होती है कि हमारे राज्य में पूरा कामकाज मराठी में हो और यह

[श्री उद्धवराव सहेबराव पाटिल]

भारत के खिलाफ नहीं जाता है। जब मैं यहां तकरीरें सुनता हूं तो मुझे हैरानी होती है। पंजाबियों को देश की सेवा करने के बारे में शहादत देने की जरूरत नहीं है, वे किसी से कभी पीछे नहीं रहे हैं। पंजाब के लोग भी भारत के साथ उसी तरह से प्रेम करते हैं जैसे महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र या किसी प्रांत के लोग करते हैं।

एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि 1956 में जब रिआर्गेनाइजेशन हुआ था तो उस वक्त भी बम्बई को कम्पोजिट रखने के लिये कहा गया था। ऐसा इसलिये था कि कांग्रेस के अंतर्गत झगड़े थे, उनके अन्दरूनी झगड़े थे, फिर लोगों ने वहां आन्दोलन किया। महाराष्ट्र वालों को बदनाम किया जाता है कि वे झगड़ालू हैं। अगर वे शांति से लड़ें तो उनको क्यों बदनाम किया जाता है? आज वही झगड़ा वहां रह गया है। मैं नन्दा जी से फिर इस बात के लिए कहूंगा कि जब दो स्टेट बन जाते हैं, दोनों स्टेट में केबिनेट बन जाती हैं, उसके बाद आप कहेंगे पंजाब में हिन्दी का सर्किल है, हरियाना में पंजाबी का सर्किल है, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो तो उस वक्त तक उनके इन्टरेस्ट हो जाते हैं और मुश्किल पड़ती है। अगर आज इस बुनियाद पर कर देते तो आपको आइन्दा के लिए परेशानी न उठानी पड़ती। जो लोग सरहद पर रहते हैं उनके लिए बाउन्डरी बड़ी मुश्किल की चीज हो जाती है। उसमें हिन्दी और पंजाबी का संघर्ष जरूर रहेगा। आप जो कहते हैं प्रेम होगा, प्रेम नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जो पंजाबी लोग हरियाना में रह गए हैं वे पंजाबी प्रान्त में जायें, अपनी भाषा और बच्चों के लिए आगे चल कर तरक्की के लिए रास्ता निकालें।

एक और मसला पड़ा हुआ है जो एक साथ टाला जा रहा है—मैसूर और महाराष्ट्र का। 10 साल से वह मसला पड़ा हुआ है। पन्तजी ने आश्वासन दिया था कि बेलगांव के बारे में जहां दस लाख मराठी लोग हैं, बाद में सोचा जायगा, जोनल कौंसिल में सोचा जायगा। दो मुख्य मंत्री बैठे, लेकिन कोई तस्फिया नहीं हुआ। आज भी झगड़ा है। इसकी वजह है कि दोनों मुख्य मंत्री एक ही पार्टी के थे लेकिन केन्द्रीय सरकार इतनी कमजोर है कि उनको कह नहीं सकती कि हमको यह सही मालूम होता है, आप लोग इस सिद्धान्त को मान लें। उसकी वजह से क्या होता है? जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए कोई प्रगति का मौका नहीं है, उनके बच्चों के लिए नहीं है। इसके अलावा संघर्ष जरूर है यहां पर।

मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, यही कहूंगा कि चाहे चन्डीगढ़ का मसला हो, चाहे बार्डर का मसला हो, खुले दिल से आज ही हल कर लेते भाषा की बुनियाद पर तो झगड़ा आइन्दा न होता। आइन्दा यह झगड़े जरूर होंगे। शायद एक साल के बाद ही हम देखेंगे कि इन प्रश्नों को कांग्रेस के नेता वहां बैठ कर हल नहीं कर सके। फिर लोगों को कांग्रेस को दुरुस्त करने के लिए आन्दोलन करना पड़ता है, और उनको जेल भेजने की वही मुसीबत उठानी पड़ती है। इसलिए मैं सदन के तमाम मेम्बरों से कहूंगा कि भाषा का सिद्धान्त मानकर बाउन्डरीज मुकर्रर करिए, भाषा का ही सिद्धान्त मानकर चन्डीगढ़ का मसला हल कर दीजिए। इतना कह कर मैं खत्म कर देता हूं।

DIWAN CHAMAN LALL (Punjab): Mr. Chairman, I have very serious doubts in my mind about some of the provisions of this particular measure, whether they are likely or not to pass muster before the High Court or the Supreme Court. Personally I would have preferred, what the late Prime Minis'er, Pandit Jawaharlal Nehru, had done, namely, not to divide the Punjab again. I would have preferred that because he was a very wise man indeed and he realised that the Punjabi language was a language that was spoken throughout the Punjab as it was. You take Haryana. People do not seem to realise that even in Haryana millions of people are settled down who came away from West Pakistan whose mother tongue is Punjabi. I do not go by the

census report. The census report was doctored and people whose mother tongue was Punjabi said that their mother tongue was Hindi, and it is on that basis I think that my hon. friend, the Home Minister, has divided the Punjab again. We saw the misery and the un-happiness that was caused to millions of people when Pakistan was created, and I think if you were, to look into the actual facts of the situation and not go by a doctored report on the census, you wiH realise that what is happening in Punjab is exactly what the Prime Minister, late Pandit Jawaharlal Nehru, thought, namely, that the whole of Punjab is really a Punjabi speaking State. | and I am quite certain in my mind that those who have claimed for a separation or division of Punjab are the ones who will certainly regret the fact that they claimed this division. They will regret it in the end. They are bound to regret j it because it is an unnatural division. You are dividing Punjabi from Punjabi. '

Take the case of a little village where I have been allotted a little land. ID my own right I had about 10,000 acres of land in Pakistan. In lieu of that 1 was allotted the handsome sum of 300 acres of land which has now been whittled down to about 100 acres under the new legislation that has been passed. In that village of Kharwan there used to be only three Punjabi speaking families in the pre-partition days. Today out of 'he 3000 families there are 3 famil'es which are Hindi speaking or Urdu speaking. They are Muslim iami-lies whose language is Urdu. But this is the state of affairs throughout Harya-ana, and I am very very sorry indeed that this advice was given to the Government to divide Punjab once again.

Mr. Chairman, I started by saying that I am not so sure that some of tbe provisions of this measure will stand up to a scruitny by the High Court of the Supreme Court. Let us have a look at clause 10 :

> "(1) On and from the appointed day, the eleven sitting members of the Council of States representing the existing State of Punjab shall be deemed to have been elected to fill the seats allotted to the States of Haryana and Punjab and the Union territory of Himachal Pradesh, as specified in die Fourth Schedule."

Then it says :

> "(2) The terms of office of such sitting members shall remain unaltered".

Clause 11 says :

> "(1) As soon as may be afer the appointed day, bye-elections shall be held to fill the vacancies existing on the appointed day in the seats allotted to the State of Haryana.
>
> (2) The term of office of such one of the two members so elected, as the Chairman of the Council of States may determine by drawing lot, shall expire on the 2nd day of April, 1968, and the term of office of the other member shall expire on the 2nd day of April, 1972."

This is completely anomalous What is sought to be done under this is tbe fact that one of the seats which may ce declared by you, Sir, by drawing a lot shall expire on the 2nd day of April, 1968, and the term of office of the other Member when you have taken Jhe lot shall expire on the 2nd day of April, 1972. This is a complete anomaly. Let us have a look at the Fourth Schedule on page 58 :

> "1. Of the three sitting members whose term of office will expire on the 2nd April, 1968, Shri Surjit S'ngh and such one of the two members, namely, Shri Abdul Ghani and Shri Chaman Lal, as the Chairman ct the Council of States may determine by urawing tot, shall be deemed to nave been elected to fill two ot the seats allotted to the State of Punjab and the remaining member shali be deemed to have been allotted to fill on<» of the seats allotted to the State of Haryana."

In clause 1 this is the procedure laid down. Shri Surjit Singh Atwal has been made an exception of in regard to this matter. He has been allotted a seat in Punjab whereas Moulvi Abdul Ghani and myself we have to depend upon a lot to be cast by you, Sir, and you will have to decide then, after casting the

[Diwan Chaman Lall.] lot, whether Moulvi Abdul Ghani goes to Punjab and I go to Haryana or I go to Punjab and he goes to Haryana.

Then in clause 2 of this particular Fourth Schedule another me'hod has been adopted and in clause 3 a still further, different method has been adopted. Clause 2 says:

> "Of the four sitting members wbosa term of office will expire on the 2nd April, 1970, namely, Shri Anup Singh, Shri Jagat Narain, Shrimati Mohinder Kaur and Shri Uttam Singh Dugal, such one as the Chairman of the Council of States may determine by drawing lot shall be deemed to have been elected to fill one of the seats allotted to the States of Haryana, and the other three sitting members shall be deemed to have been elected to fill three of the seats allotted to the State of Punjab."

Why was not this particular method which affects my old friend, Shri Uttam Singh Dugal, adopted as far as the others are concerned whose term expires in 1968 ? Why was a different method adopted in the case of Sh' i U.S. Dugal and his colleagues and my friend, Dr. Anup Singh ? Why was it that a different method was adopted as far as we three are concerned, Moulvi Abdul Ghani, Shri Surjit Singh and myself, ...

सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी (पंजाब): इसलिए कि अटवाल साहब का तो पंजाब का एड्रेस है और आप दोनों का हरियाणा प्रान्त का एड्रेस था ।

DIWAN CHAMAN LALL : Yes, my learned friend is insapable of understanding anything in regard to this matter. What I am suggesting is this that if our addresses were Haryana addresses. ..

SHRI G. RAMACHANDRAN (Nominated) : May I rise on a point of order ? I can understand a Member saying of another that he does not understand but is it parliamentary to say that a fellow-Member is incapable of understanding ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI GULZARILAL NANDA) : His capacity to understand is better.

MR. CHAIRMAN : I do not thi»k you meant to discuss that.

DIWAN CHAMAN LALL : I think the hon. Home Minister has really not understood the point that I am driving at. The point that I am driving at is this. I wish he had not made that particular remark. My friend. Mr. Panjhazari, has not really understood the significance of what I am saying and I am quite certain that my hon. friend, the Home Minister, has not understood the point that I am driving at. *(Interruptions)* . He has not understood it because he himself is guilty of making this particular discrimination. He has made this discrimination in the case of Sardar Dugal. Moulvi Abdul Ghani and myself are the people who are affected by this thing in regard to these ma'ters. This is a discrimination. As I said, Sir, there is one. method followed in regard to ...

सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी : दीवान चमन लाल जी ने कहा कि मैंने अंडरस्टुड नही किया लेकिन यह तो अंडरस्टुड किया ही है कि जो उनकी जायदाद या प्रापर्टी है वह सारी हरियाणा प्रान्त में आई । वहां के वह वोटर हैं तो जिस जगह के वोटर हैं उस इलाके में आना पड़ेगा या जिस जगह के वोटर नहीं है उस इलाके में जाना पड़ेगा ।

DIWAN CHAMAN LALL : Mr. Panjhazari has not again understood the point. I am there in Haryana, I am a voter in Haryana, I am a voter in Jaga-dhri, I have my property in Jagadhri. But, nevertheless, what has my friend, the Home Minister, done? He has given a seat to Mr. Surjit Singh Atwal. But as far as I am concerned and MouM Abdul Ghani is concerned., we have got to depend upon the lot to decide whether we should go to Punjab or we should go to Haryana.

THE MINISTER OF STATE IN *im* MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI JAISHKHLAL HATHI): You will not have to go to Punjab.

DIWAN CHAMAN LALL: I hope not. As it is ...

SHRI JAISUKHLAL HATHI: You will be represented for some time.

DIWAN CHAMAN LALL : I want to draw the attention of my friend, Mr. Panjhazari, to this particular matter that although I am a voter in Haiyana, nevertheless, a lot has to be drawn by the honourable Chairman of this House and according to that lot, he will decide, it is not that I will be automatically in Haryana. He will decide whether I am in Haryana or whether Moulvi Abdul Ghani will be in Haryana. That is the point.

SHRI SURJIT SINGH ATWAL (Punjab) : With your permission, Sir, I want to make a suggestion that I am ready to go to Haryana if he does not like to go there.

DIWAN CHAMAN LALL : It has nothing to do with Mr. Atwal. I am drawing the attention of the Home Minister to ...

MR. CHAIRMAN : Two methods.

DIWAN CHAMAN LALL : I am going to finish this point.

I am drawing the attention of the Home Minister to this discrimination that exists. I do know how it crept in or whether my hon. friend, the Home Minister, was even aware of these facts or not. I do not know how this discrimination crept in. Look at the. second portion. In the second portion, this discrimination does not exist. There, in the case of Dr. Anup Singh, Shrimati Mohinder Kaur, Shri Jagat Narain and Shri Uttam Singh Dugal, it is you, Sir, who will draw the lot and decide which one of these people goes to Haryana and which one goes to Punjab.

Look at the third clause. Again a different procedure has been adopted. Clause 3 says :

"Of the four sitting members whose term of office wiH expire on the 2nd April, 1972, Shri Neki Ram shall be deemed to have been elected to fill one of the seats allotted to the State of Haryana; Shri Narinder Singh and Shri Raghubir Singh shall be deemed to have been elected to fill two of the seats allotted to the State of Punjab; and Shri Salig Ram shall be deemed to have been elected to fill one of the seats allotted to the Union territory of Himachal Pradesh." LI 24RS/66—2

Now, these are the three methods. What I am suggesting is this that personally I think that when anybody goes to the High Court or to the Supreme Court, I am quite certain that there will be legal complications, a provision of this nature will be challenged and if it is challenged, it will be hard put to it to answer in regard to this particular matter. I wish my hon. friend had consulted me in regard to this matter or consulted anyone of us who is affected by this.

SARDAR RAGHBIR SINGH PANJHAZARI : The Home Minister consulted but unfortunately you were not there.

DIWAN CHAMAN LAL : I was there. I went to his room but he had gone to Parliament. He was inside the Lok Sabha. I did go to his room. But I wish that he had consulted those who were affected by this particular measure and if he had consulted them, then probably this difficulty would not have arisen.

PROF. SATYAVRATA SIDDHANTALANKAR (Nominated) : Sir, it is very unfortunate that I rise to oppose this Bill. I oppose it because it is based on communalism, I oppose it because it is the result of pressure, I oppose it because it will result in the disintegration of the countiy.

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

It is the result of communalism because from history you will notice that it originated in the form of a communal demand. In 1942 when the British Cabinet Mission came to India, Master Tara Singh and Sardar Pratap Singh met the Commission and made a demand for Azad Punjab, if India were to be partitioned. Now, it was the good sense of the British Cabinet Mission that they did not accept this demand. But later on, these very people went and saw Mr. Jinnah, and made the same demand. Mr. Jinnah also rejected it and ultimately in 1947 when India was partitioned, at that time also, Master Tara Singh wanted a separate Suba for the Sikhs which he called the Punjabi Suba. Of course, when India was partitioned, there was a great demand for the linguistic division of the country and Master Tara Singh

[Prof. Satyavrata Siddhantalankar.]

and his people thought that it would be better for them to give it a linguistic touch to the demand. Therefore, they raised the demand on a linguistic basis. When this linguistic demand was made by the Akali people . . .

SHRI NARINDAR SINGH BRAR (Punjab): Master Tara Singh's demand was a communal one but Sant Fateh Singh's demand was for a Punjabi Suba.

PROF. SATYAVRATA SIDDHANTALANKAR : It was a communal demand. Then came the demand for an Azad Punjab. But when India was partitioned, it was changed into a linguistic demand because they thought that linguism perhaps was a better demand than the communal demand. Therefore, so many linguistic demands came up. It was said that they wanted Punjabi to be included in the Eighth Schedule of the Constitution. This demand was accepted because it was a right demand. Punjabi being a very good and prosperous language it was accepted as one of the languages for the Eighth Schedule.

Then another demand was made, namely, that Punjabi should be made the official language of Punjab. That was accepted in 1960 under the Punjab Official Languages Act. Further on, the demand for the language still persisted and a language department was opened in Punjab where particular attention was given for the cultivation of Punjabi and ultimately a Punjabi University was established in Punjab with an emphasis for the cultivation of the Punjabi language. Now all this shows that there was a genuine desire for the cultivation of the Punjabi language and all these demandsi were accepted by the Government.

Madam, if this demand had remained confined to the development of a language one could easily understand the reasonableness of the demand. But in-between the communal demand again sprang up and Master Tara Singh demanded that just as the Scheduled Castes have got special rights, similarly the backward classes among the Sikhs must also be given special rights. Now this demand, though communal in its background, was also accepted. Of course, everybody knows that among the Sikhs there are no Scheduled Castes; they do not believe in the caste system; still this demand was put forth and it was accepted.

DR. ANUP SINGH (Punjab) : I am sorry, in theory there may not be castes but in practice there is a good deal of caste system among the Sikhs.

PROF. SATYAVRATA SIDDHANTALANKAR : It may be there in practice. But among the Sikhs generally there is no such thing as Scheduled Castes or backward classes. All are equal there. Therefore, this demand was only a communal demand and that was accepted.

Now again history takes a new turn and this linguistic demand again takes the form of a communal demand. In 1960, Master Tara Singh launched upon a fast unto death. He demanded that a Punjabi Suba should be conceded. Madam, if all your demands for the development of language are accepted, then there is no reason for you to demand a Punjabi Suba. Your fundamental demand was for a Punjabi Suba based on the Punjabi language. That was accepted. You were given the Punjabi language and you were given a department for the development of the Punjabi language. Everything possible was given. Still the demand went on. Here it again turns into a communal demand. Master Tara Singh launched upon a fast unto death. He went on fasting for about a month or so; yet he did not lose weight. God alone knows what inspired him in his fast that for so manv days he continued having the same weight.

AN HON. MEMBER: Spiritual strength.

PROF. SATYAVRATA SIDDHANTALANKAR : May be any strength but he did not lose weight. And ultimately the Sikhs rose against him and he was dethroned and Sant Fateh Singh came on the scene.

Sant Fateh Singh demanded Punjabi Suba on the basis of Punjabi language'. Now he again gave it a linguistic turn. The question is what was the logic' behind it. The logic that he propounded

was just as all other provinces had been divided on the linguistic basis like Maharashtra for the Marathi-speaking people and Gujarat for the Gujarati-speaking people, similarly Punjabi Suba should be given to those who are Punjabi-speaking people. But herein lies a difference between Maharashtra and Punjab. In Maharashtra everybody spoke Marathi. When the cry of Maharashtra was raised, all the Marathi-speaking people rose to a man for the demand. But what happened in Punjab ? If you take the old Punjab, then you have got Haryana, Punjab and Himachal Pradesh. Seventy per cent, of the people there are Hindi-speaking. If you bifurcate them and take out Haryana and Himachal Pradesh, even then 45 per cent, are Hindi-speaking people in what is called the Punjabi Suba. The rest are Punjabi-speaking.

SHRI NARINDAR SlNGH BRAR : It was a bogus census.

PROF. SATYAVRATA SIDDHANTALANKAR : You may call it bogus but others call it the correct census. The question is that Punjab is not a uni-lingual State; it is a bilingual State. Therefore, the States Reorganisation Commission opined that Punjab should not be divided. It is very unfortunate that though there was no comparison between Maharashtra and Gujarat and Punjab, they have bifurcated Punjab and a Punjabi Suba has been carved out. This Punjabi-speaking State has no parallel wi'h other provinces and, therefore, I say that this division is not a linguistic division, it is a communal division. Therefore, as a Congressman I decry it. I decry it not because I belong to any other party but because I belong to the party of Mahatma Gandhi who taught us to work as one man, who gave us the lesson of secularism. If secularism has to be our concept, then the spirit of communalism has to be washed away. Unfortunately, we find that our Congress people., our Government is being cowed down by those people who issue threats of self-immolation. Today somebody gives some threat and they bow before it. Tomorrow Mr. Bhrpesh Gupta may take into his head and say that he would pour kerosene oil on himself and burn unless you make the country Moscow Red, Some other man may say that unless you make the country Peking Red, he would burn himself. Therefore, this threat of self-immolation has resulted in the partition of Punjab. And, therefore, I decry this attitude. I decry it because India can ultimately maintain its policy of secularism only if it is not cowed down by such threats. But what do we see today ? You see, lawaharlal Nehru gave the gospel of integration, but are we moving towards integration ? Integration does not mean partitioning of the country or balkanisation. If we go on along this line, ultimately the whole of India will be balkanised. Every part of the country will ask for its own people and its own Government. It is politicians' dominance, it is the politicians' ambitions which have partitioned Punjab. Therefore, these politicians should bear in mind that a day will come—as Diwan Chaman Lall said—when the people who have been instrumental for the partitioning of the country will regret the day when they accepted the partition. The Government will regret the day when they accepted this partition.

DR. ANUP SINGH : Madam, before I say anything about the Bill itself I would like to make a few observations. Firstly, I think anyone who has the larger interests of Punjab in mind or the interests of the integration of this country cannot be very enthusiastic or jubilant about the division of Punjab which, as my friend Diwan Chaman Lall said, has already suffered a great deal but this Bill has a history and there is not much time at my disposal to go into it and I deeply regret that some of the partisan attitudes have been injected into this debate at this very late stage. The truth of the matter is that the demand for a Punjabi Suba on a linguistic basis became irrefutable and unassailable once we had conceded that principle and I will come to the points that have been raised by my friends here.

Before Maharashtra was carved out, Pandit Jawaharlal Nehru said in one of the party meetings that there would be no more divisions on the basis *ot* language but due to the exigencies of the political circumstances, the Government had to give in and the demand for

[Dr. Anup Singh.] Punjabi Suba became accentuated and intensified. As for dubbing the Sikhs as communal, I think that is rather unfair because this has become a vicious circle. The Sikhs are as secular in their outlook as any other community but what is the true picture ? Master Tara Singh represents, at the moment, a very small fraction even of the Sikhs and to keep on quoting him 'This is what he wanted in 1947 or 1949' is irrelevant. We must take the recent past into consideration if we want to assess the situation properly. He has been repudiated by an overwhelming majority of the Sikhs. The demand is based on language but what has happened ? Unfortunately a section of the Hindus—I will not say Hindus but a section of the Hindus— whose proportion I do not claim to know, disowned their own language and said : 'Hindi is our mother-tongue' and on that basis the 1961 census report was prepared. I would like to remind my friend here that the late Prime Minister characterised that report as bogus and I think it was very unfortunate and very unwise on the part of the Home Minister to include the 1961 report as one of the terms of reference. If we had left it to the Commission itself, if language was going to be the criterion I would personally have given more time to the Commission and asked them to go into the whole problem properly, and to accurately and objectively assess the language ratio and then carve out a State. Anyhow the demand was accentuated first because Punjab was the only exception, it was made out to be an exception. Forget about the Hindus or the Sikhs. The demand was accentuated further because the Hindus disowned their own language. It is a vicious circle, or reaction. A new bitterness had been created because of the issue of Chandigarh. I am not going to go into the merits as to whom Chandigarh belongs. I will indicate my own preference a little later but some of the most prominent Hindus, nationalists, otherwise known as people with a secular outlook, joined hands and they say that Chandigarh should go to Haryana. It is a very interesting, rather amusing situation. You first disown your State, you are more interested in the Hindus in Haryana than in the people of Punjab. Let us not try to blame anyone as a communalist. I deeply regret that it has become a vicious circle. The problem is, to use that very happy phrase of Harold Laski: 'Where do we go from here ?' This Bill embodies or has tried to bring forward a reconciliation of the almost irreconcilable points of view. It has its defects but I think to say the Government always capitulates to force is not the proper appreciation of the situation. Every Government has ultimately to bow down before the collective will of the people which has been expressed in a democratic way. Take the history of any Government anywhere. To say that they yielded to this demand is wrong.

PROF. SATYAVRATA SIDDHANTALANKAR : Is it democracy ?

(Interruptions)

DR. ANUP SINGH : I am utterly against it. I will provide the kerosene for those who want to immolate themselves. We should give credit to the present Government for ultimately bringing forward a solution which is not ideal, and it cannot be because it seeks to reconcile certain differences. The Sikhs have not accepted it fully. Some of the Akalis in the other House had walked out. The extreme Jan Sangh people are not happy and they say that this division should not have taken place but the Government had to take into consideration the realities of the situation. I am against this division but it has been brought about not deliberately by the Government and I also repudiate the suggestion which I am told my friend Abdul Ghani made yesterday that the Government had a certain bias against any community. Some of the sections of people in Punjab may have bias one way or the other but so far as the Government is concerned they are above it. There may be some individuals who have their own preferences but to accuse the Government of any bias is wrons

شری عبدالغنی (پنجاب) : میں نے یہ نہیں کہا تھا ۔ میں نے یہ کہا تھا کہ مدھیہ پردیش پنجاب

سے جتنا بڑا ہے اور وہاں پر اپر
ھاؤس کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں
پنجابی صوبہ پر اپر ھاؤس کا بوجھا
کیوں ڈالا گیا ہے ۔ اس کے معنی
کیا یہ ھیں کہ آپ کا ان پر شک ہے
اور آپ چک لگانا چاھتے ھیں ؟

†[श्री अब्दुल गनी (पंजाब) : मैंने यह नहीं कहा था। मैंने यह कहा था कि मध्य प्रदेश पंजाब से जितना बड़ा है और वहां पर अपर हाउस की जरूरत नहीं है तो यहां पंजाबी सूबा पर अपर हाउस का बोझा क्यों डाला गया है। इसके मायने क्या यह हैं कि आपका इन पर शक है और आप चेक लगाना चाहते हैं ?]

DR. ANUP SINGH : This is a demand from the people of Punjab. If they jointly say that they do not want it because it is a very expensive luxury, I think the Government will be willing to take the initiative to abolish the Upper House.

I will make two or three suggestions. I take it that the Bill embodies the demands and aspirations of a cross-section of the people of Punjab, not of any particular party, not of the protagonists of one group or the other. The new leadership which will emerge both in Punjab and Haryana should rise above petty parochial and communal outlooks and implement this Bill in good faith and in co-operation. Secondly, I feel that the Bhakra Dam, its entire organisation with its remarkable past achievements should have stayed as the joint venture of the Punjab and Haryana Governments. It has been taken over by the Centre not for any ulterior motives, I take it, but perhaps they thought they will be able to run it better. I do not agree with this because the past record of the Central Government in many public undertakings is not too commendable. Because most of the Chief Engineers of the Bhakra organisation were subsequently made Chairmen of the CWPC and they have been managing some'hing to tune of Rs. 700 crores, to take it from them and give it to the Centre, I personally think, was not a very wise step and I do hope that the people of Haryana and Punjab will make a joint demand and I hope ihe Home Minister will be good enough to hand it back to the States where it belongs.

t[ ] Hindi transliteration.

SHRI GULZARILAL NANDA : Which State ?

DR. ANUP SINGH : Jointly. Let them make arrangements about the details but do not be over-anxious to take it over under you because you have too many other things to attend to.

SHRI B. D. KHOBARAGADE (Maharashtra) : Otherwise they will not have an opportunity to play their own politics.

DR. ANUP SINGH : I feel that Himachal Pradesh has a legitimate claim both in terms of the population and resources in the new area that has been added to it for full Statehood. I personally do not see any reason why it should be kept as a separate ca'egory.

And finally I would make an appeal to all the protagonists of the Punjabi Suba and all the antagonists of the Punjabi Suba to make the best use of the present Bill and make the necessary changes—if there are any desirable changes—by common agreement, and I understand from the informal discussion with the Home Minister that he will be only too happy if any suggestions are brought forward even now. Even after the passing of the Bill, if there are certain changes to be made, which are designed deliberately for the good of the Haryana and the Punjab people, some way will be found out to incorporate them even at this stage. Thank you.

KUMARI SHANTA VAS1SHT (Delhi): Madam Deputy Chairman, there has been a very strong expression of feelings on either side about the Punjabi Suba and the creation of ihe two States, and Members have shown a good deal of feeling about it. Just now our friend, I think Diwan Chaman Lall said, and also another Member said that they wanted an independent Punjab and that it was a very bad demand and it wns not for the good, but I think that we should have before us the background for such a demand. Instead of blaming the Akali Party for demanding an independent

[Khmari Shanta Vasisht.] Punjabi State, we should get our facts again, rebrushed and recollected that, when there was the demand for Pakistan, where a large number of even those who are to-day staunch opponents of the Punjabi Suba, like some of the vernacular papers of Punjab, some of ihe Hindu Mahasabha people, or the Jana Sangh people who came to be known as such later on, they were all anxious that the Akali demand should be for an independent Punjabi State so that the demand for Pakistan could be defeated by this counter demand. Nowadays we turn down the Akali Party when they want a free and independent State, and we forget that these very elements, who are so much against the Punjabi Suba now-a-days, were, at that time, anxious that, to defeat the demand for an independent Pakistan, they had to put a counter demand like that hoping that that particular thing could be utilised to defeat the demand for Pakistan, and I think all the time this demand is repeated infinitely, I should say, but this fact is always overlooked. So I would like to contradict my friend who said just now that they wanted a free State and so on and so forth. I had the privilege to be on the committee for Punjabi Suba, and 1 am one of those who feel that the Government's action has been extremely right in this respect. It is not that they have been p[r]essurized or that they have worked under pressure or that they wanted to create that State. But I feel sincerely that a very genuine demand of the Punjabi people, which was very longstanding, was denied for a very long time and has, at long last, been admitted recently now, in this year. This should have been done long ago. It was a just demand but it has been denied too long. Our friend, Diwan Chaman Lall, also said that all over Punjab, Punjabi is spoken. I personally feel that Haryana is such a backward area that till yesterday nobody knew what Haryana is, what those people are, what their ways are, so much so that some of us. when we *were* living in Punjab, in that part of Punjab which is now in Pakistan, where I spent a large part of my life, at least my children, they used to refer to us as Hindusthanis. We were in Punjab because we belonged to this part of India. All the same they always used to say that they were Punjabis and we were Hindusthanis. There were people from this Haryana area also in the district from where the Home Minister hails, namely, Multan. There, everywhere we were all referred to as Hindu-sthani people by people from Punjab mostly, and they used to even look down upon coming to Delhi, because that was not their place. Lahore was the place where everybody liked to go, and people were very proud of Lahore, and very much attached to Lahore also. It was to Lahore they looked up to, and Delhi to them was almost a second grade place. And nobody thought of Delhi before partition. That was the sentiment and the feeling of the people in Punjab at that time. Therefore, everybody, even the Government of India, I must confess, has been very very neglectful and ignorant about the existence of Haryana, the characteristics of the people there, their way of life, their entire existence, I should say. They have not known as to who these people are, what they lived on, what their culture was, what their traditions were, what are their ways. They did not know anything about them, but gradually they have to come to know them. Now they feel that such thing as Haryana exists. When the Akali demand came again they began to express their fears greater and greater and they had a lot of backing of the people at large in their aspiration to have a State of their own. I personally feel that no one minority community should feel neglected or aggrieved in the Union of India. Every minority community must be given the assurance that they shall be dealt with fairly and that the major community wants to give them all kinds of help, all sense of security and sense of expression also. There are those of our friends who feel that this Suba should not have been created. I can appreciate their feelings and also their anxiety. I can appreciate all that, but I genuinely believe that this is not disintegration of the country at all. I genuinely believe that this is not a division of Punjab either, because we do not visualise, we do not want, we do not hope that there will be any migration of population or that the people shall be separated like

that. If they do, I shall be very sorry; I would not like it at all. But I do feel that when Maharashtra was created, I think, a certain justice was done to the people of Maharashtra, and we feel that when a people feel that they are going to be neglected, whether they be of Maharashtra or Gujarat or any other area if they feel that they cannot get justice from those parts which are well off—the economic factors also are very important; when one section is very rich, whe her it is Gujarati or anybody else, and the Maharashtrians are very poor, mostly they are the working class people or peasantry,—they are bound to demand their own expression and their own way and their own opportunity to run their affairs in their own way. And to deny them that opportunity would be very wrong indeed. So also if the Andhra people wanted to have their own entity and expression, it was only fair that we gave them that. Therefore I do not at all feel that this is going to cause any disintegration in the country. If the Sindhis want their own way of life, their own entity, their own culture, their own ways, they have a right to it, and they should have it. Only then they can go beyond their own personalities, beyond their own selves and mix with other people and become a part of, or integrate with, other parts of the country. So also if tbe Maharashtrians want their own way of life, they have a right to it. *So* also the Andhras if they want their own way of life. And when the Akali demand came to be considered, I think the sense of neglect was equally strong in the people of Haryana also, the feeling that they were very much neglected, that there was no education there, that there were no industries there, that there were no development programmes there, that their social services were neglected, that the services in Punjab were predominantly manned by people who are not from Haryana, bv people who do not even understand about the Haryana people. Therefore I feel that *to* have more States is not eo-ing to create any kind of disintegration. As a matter of fact, when people are allowed to have their own expression, they are bound to integrate better with other States and other people. They are going to appreciate other people a little more because they are allowed to have their own expression. I may give an example here, the example of the United States of America. They had at one time 48 States. Then it rose to 50 States. Now I think it is 52.

SHRI SYED AHMAD (Madhya Pradesh): They are 51 States now.

KUMARI SHANTA VASISHT : They are probably almost 52. Anyway they will be 52 without any delay. The point is that every now and then a new State is added up in the United States of America. They are going on creating or adding new States without any dis-integration at all. It is the point of view of the people there, their thinking, their education, their feeling of nationalism, their interest in their own States and their relations with other people in other States, that makes the whole country. It is not small States, it is not a question whether they will make it or will not make it.

شری عبدالغنی : چھوٹی بہن جی—ہماری آبادی بہت زیادہ ہے ہمیں ۱۰۱ بنانی چاہئے -

†[श्री अब्दुल गनी : छोटी बहन जी, हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। हमें 101 बनानी चाहियें।]

कुमारी शांता वशिष्ठ : मैं आपसे बिलकुल एग्री करती हूं कि 101 होने चाहिएं, खासकर यू०पी० और बिहार के कई हिस्से होने चाहियें।

U.P. and Bihar are so big and so dominating in many ways., and so backward also—Bihar also—that they should be made into so many States, so that the communication is better, the administration is better, the supervision is better, the administration improves, there is greater contact between the . . .

SHRI SYED AHMAD: Their temperament would also become better.

KUMARI SHANTA VASISHT: Their temperament would also become better. So I feel that some of these bigger States should be made into smaller States, so that their administrations are better off

t[ ] Hindi transliteration.

[Kumari Shanta Vasisht.] and viable, they are more efficient, they are more able to look after their affairs in a better way. But in bigger States, sometimes the administration remains at the total mercy of the District Collector and, therefore, these States cannot really have all the advantages which go with smaller States. In a small area the administration can be very very intense and better and more efficient compared to a bigger State. Now, I shall come to some other points.

THE DEPUTY CHAIRMAN : You will have to be very brief.

KUMARI SHANTA VASISHT : I feel that in this Bill some of the assets and liabilities have still to be looked into properly. For example, the way all the Ministers from various States hover round Delhi, they have to talk to the Central leaders all the time. Half their time is spent in meeting the Central leaders. I think the Rest House should be divided equally so that people from both the areas can make use of it. I think it is a very unfortunate development in our country that every State leader will have to hover round Delhi. They have to come here all the time and they have no time or capacity to do anything including looking after the affairs of their own States. The Central Government should discourage as far as possible any desire on the part of the States to always run to the Central Government. It is not a good thing if always they were to be tied to the apron strings of the Cential Government expecting some help from them.

Secondly, many of our Central leaders go and interfere with the States. It is an extremely bad thing for democracy and for the proper working of the States. I am very sorry to say that so many Ministers including our State Minister from Delhi have been holding meetings, have been giving material to the Press and so on. They have been doing a lot of work against the units or the States. That is what is being done in various States including my own Territory. At this rate the ruling party or the Congress organisation cannot function effectively or properly; nor can it work nicely if the Central Government continues to interfere, continues to patronise, continues to keep them under their sway. It is a very wrong thing. It creates innumerable difficulties for everybody. We have seen what is happening in Orissa. We have seen what has happened in a perfect State like Maharashtra where the Government is veiy good, where the administration is very good and there was honesty and integrity and so on. There was some interference from the Central Minister and the whole thing was made to collapse at least for a few hours. Some Ministers resigned and then took back their resignations and a patch-up takes place. This sort of thing brings down the dignity and the prestige of the ruling party. The Government had a good name there and it was enjoying a good reputation in the matter of Government there in Maharashtra and I think that ought not to have been interfered with by any leader of the Central Government. It is very unfair; it is very wrong and I think the ordinary people feel very sore about it that even those State Governments which are doing a good job are being interfered with by the Central Government. Such interference by the Central Government is extremely unjustified. In Delhi also we have been the sufferers and victims of such interference with the dissidents having meetings and other things. They have Ministers in the Centre but they are dissidents in the Territory and by their actions they ruin the Congress; they damage it. So the whole thing is very wrong and unjustified on all grounds, whether on grounds of administration, or on grounds of political astuteness or on grounds of expediency and it is wrong also from the point of view of discipline in the Congress. If the Prime Minister was so keen that there should be discipline in the Congress organisation she should have removed this Minister from the Ministry and seen to it that he does not create difficulties for the Congress of Delhi.

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh) : Which Minister ?

KUMARI SHANTA VASISHT: State Minister from Delhi in the Central Government.

SHRI ARJUN ARORA : What is his portfolio ?

KUMARI SHANTA VASISHT : Housing. It is a misfortune; such interferences ought not to be allowed. This is very bad for the discipline of the party. They should not be doing this. They should have asked him not to indulge in these activities. I conveyed . . .

THE DEPUTY MINISTER IN THF. MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. S. NASKAR): He represents Delhi, is it not ?

KUMARI SHANTA VASISHT : It was very unfortunate he was imposed upon Delhi and he is our representative. I am very sorry.

SHRI AWADHESHWAR PRASAD SINHA (Bihar): He is a duly elected Member from Delhi. Anyway, all this has nothing to do with the Bill.

شری عبدالغنی : یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس لئے اس پر اس بہن کو اور کہنے دیں ۔

†[श्री अब्दुल गनी : यह बड़ा इम्पार्टेंट प्वाइंट है इसलिये इस पर इस बहन को और कहने दें ।]

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please wind up. It is time.

KUMARI SHANTA VASISHT : I do see why you are standing up in his defence when I know privately how you feel about him and how you have criticised him. What I am stressing is that the Ministers ought not to be allowed to interfere in the affairs of the States. So also Haryana needs all the care and attention. They should be allowed to have their own leadership in the area and efforis should be made to build up good traditions so that the State will not fall into the same . . .

SHRI GULZARILAL NANDA: Whatever there may be privately, views and sources of discontent arising from any action of omission or commission of a colleague, at any rate these are not things which can be dealt with here, particularly in this context.

tt] Hindi transliteration.

KUMARI SHANTA VASISHT : They are not very far off. These are some of the problems of Central interference. Interference by the Central Ministers is there in almost all the States. Even in States like Maharashtra where . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN : You keep to Haryana.

KUMARI SHANTA VASISHT: There-fore what I am trying to say is this. They should not interfere with these States. They should not try to put their puppets there because puppets won't work. They cannot administer any State. If puppets are put up the whole thing collapses. Therefore they should try to set up good traditions and good standards in every possible way. I would also suggest that the people in the services should be drawn from other States like Madras or Andhra who can look upon this matter objectively and impartially. If only the people of the neighbouring States are taken into the services in these States, I think it would not work. This is a big emotional problem and about this creation of a Punjabi Suba emotions are so deeply involved that these people wfll not ordinarily do justice. They will be either very antagonistic or very pro in their feelings against each other. Only those people who are non-attached and non-aligned in this particular matter, whose emotions are not involved in this, will be able to administer the areas justly.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now you must wind up.

KUMARI SHANTA VASISHT: Madam, I wish the States well and I hope they will find their own expression and they will grow from prosperity to prosperity.

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया (राजस्थान) : उप-सभापति जी, पंजाब के विभाजन के इस बिल पर इस पक्ष के और उस पक्ष के कितने ही भाषण हमने सुने । कुछ ऐसा लगता है कि जो कुछ कांग्रेस ने और इस सरकार ने इस सदन में और इस सदन के बाहर पंजाब के बंटवारे के बारे में जो कदम उठाया उस सबका क्रेडिट हमारे विरोधी पक्ष के भाई लेने की कोशिश कर

[श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया]

रहे हैं। एक तरफ तो जनसंघ वाले भाई अपने पक्ष की बात कुछ कहते हैं और ऐसा महसूस कराने की कोशिश करते हैं कि शायद हरियाना के लोगों को उन्होंने बचा लिया, पंजाब के हिन्दुओं की रक्षा उन्होंने की। दूसरी तरफ हमारे अकाली भाई—इत्तफाक से उनमें से एक नहीं हैं—इस बात की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं इस सदन के जरिए पंजाब के रहने वाले लोगों को और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों को यह दिखाने की कि पंजाब का बंटवारा उन्होंने कराया भाषा के आधार पर और सिखों के रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या वे पुराना इतिहास भूल गए, क्या कांग्रेस का 1926 का वह प्रस्ताव भूल गए जब कि अकाली पार्टी का निर्माण ही नहीं हुआ था? उस समय कांग्रेस ने यह फैसला किया था कि देश के अन्दर सूबों का निर्माण हम भाषा के आधार पर करेंगे। चाहे मैं उस बिल से इत्तफाक नहीं रखता लेकिन निश्चय रूप से कांग्रेस को और कांग्रेस की इस सरकार को और खास तौर पर वर्तमान गृह मंत्री को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि चाहे देर आए, दुरुस्त आए, उन्होंने पंजाब का विभाजन भाषा के आधार पर आखिर किया।

हमारे प्रतिपक्ष के भाईयों ने यह लांछन लगाया कि पंजाब का भाषावार प्रान्त बनाने में सरकार ने बड़ी देर लगाई, लेकिन वे यह क्यों भूल जाते हैं कि पंजाब एक बार्डर स्टेट है। आज भी है, रहा था और आगे भी रहेगा और वहां पर हमारे सीमा के झगड़े पाकिस्तान के साथ बराबर चलते रहे हैं। उन सब को देखते हुए और दूसरी तरफ हिन्दुओं और सिखों के झगड़े को देखते हुये, साम्प्रदायिकता का जो विष वहां फैला चाहे वह अकाली पार्टी की ओर से हो या दूसरे विरोधी दलों की ओर से हो उसकी देखते हुये न यह कांग्रेस के लिये सम्भव था न यह सरकार के लिये सम्भव था न हमारे प्रधान मंत्री के लिये, न वर्तमान गृह मंत्री के लिये सम्भव था कि उस मौके पर जब कि आग जल रही थी, देश खतरे से निकल रहा था, उस वक्त पर पंजाब का विभाजन कर दें। इस वजह से इन सब बातों का ख़याल करते हुये कांग्रेस अध्यक्ष ने, गृह मंत्री ने और प्रधान मंत्री ने इस बात को उचित समझा कि अब उचित मौका आया है जब कि भाषा के आधार पर पंजाब को बांटा जा सकता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता को गुमराह न करें। मैं जानता हूं कि चुनाव नजदीक आ रहा है, वोट उनको लेना है, पंजाबी सूबे के अकाली भाइयों को वोट लेना है और दूसरों को वोट लेना है, लेकिन जनता गुमराह नहीं होने वाली है, जनता के सामने वह सारा पुराना इतिहास है कि पंजाब में क्या किस तरह से चल रहा था, किस तरह से भाषा के आधार पर, साम्प्रदायिकता के आधार पर झगड़ा हो रहा था, वह सब जनता जानती है इसलिये जनता गुमराह नहीं होने वाली है। इसलिये उन भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ हो गया उसको मान लो, जिस खुशी के साथ इसको मान कर चले थे उसी खुशी के साथ माने। मैंने कल सदन में सुना, उन भाइयों ने कहा कि आज कुछ अकाली भाई भी इस बात को महसूस करते हैं कि पंजाब का विभाजन गलत हो गया। आज उन्होंने इसको महसूस किया और आगे जा कर गौर करेंगे और देखेंगे तो और महसूस करेंगे क्योंकि एक तरफ तो जो सारे जंगलात थे, फारेस्ट्स थे, जो खनिज पदार्थ थे वह हिमाचल को चले गये और दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रीज थीं वह हरियाणा में आ गई और इस बात को भी वह क्यों भूल जाते हैं, पंजाब के रहने वाले भाई भूल जाते हैं, चाहे वह सिख हों या नान-सिख हों, कि पंजाब की सेवाओं में, सर्विसेज में, सरकारी कर्मचारियों की जितनी तादाद थी जितनी अनडिवाइडेड पंजाब में थी, उसमें दूसरे हिस्से के लोगों का बहुत कम हिस्सा था, बहुत कम परसेंटेज था, सारे का सारा जो फायदा था वह जो आज पंजाब कहलायेगा उसके लोग उठाते थे। तो आगे चल कर इस बात को आप और ज्यादा महसूस करेंगे।

इस बात को मैं अभी नहीं कहना चाहता हूं लेकिन भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आया कि उनमें सद्बुद्धि फिर आये, चाहे वह मास्टर तारासिंह हों, चाहे वह संत फतेहसिंह हों या उनके पीछे चलने वाले फालोअर हों, और मैं समझता हूं कि उनमें बुद्धि जरूर आयेगी कि जिस तरह से उन्होंने साम्प्रदायिकता के आधार पर, भाषा की आड़ ले कर, पंजाब के बंटवारे की मांग की थी वह ठीक नहीं थी और सद्बुद्धि आने पर कहेंगे कि पंजाब का पुनर्गठन होना चाहिये, पंजाब बंटा हुआ नहीं होना चाहिये, पंजाब का फिर से गठन होना चाहिये।

श्री बी० डी० खोबरागड़े : यह तो हिन्दू लोगों के बर्ताव पर रहेगा।

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया : बर्ताव तो हमारा बहुत ही अच्छा है, आप देख रहे हैं। जरा सुनिये।

नन्दा जी को कुछ कहा गया कि जो कर रहे हैं ठीक नहीं, मैं नन्दा जी की इसमें कोई गल्ती नहीं समझता, वह जो कुछ कर रहे हैं वह खूब सोच समझ कर कर रहे हैं। अब सोचना समझना तो आपको है। इसके पहले कि मैं कुछ और बात कहूं मैं अपने विपक्ष के भाइयों से और इस पक्ष के भाईयों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह व्यक्तिगत रूप से गृह मंत्री के ऊपर अटैक करने की जो उन्होंने बात की और जो यह बताने की कोशिश की कि उनकी ढीली नीति के कारण बंटवारे में देरी लगी। देश में जो झगड़े होते हैं उसका कारण नन्दा जी की ढीली नीति बताया जाता है, नन्दा जी को वह दोषी बताते हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वह यह क्यों भूल जाते हैं कि नन्दा जी ही हैं जिन्होंने काश्मीर की समस्या का समाधान इस अच्छे ढंग से किया कि दूसरी जगह बात फैलने भी नहीं पाई, वह क्यों भूल जाते हैं कि कलकत्ते के साम्प्रदायिक झगड़े में हमारे नन्दा जी ही अपनी पुलिस को ले कर गली गली और सड़क सड़क में घूमे थे और वहां शान्ति का वातावरण पैदा किया था, वह क्यों भूल जाते हैं कि रूरकेला के अन्दर जब लेबर ट्रबल हुई तो नन्दा जी ने ही दिलचस्पी ले कर वहां उसको शान्त किया। मैं उदाहरण के तौर पर इन बातों को कह रहा हूं लेकिन हम आये-दिन रोजमर्रा देखते हैं कि कहीं भी झगड़ा हो उनको कह देते हैं। अभी कुछ दिन की बात है कि आसाम में झगड़ा पैदा हुआ, वहां नन्दा जी के जाने की जरूरत तो नहीं पड़ी लेकिन मालूम हुआ कि गृह मंत्री स्वयं तशरीफ ला रहे हैं तो वहां शान्ति हो गई। तो मैं समझता हूं कि वह सोचते समझते हैं, यह कोई ढिलाई की नीति नहीं है। उच्च पद पर रहने वाले ऐसे व्यक्तियों को बहुत देखना पड़ता है, सब बातों को सोचना पड़ता है, ख़याल करना पड़ता है, किसी बात का रिएक्शन क्या होगा उसको देखना पड़ता है। तो केवल गाली देने और आलोचना करने से ही वह बातें नहीं हो जातीं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आलोचना करते समय इस पर भी ध्यान दिया जाय। खुदा करे कि कभी ऐसा मौका आये, खुदा अगर उनको मौका दे तो क्या वह भी इस तरह से नहीं करेंगे, क्या वह कोई बात सोचे समझेंगे नहीं या जल्दी में जो मर्जी होगी उसी को करते रहेंगे।

उपसभापति जी, ये बातें तो मैंने रेफरेंस के तौर पर, इंट्रोडक्शन के तौर पर कहीं लेकिन जो दो एक खास बातें निवेदन करनी हैं वह यह है कि जिस तरह से पंजाब का विभाजन हो रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं। पंजाब का विभाजन आज इतने साल के बाद क्यों करने की आवश्यकता पड़ी, भाषा के आधार पर करना था तो हम पहले कर देते। मैं तो इस बात को मानता हूं, इस धारणा को ले कर चलता हूं कि पंजाब के अन्दर भाषा के कोई झगड़े थे ही नहीं और अगर भाषा का कोई झगड़ा था तो उसे आप सुलझा सकते थे। यह झगड़ा तो साम्प्रदायिक था, साम्प्रदायिक बन गया, इस बात को हमारे अकाली भाई या दूसरे मेम्बर महसूस करें या न करें, मंजूर करें या न करें, कहें न कहें

[श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया]

लेकिन यह बात निश्चित है कि उनके दिमाग में कम्युनल सेपरेशन की टेंडेंसी थी और जो कुछ उनके दिमाग के पीछे काम कर रहा था उसी के कारण इस भावना को और बढ़ावा दिया गया। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह की मांग को मंजूर करते जाते रहेंगे तो देश के न मालूम कितने टुकड़े हो जायेंगे। मैं देखता हूं कि बिहार में मगधी और भोजपुर का झगड़ा है, उत्तर प्रदेश में पूर्व और पश्चिम के सामंजस्य की बात है, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तथा भिन्न भिन्न प्रान्तों में इसी तरह की बात है, अब भी कन्नड़ का झगड़ा चल रहा है। तो इस तरह से देश के अन्दर विभिन्न भाषाओं को ले कर झगड़ा चल रहा है। अगर हम उनको मंजूर करते रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के अन्दर फिर पांच सौ रियासतें कायम करनी पड़ेंगी। यह न देश की दृष्टि से, न भाषा की दृष्टि से और न शासन की व्यवस्था की दृष्टि से उचित होगा, इससे हमारी राष्ट्रीयता को आघात, पहुंचेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो कुछ हो गया वह हो गया, जितना हो गया वह ठीक है, आगे अब ऐसा कोई सिद्धांत नहीं रहना चाहिये, इस तरह की कोई भी मांग सरकार के सामने आवे तो उसको ठुकराना चाहिये और विरोधी पार्टियों से और अपनी इस पार्टी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अब भाषा के झगड़े को आगे नहीं बढ़ाना चाहिये, अगर भाषा का झगड़ा चलता रहा तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि पुनः आपके सामने एक राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त करने की मांग आयेगी। पुनर्गठन आयोग में बहुत स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में कहा है, उसको मैं पढ़ कर सुनाना चाहता था, किन्तु योंही कहूंगा कि उसमें कहा गया है कि देश के सूबों के बटवारे का ही आधार भाषा नहीं हो सकती बल्कि शासकीय ईकाई, आर्थिक उन्नति और आने-जाने जो साधन आदि हैं उनको भी मद्देनजर रखना पड़ता है, उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन बातों को ध्यान में रखा जाये और केवल भाषा को ही ध्यान में नहीं रखा जाय और अगर भाषा को ही ध्यान में रखा जायगा तो जैसा कि मैंने कहा है देश के अनेक टुकड़े हो जायेंगे और वह देश के लिये हितकारी नहीं है।

अब एक बात में निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कुछ भाइयों ने यहां पर इस बात को खास तौर पर कहा—मुझे उनका नाम ठीक याद नहीं रहा, सरदार डुग्गल साहब ने कहा था—कि जो नया पंजाब होगा उसका नाम पंजाब न हो कर पंजाबी सूबा होना चाहिये। पंजाब न हो कर पंजाबी सूबा उसका नाम हो तो ऐसा उन्होंने क्यों आवश्यक समझा। राजस्थान एक स्टेट है केरल और मद्रास के स्टेट हैं, सूबे हैं, वे सब भी तो सूबे हैं तो क्या उनका नाम भी दूसरा कर दिया जाय। तो जो उन्होंने कहा कि उसका नाम पंजाबी सूबा रख दिया जाय उससे मेरे मन में यह भावना आती है कि उसके अन्दर भी कोई भावना काम कर रही है और उस भावना को इसके जरिये से यहां व्यक्त करना है। मेरा निवेदन है कि इस भावना को आप पहिचान लें। भावना यह है कि आपका नुकसान हुआ है इसको आप महसूस करने लगे हैं, आगे और ज्यादा नुकसान होने वाला है, तो इस तरह की मांग पर हमें कोई ध्यान नहीं देना है। सभी तो सूबे हैं। उर्दू में उनको सूबा कहते हैं, हिन्दी में प्रान्त कहते हैं और अंग्रेजी में प्राविंस कहते हैं। उनको या किसी साहब को इस बात को नहीं कहना चाहिये था।

(*Time bell rings.*)

महोदया, यह बहुत इम्पार्टेंट मसला है। मुझे कई बातें कहनी है। मैं सभा में आज दूसरी बार बोल रहा हूं।

(*Time bell rings*)

THE DEPUTY CHAIRMAN : You halve to finish in two minutes more. You must co-operate now. We have to finish two Bills.

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया : अब मैं उस बिल के कुछ मुद्दों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। गृह मंत्री ने, उनके मंत्रालय ने, या इस पूरी सरकार ने उचित ही किया कि चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी रखा लेकिन इस बात का कोई भाई विरोध करते हैं और इस बात की धमकी देते हैं, आज भी देते चले जा रहे हैं, कि अगर चंडीगढ़ को पंजाब को नहीं दिया गया तो वह आन्दोलन करेंगे और आन्दोलन को तेजी से करेंगे और शायद फिर सरकार को झुका देंगे। उन लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार धमकियों से नहीं डरती सरकार कुछ उसूलों से डरती है। हमने कुछ सिद्धांत तय किये हैं, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमने पंजाब का बटवारा किया है। अगर उनको यह भ्रम हो कि उनकी धमकियों से, उनके आंदोलन से, उनके व्रत से, इस सरकार ने पंजाब का विभाजन स्वीकार कर लिया तो उसको वे दिमाग से निकाल दें क्यों कि आपको याद हो कि गृह मंत्री जी ने व्रत करने का मौका संत फतेहसिंह को नहीं दिया था। संत फतेह सिंह ने केवल व्रत करने की बात कही थी। गृह मंत्री जी ने, जैसे ही पाकिस्तान के साथ हमारे झगड़े का निपटारा हुआ, जिस दिन इस बात की घोषणा हुई कि आज वह व्रत बंद हो गया, उसके दूसरे दिन गृह मंत्री ने घोषणा की कि हम पंजाब के भाषा के आधार पर बंटवारे की बात सोचेंगे और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया और आज हम इस पर विचार कर रहे हैं। इसलिये अगर उनको भ्रम है कि हमारी सरकार या पार्टी उनके डर से, उनकी धमकियों से कोई बात मान लेती है तो इस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिये और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को दिमाग से साफ करने के लिये जरूरी हो जाता है कि आगे जो भी कार्यवाही इस तरह की लोग करें, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये, लेकिन यह निवेदन मैं जरूर करना चाहूंगा कि चंडीगढ़ में बहुमत हिन्दी वालों का बनने वाला है और अच्छा होता उसको आप हरियाना को दे देते लेकिन चंडीगढ़ को आपने संयुक्त राजधानी जो रखा है उसका भी मैं स्वागत करता हूं। चंडीगढ़ को दोनों की राजधानी बनाये रखने से और वहां पर दोनों का हाईकोर्ट होने से दोनों भाइयों में वैमनस्य नहीं फैलेगा और कटुता नहीं होगी और मेल-जोल की भावना आयगी, मिल जुल कर बैठेंगे और सोचेंगे।

इसके साथ साथ निवेदन करना चाहता हूं कि क्या ही अच्छा होता अगर दोनों के लिये राज्यपाल भी एक ही होता क्योंकि हाईकोर्ट एक है, राजधानी एक है। तो क्या जरूरत है आप अलग-अलग राज्यपाल बनायें। मेरा निवेदन है कि आप भी सोच सकते हैं कि अगर दोनों के लिये एक राज्यपाल बना सकते हैं तो बनाइये।

इसके साथ साथ एक बात हिमाचल प्रदेश के और दिल्ली के हाईकोर्ट को एक साथ जोड़ने की आई है। अच्छा तो यह होता कि चूंकि चंडीगढ़ में जो हाईकोर्ट बनेगा वह दोनों प्रान्तों के लिये होगा, पहले तीन प्रान्त आते थे, तो हिमाचल प्रदेश के दूसरे हिस्से के भाई इतनी दूर तक दिल्ली आयेंगे हाईकोर्ट में तो हाईकोर्ट के मामले में वह भी चंडीगढ़ के साथ जोड़ दिया जाता तो अच्छा होता।

THE DEPUTY CHAIRMAN: That will do, Mr. Pahadia.

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया : मैं खत्म करता हूं। इसके साथ ही साथ उपसभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सदन की पेटीशन्स कमेटी कांडी तथा ऊना तहसील के निवासियों के हस्ताक्षर से जो पेटीशन्स भेजा गया है उस पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। मेरा आपके जरिये गृह मंत्री जी से निवेदन है कि इन पेटीशन्स पर विचार करना चाहिये। इस सदन के दो माननीय सदस्यों ने वहां की जनता के हजारों हस्ताक्षरों के साथ दो अलग अलग पेटीशन पेश किये हैं। अब पेटीशन्स कमेटी ने जो अपना विचार प्रकट किया है उसको आपके पास फैसले के लिये

[श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया]

भेज दिया है। इस सदन के हर माननीय सदस्य को महसूस करना चाहिये कि यह वहां की जनता की जेनुइन मांग है और उसको ठुकराया नहीं जाना चाहिये। यह कोई भावना में बहकर या जल्दीबाजी में काम नहीं किया गया है और उनकी मांग उचित है और उसके बारे में जल्द से जल्द कुछ करना चाहिये।

उपसभापति जी, एक और बात कह कर समाप्त कर देना चाहूंगा। बिल की धारा 78, 79 और 80, मेरे अपने प्रान्त से ताल्लुक रखती हैं। आपने भाकड़ा नांगल और राजस्थान कैनाल को पानी देने के लिये रावी का जिक्र बिल्कुल नहीं किया है, सतलुज और व्यास का जिक्र इसमें किया गया है। इससे आगे चल कर झगड़े हो सकते हैं। वाटर सप्लाई कन्ट्रोल बोर्ड पंजाब सरकार का है, वह तो केन्द्र से और राजस्थान सरकार से पैसा तो ले लेंगे और वे हमारी पानी और बिजली की सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें रावी का पानी का जिक्र नहीं है इसलिय हो सकता है आगे चलकर वह रावी का पानी राजस्थान या भाकड़ा कैनाल को नहीं देंगे। इसलिये अच्छा हो यदि रावी का जिक्र इसमे किया जाय और रावी का पानी राजस्थान की नहर में जायेगा, अगर इस बात का जिक्र यहां नहीं किया गया तो कल को मुश्किल पैदा हो सकती है।

अंत में एक और बात मैं कह देना चाहता हूं, कि पंजाब के बाहर की जो प्रापर्टीज हैं जैसे डाक बंगले, रेस्ट हाउसेज, इत्यादि, उनका जिक्र इसमें नहीं किया गया है कि उनका कुछ हिस्सा हरियाना को भी मिलेगा। इसलिए जब पंजाब का बंटवारा हो रहा है तो सारी सर्विसेज की अन्य जायदादें जो पंजाब के बाहर पंजाब की जायदाद हैं, चाहे दिल्ली में हो, शिमला में हो, कहीं हो, उसका कुछ हिस्सा हरियाने वालों को भी मिलने लगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री सी० एल० वर्मा (हिमाचल प्रदेश) : उपसभापति महोदया, इस बिल पर बोलते हुए बहुत से मेम्बरान ने हिस्सा लिया और मुझे कोई भी मेम्बर आफ दि हाऊस नहीं मिला जिसने कि हिमाचल के वास्ते यह मांग नहीं की कि उसे स्टेटहुड दिया जाय। मैं बहुत अदब से साथ माननीय होम मिनिस्टर साहब से यह दरख्वास्त करूंगा कि उनके रास्ते में क्या कठिनाइयां हैं जिसकी वजह से वे हमको स्टेटहुड नहीं दे सकते। एक चीज में मैं अपने साथ ज्यादती करूंगा अगर मैं सदन के सामने यह न रखूं कि जितने भी पहाड़ के लोग हैं, चाहे वे यू० पी० के हों, चाहे वे बंगाल के हों, चाहे वे आसाम के हों, चाहे वे हिमाचल प्रदेश के हों, उनके दिमाग में एक बात यह पहले से लेकर जरूर है, खास कर हिमाचल वालों के, कि जो प्लेन्स के आदमी हैं वे हमारे साथ इन्साफ नहीं करते हैं। इस सिलसिले में जब कि 1953 में स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन हुआ था, लोगों ने रेप्रेजेन्टशन दिये थे और मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस नोट की तरफ दिलाता हूं जो कि श्री फजल अली साहब ने स्टेट्स रिआरगेनाइजेशन रिपोर्ट में दिया है उसकी मैं दो तीन लाइनें आपकी जानकारी के लिये पढ़े देता हूं :

"What seems to account for the great anxiety of the peoples of Himachal Pradesh not to be associated with the Punjab is their deep-seated distrust of the men of the plains. It is just possible that this feeling of distrust is to some extent a legacy of the pre-independence princely regime which employed a large number of retired officers from the Punjab who for some reason or other were not able to win the confidence of the local people. It may also be partly due to the advantage being taken in the past of the ignorance and poverty of the people of Himachal Pradesh by persons from outside the State."

इस सिलसिले में उस वक्त भी यह बात आई थी कि जहां तक पहाड़ के लोगों का सवाल है,

चाहे आप मीजोज को ले लें, उनके अंदर एक यह भावना है कि उनके साथ इन्साफ नहीं हो रहा है। हम यह नहीं समझ सके कि हरियाना वालों को स्टेट मिल गई, पंजाब तो खैर स्टेट थी ही, मगर जो लोग कांगड़ा के, दूसरे इलाके के, शिमला है, कुलू है, लाहौल और स्पिति है, हिमाचल प्रदेश के साथ एक यूनियन टेरीटरी में उनके साथ इन्साफ क्यों नहीं किया गया? आपको मालूम ही है कि कांगड़ा के लोगों ने जो अभी हिन्दुस्तान पाकिस्तान के दर्मियान लड़ाई हुई थी उस सिलसिले में सबसे ज्यादा शहीद जो हुए वे कांगड़ा के लोग हुए हैं सारे हिन्दुस्तान में महज पंजाब में नहीं। मगर आज एक स्टेट से निकाल कर यह पहाड़ी इलाके में दिया जा रहा है तो उनको एक स्टेटहुड नहीं दिया जाता है।

बाकी जहां तक सवाल फाइनेन्सज का है, जब कांस्टीट्यूशन अमेंडिंग बिल आया था उस रोज मैंने अर्ज कर दिया था कि बहुतसी स्टेट्स हैं जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से ग्रान्ट इन् एड लेती हैं, अगर ग्रान्ट लेना इतना जुर्म है तो मैं क्या इतना समझ सकता हूं कि क्या वे स्टेट भी कल को यूनियन टेरीटरीज बनने वाली हैं क्योंकि वे अगर स्टेट रह सकती हैं तो हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं स्टेट हो सकता है। अगर यह कहा जाय कि वहां पर कोई इन्टेलिजेन्शिया नहीं है तो मैं आपसे मोअद्बाना अर्ज करूंगा कि क्या कांगड़ा ने हिन्दुस्तान को चीफ जस्टिस आफ इंडिया नहीं दिया था? क्या वह कांगड़ा नहीं है जिसने मेजर जनरल और मिलिटरी के बड़े बड़े आफिसरान दिये हैं? हम तो हिमाचल प्रदेश के साथ यूनियन टेरीटरी में थे ही मगर आज कांगड़ा के पहाड़ी इलाके के लोगों को भी यूनियन टेरीटरी में रख रहे हैं। इसलिये मेरी फिर मोअद्बाना अर्ज है कि इस चीज को माननीय मंत्री जी जरा ध्यान से सोचें।

इसके अलावा एक चीज यह भी कह देना चाहता हूं कि यूनियन टेरीटरी का शब्द हमने यू० एस० ए० के कांस्टीट्यूशन से लिया है मगर यू० एस० ए० के लोग पहले 10, 15 स्टेटों में थे जो अब 51 या 52 स्टेटें हो गई हैं। उसके अंदर भी कोई तरीका रखा गया है कि कितने अरसे के बाद, किन हालत के बाद एक यूनियन टेरीटरी एक स्टेट बन जायेगी। या तो यह है कि ये यूनियन टेरीटरिज हमेशा के लिये होम मिनिस्ट्री की जागीर रहेंगी। यह जहां तक मैं समझता हूं यूनियन टेरीटरीज एक्ट 1963 जो है उसके अंदर धारा 22, 23 और 27 को देखें तो आपको मालूम हो जायेगा आप कोई बिल नहीं पास कर सकते, आप किसी बिल का अमेन्डमेन्ट नहीं कर सकते, जब तक वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट से पास न हो जाय, आप कोई बजट पेश नहीं कर सकते जब तक वह सेन्ट्रल गवर्नमेंट से न आ जाय। बजट चूंकि नई दिल्ली में पास होता है वह जून जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में आता है और सितम्बर अक्तूबर तक हर एक ब्रान्च में पहुंचता है। नतीजा यह होता है कि मार्च के महीने में दिन रात हमारे यहां इधर उधर करके, नीचे ऊपर करके, कहीं यहां से कोटेशन ली वहां से ली, सब का सब रुपया खर्च हो पाता है और अगर खर्च नहीं होता तो उन आफिसरान के खिलाफ इन्ट्री हो जाती है। तो यह गवर्नमेंट इंडिया की बात है और इस वास्ते मैं कहता हूं कि इस ऐक्ट के मातहत यूनियन टेरीटरी कोई तरक्की नहीं कर सकती है। इसके साथ ही साथ जो ऐक्ट बना वह बना, जो बिजनैस रूल्स बने, उसके अन्दर जो खास खास बातें हैं, मैं उनके बारे में इस समय कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है।

जहां तक लोगों का सवाल है, मिनिस्टरों का सवाल है, उन्हें कोई खास पावर नहीं है। जहां तक कि मैं समझता हूं उनके पास एक पावर है कि वे एक कार रख सकते हैं और टूर कर सकते हैं। असल में जो पावर है वह चीफ सेक्रेटरी के पास है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर के पास है और इनकी हालत का किसी को पता नहीं चलता है।

[श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया]

जहां तक प्लानिंग का संबंध है, मैं इस बारे में मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास इन बातों को कहने के लिए वक्त नहीं है । लेकिन मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि वहां पर किसी तरह का कोई पब्लिक सर्विस कमिशन नहीं है । वहां पर दो आफिसर बैठ जाते हैं और वही प्रोमोशन देते हैं और यह जरूरी नहीं है कि वह आफिसर हिमाचल प्रदेश का ही हो । यू० पी० एस० सी० जब कोई सलैक्शन वहां के लिए करता है तो उस सलैक्शन बोर्ड में वहां का हैड आफ दी डिपार्टमेंट बैठता है या डायरेक्टर होता है या फिर चीफ़ सेक्रेटरी होता है । ये लोग अपनी मर्जी के लोग छांटते हैं और उनके इलाके के आदमी हमारे यहां नौकरियों में बैठ जाते हैं और शिमले आदि का कोई नहीं लिया जाता है । इसी तरह से वहां के स्टाफ की हालत है । जितनी भी पोस्टें होती हैं, उनमें एक चौथाई लोग वहां के हैं आज 6, 7 होम मिनिस्ट्री का एक मुकम्मल इनचार्ज वहां पर रहा है यानी लैफ्टिनैन्ट गवर्नर । जिसकी वजह से वहां पर कुछ पोस्टें क्रियेट हुई हैं । आज यह कहा जाता है, मैंने यह सुना है कि हिमाचल प्रदेश के जो एड-मिनिस्ट्रेटर हैं वह यह कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो पंजाब के सर्विसेज वाले आने वाले हैं उनके लिए जगह नहीं है । तो मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब के हिल एरियाज हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और उन सर्विसेज़ वालों को हिमाचल प्रदेश में जगह मिलनी चाहिए । अगर कोई हिमाचल प्रदेश की सर्विस में डैपुटेशन में आया है, बाहर से आया है, तो उसको जाना चाहिये । लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो सर्विसेज़ वाले इस समय पंजाब के हिल एरियाज में काम कर रहे हैं उन्हें हिमाचल प्रदेश में आना चाहिये न कि उन्हें हरियाणा भेजा जाना चाहिये । अगर ऐसा किया गया तो मैं अपील करूंगा कि इस बारे में मिनिस्टर साहब जरूर ध्यान देंगे और ऐसी कोई बात नहीं होने देंगे जिससे उन लोगों पर ज्यादती हो ।

इसके साथ ही साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लिए कोई पब्लिक सर्विस कमिशन नहीं है और जितने भी आफिसर्स चुने जाते हैं वे थ्री पीज होते हैं, एक तो वे आफिसर हैं जो आइ० ए० एस० के होते हैं और जिन्हें प्रोबिशनरी पीरियड के लिए ट्रेनिंग के लिए वहां भेज दिया जाता है, ट्राइल के लिए वहां भेज दिया जाता है । दूसरे वे आफिसर वहां पर हैं जो पैंशनर हैं और इसके बाद फिर प्रमोटेड आफिसर हैं । इस तरह से वहां पर एडमिनिसट्रेशन की हालत है । मेरे पास टाइम थोड़ा है, इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इस बारे में भी हमारे मिनिस्टर साहब गौर फरमायेंगे ।

यहां पर कांगड़ा की जबान के बारे में कहा गया है । इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि 1881 की मर्दमशुमारी की रिपोर्ट में सिरमौर से लेकर कांगड़ा तक, बल्कि बघरवा काश्मीर तक, पहाड़ी जबान लिखी गई है । मगर उस समय मर्दमशुमारी करने वालों ने जैसा अगर देश के हिन्दू की हिन्दी लिखी गई, उसी तरह से सिख हुआ तो उसकी पंजाबी लिखी गई ।

डा० गोपालसिंह (नाम-निर्देशित) : 1911 में क्या हुआ ।

श्री सी० एल० वर्मा : 1891 और 1901 में भी यही जबान पहाड़ी मानी गई । 1911 में डा० ग्रेशन ने इसको एक खास नाम दिया और वह वैस्टर्न पहाड़ी थी । जम्मू की जबान डोंगरी थी । जैसा कि उसने यह बतलाया कि डोंगरी जबान जो है वह पंजाब की डायलेक्ट लिये हुए है मगर उसका कांगड़ा से कोई दखल नहीं था और यह जो जबान थी वह कांगड़ी ही जबान थी । (*Time bell rings*) इस वास्ते जो जबान का झगड़ा है, वह इस तरह का है । दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि इस देश में लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो क्या उनकी जबान अंग्रेजी हो गई ? हमारी जो जबान है वह अपनी जगह पर है ।

(Time bell rings)

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair]

SHRI B. D. KHOBARAGADE: I welcome this Bill and the decision of the Government to create two States, one for the Punjabi-speaking people and the other for the Hindi-speaking people. Actually, this demand should have been conceded a long time before. My party, the Republican Party of India, had long before demanded that there should be a State for the Punjabi-speaking people because that State is purely based on the linguistic principle. The Government should have accepted this demand of the Punjabi-speaking people long ago and two different States, one for the Hindi-speaking people and another for the Punjabi-speaking people should have been created long ago. But, unfortunately, wisdom did not dawn upon the Government and the leaders of ihe Congress Party. People had to struggle hard, fight for their legitimate demand, and when popular pressure was brought to bear upon the Congress Tarty, then only all these demands were accepted. Apart from that, whenever the Government was considering such problems of conflict, they had not considered the problems from a national point of view but from the party point of view; nay, not also from the party point of view, but from the point of view of power politics prevalent within the Congress Party itself. Some of the people have said that the demand of the Punjabi-speaking people is not based on language but that it is a communal demand. I do not agree with that contention. In my opinion, Punjabi is a language and when we have accepted the linguistic principle, then there should be no opposition whatsoever to the formation of a Punjabi-speaking State. Moreover, those people who claim that the Punjabi State is created on the basis of communalism, I am sorry to say, they do not understand the implications of what they say. If we accept their contention, what does it mean ? The Punjabi-speaking people are the Sikhs in that area and they want their own State. Why should they clamour for their own State? Dees it not mean that they are suffering under the majority rule of the Hindus 7 Does it not mean that under that rule L124RS/66—3 they have got their own grievances *7* Because of these grievances they want to have their own State. It will have different implications, different meanings, different imports if the foreigners come and see what kind of Hindu rule is there in this country. There is not one minority. There are the Sikhs, there are the Buddhists, there are the Jains, there are the Muslims, there are the Christians. What about these minorities ? If we accept the contention of these people that the Sikhs have been demanding for the Punjabi State just because they want to protect their own right, it will only mean that all the minorities, the Buddhists, the Muslims and others, they cannot enjoy their privileges and rights of citizenship and they cannot get any share in the economic development of this country. I would request the Home Minister—let him appoint one Commission and find out what is the percentage of the minorities in the Government services at the Centre as well as at the States. Let him find out whether the mionrities have benefited so far as the economic development is concerned. Let him examine and see what is the value of the shares purchased by the majority community and by Ihe minority communities. And he will find that in this country the minority people are suffering and therefore they are clamouring. Those people who are contending that this demand is based on communalism do not understand the meaning of their contention. It will have a bad effect on the nation.

Sir, when once it has been decided that there should be two different States, one, a Hindi-speaking State, and another, a Punjabi-speaking State, naturally there will be ce tain border areas which will be claimed by both the Stales. Of course, there is a dispute regarding the border areas between the Hindi-speaking people and the Punjabi-speaking people. There is the dispute about Chandigarh. I do not want to enter into the controversy regarding the census of 1931 and 1961. But from the figures it becomes clear that thee are many Hindus who have recorded their language as Punjabi. The total population of Hindus in Punjab, according to this Report is, about 1,29,30,000, that is 63.7 per cent, are

[Shri B. S. Khobagade.]

Hindus. But Hindi-speaking people are 55 per cent. It means that eight per cent of Hindus have recorded that their language is Punjabi. Only the Sikhs have recorded their language as Gui-mukhi or Punjabi. The contention of the Hindus does not hold water. Apart from that, when we have divided Punjab into two different States, naturally, whatever contiguous linguistic areas are there they will be included in the two different States. The only dispute will be regarding border areas, whether a particular town in a particular district should be included in the Hindi-speaking area or the Punjabi-speaking State. Unfortunately, Sir, no village-wise figures nave been made available, not even police station-wise or patwari circle-wise. Only there are figures available tehsil-wise. When the Census collected all these figures, all that record should have been available. The Census authorities could have found out the Punjabi-speaking number as well as the Hindi-speaking number. They could have found out the percentage of the Punjabi and the Hindi-speaking people in each and every village. Why did they not find that out ? That could form the basis for Tesolving the dispute. Wherever there is a majority of a particular language, "that area could be given to that particular language-speaking State which was contiguous to that area. They have not done that.

Sir, my own view is that we should not have Chandigarh as the centrally-adminis'ered territory. I am against it. There should not be any Union territory. By deciding to have Chandigarh as a Union territory the Government is creating a very bad precedent which will give rise to many difficult problems in future. Perhaps there will be a clamour and demand for creating many such Union territories. Only about ten or fifteen days back there has been a demand from the Bombay people to declare Bangalore will put forward the same (he people from Madras, Hyderabad and Bangalore will put forward the same demand. Only yesterday somebody observed that in Hyderabad there were five or six languages spoken and tomorrow there can be the demand for declaring it as a Union territory. The population of Hyderabad is more than six or seven lakhs whereas the population of Chandigarh is only about two lakhs. If you could have a Union territory with 2 lakhs of population, naturally Hyderabad with a population of about seven lakhs has every claim to be called a Union territory. *(Time btll rings.)* I have taken only seven or eight minutes. I have to speak for another five minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : Two minutes more.

SHRI B. D. KHOBARAGADE: My submission is that there should not be this Union territory of Chandigarh. Now the question would arise as to in which State it should be included. My own submission is that there should be an opinion poll for these disputed areas. Let the people go and say whether they want to join the Punjabi-speaking State or the Hindi-speaking State, and after considering the opinion of the majority in the cities and villages and after taking into consideration the contiguity of those areas with a particular language-speaking State, the disputed area should be merged either with the Hindi-speaking State or with the Punjabi-speaking State.

Sir, there are many provisions in this Bill which are a source of conflict. There are many matters which could be settled amicably by the two States within two years and, as the Bill says, if they are not in a position to decide within two years, naiurally the Centre would intervene. As I said earlier, the Central Government or the Congress Party does not consider any issue, any problem, from a national point of view. They have got their own vested in'erest to safeguard. Now what happens to this Mysore-Maharashtra border dispute. Four months ago it was decided by the Congress High Command that there would be a Commission to enquire into the question. Once they accepted the demand for the appointment of a Commission, they should have appointed the Commission. But power politics entered into this question. They have again started giving rise to controversies. Now they say that both the Chief Ministers

will sit together and decide the terms of reference. When conflict arises, the Government or the party in power never decide from the national point of view. They will only think which group will support in case this man stands up for the Chief Ministership and whether a particular group will support if such and such man stands for ihe Congress Presidentship. That is the criterion which compels them to take a decision in these matters.

Only one more point and I have done. Sir, by dividing Punjab into two smaller States, we have opened the door for more demands for smaller States. Already in the South we have got a number small States. Kerala is there. Madras is there. Mysore is there. But what about huge, monstrous monolithic States of Uttar Pradesh and Bihar? There is no balance between North and South. As we have now divided Punjab into smaller States, I would request the Government to consider the proposal and allow Uttar Pradesh and also Bihar to be divided into smaller States so that there is parity between the northern States and the southern States because during the past fifteen years we have seen all the Prime Ministers in this country from Uttar Pradesh. We had three Prime Ministers and all of them have been from Uttar Pradesh, and if we continue with the same monolithic Uttar Pradesh, we will have Prime Ministers all the time from that State. Therefore, I would request that Uttar Pradesh and Bihar should also be divided.

SHRI GULZAPJLAL NANDA : Sir, a brief reply from me would suffice. Points of criticism and objections raised in the course of the discussion have been very adequately answered by some of the Members of the House who spoke on this occasion. In fact, here it is not a question of the Opposition or this Party here. The points of view cut across party alignments. Sir, one would have thought that the reorganisation of the State of Punjab was an accomplished fact, that the Members would just proceed to deal with the provisions of the Bill before them. I do not think that I would be called upon to furnish any fresh justification for the principle and the, basis of this Bill.

Some Members, it appeared to me, just looked at the Bill, paused and then looked back. Some of them received it with a heavy heart, some with a feeling of sorrow, almost nostalgia. Several Members raised the question as to what interest has this reorganisation served, who was benefited by it, what problems it has solved. With considerable emotion Dr. Gopal Singh said—I am just giving the essence of it—that it would not solve the language problem, that it could only result in the industrial belt of Punjab being separated from Punjab and the mineral rich area as well as the forest area going over to Himachal Pradesh and various other things. Now he conjured up a picture of Punjab as a shrunken Punjab and all the good things being taken away from it. I just leave it at that. It only shows contrary emotions being roused by this reorganisation.

Criticism was levelled at us that we go on delaying and drifting and refusing to do the right thing till some kind of agitation is started and there is an outbreak of disorders. In this case, at any rate, it would not be a just accusation. The House is aware of the series of statements which I made here beginning with the 6th September. I have that before me. This statement was in the context of certain developments arising out of Sant Fateh Singh's intention to fast from September 10. 1 then said :

> "The whole question can be examined afresh with an open mind. The Government would be prepared to have further talks on the subject. We may hope that a cooperative solution wiH be discovered based on goodwill and a reasoned approach. The final test of the good of the various sections in conformity with the national interest should prevail. In these discussions, all unresolved matters can be taken up. For this, an atmosphere of goodwill and amity should be created."

This meant one thing that we had come to the conclusion that the *status quo* could not last and fresh efforts had to be made to bring about a settlement

[Shri Gulzarilal Nanda.]

based on mutual agreement. I emphasised that aspect of a cooperative solution. The *status quo* was not likely to be accepted, I knew that, but there were other ways, keeping in view some of the points made now, some of the considerations urged here, by Dr. Gopal Singh and others. I made very earnest endeavours myself towards that end but then they did not come to fruition and this division was inevitable. There was no escape from it. This decision was taken ultimately. This was all a peaceful process. This is something about which we should feel pleasure or heartened. Of course after that decision was made known there were some violent reactions but then a further question was asked : 'Why did we not do diis much earlier, in the earlier years ? Why did not Pandit Jawaharlal Nehru agree to it, why did he persist in resisting this demand and then his daughter, this Prime Minister, conceded this?' The answer was given by the hon. Akbar Ali Khan with reference to Hyderabad and die rationale of a composite Province was then very clear. What he said was that new forces arose. It was the impact of the new forces which made that change unavoidable. Reason always does not prevail. Pandit Jawaharlal^ reasons are still valid but meanwhile certain developments had taken place and there was an upsurge of emotions. They could not be disregarded. The solution which has emerged was evolved in full view of the objections, difficulties, problems and handicaps which it might create. What Dr. Gopal Singh pointed out was not lost sight of but one has to have a balanced structure and for that balance it became essential that there should be this division. Some Members ventured to peep into the future. There was an expression or a feeling or a hope of a demand: 'Why not go back on this linguistic division of this country ? Why not divide this country into 6 or 7 divisions *T* I think Shri Abdul Ghani said that. There were others who asked : 'Why not have IOI parts or units in this country ?' The analogy of the U.S.A. does not help us. There is one language there. The resources of even some of the units there will be incomparably larger than anything that even the largest State can provide here. Then there is another consideration. We are a nation of course. We have done many things to weld the people of this country into one solid nation; yet we are aware of the fact, painfully aware, that there are fissiparous tendencies at work in thi* country. We cannot neglect them, cannot forget them or be oblivious of them. The language is all right but linguistic fanaticism is also there. The different units being created on the basis of language is a matter of administrativo convenience and there are other advantages also but if that becomes so much of an impetus that divisive forces are generated out of it further, then it is not a good thing for this nation. Anything which hampers the solidarity of this country will be good for nobody in this country.

Let us now proceed, let our minds settle down to the new fact of the reorganisation. It is an act of faith. Let us hope and pray that each unit will carve out its destiny and secure for Ihe area a rapid progress and harmonious growth. The various units will cooperate among themselves, help one another in a spirit of neighbourliness, friendliness and goodwill. I have to say this, I have to emphasise this because there are apprehensions that things may be done and said which may pull us apart further and create further problems. I will take some of ihe points which have been made first. One asked: 'Why not have extended the President's Rule till the date of the next General Elections?' It might have been done but do we not know bow many people in Punjab and even in Haryana would have reconciled themselves to a postponement of the reorganisation itself till that date ? Very few. There may have been some but a large number were not prepared to wait and if the reorganisation could not he put off till that date, the President's Rule also could not be extended because you cannot bring in the new States into being and then not immediately bring in the democratic apparatus into function. Tlie Assembly had been kept alive for that purpose. The-efore to that there is that very good answer.

There were questions about the 1961 census and from that deductions were drawn and conclusions were drawn and suspicions were thrown about that this was not a purely linguistic approach, purely secular approach but it was tinged with communalism, infected with communalism. I do not know, I cannot say for everybody in that State whether the units or how many of them have been imbued with the idea of some kind of a communal spirit or communalism but so far as the Government is concerned, so far as we are concerned, how could there be even the remotest ground for suspicion for our taking any kind of communal view ? From the very beginning, the various statements made, the very reference to that Parliamentary Committee and its recommendations contained in its report brought out very clearly the basis, linguistic homogeneity, added to it being the question of cultural and linguistic affinities so far as the hill areas are concerned. In the terms of reference for the Boundary Commission we made that also perfectly plain, with nothing in doubt. The main basis was the linguistic basis for this reorganisation. If some people are not pleased with the fact that the starting point provided for the Punjab Boundary Commission was the 1961 Census, they may not be fully satisfied with that, but ,let them not attribute other kinds of considerations. So far as the Government is concerned, it had no other alternative. There had to be some starting point. Shall we take the 1931 Census ? That was what one Member suggested. Now it is too far away, and the next Census will be coming later on. So the latest Census was kept in mind in the terms of reference. Actually they provided for something more than the 1961 Census. It was made very clear that that need not be the only factor. There will be the administrative considerations and other considerations bearing on the administrative needs of the States, and the 1961 Census was just one factor. Other things could have modified that. Therefore there cannot be any question that the Boundary Commission was completely tied down to the 1961 Census. Other relevant factors and considerations were imported into the terms of reference and the Boundary Commission had a very big latitude about it, and it could.

> "The Commission has to apply the linguistic principle with due regard to the census figures of 1961 and other relevant considerations,".

I had stated that they applied the linguistic principle. Therefore, the linguistic principle was the main direction with due regard to the census figures of 1961. Here where is the ground for any feeling of dissatisfaction, any objection? The linguistic principle is the main direction, and the census figures of 1961 came io, but with this modification, this qualification, with due regard to other factors, whatever regard is due to them. Therefore, departures are permissible. The Commission may also take into account other factors, such as, administrative convenience, economic well-being, geographical contiguity and facility of communications. In recommending adjustments, ordinarily there should be no break-up of the existing tehsils. Now therefore to come back to it again and again, as if some wrong had been perpetrated, I think that is not the way, that is not the approach which will create that feeling of reconciliation on the two sides to, as I said, the new fact. This is an act of faith. Let it be approached in the spirit of faith, and everybody is concerned with it.

Then about Punjabi Suba. Why call this new unit "Punjabi Suba" ? Well, as a democracy, as a people we are free to change names. We can change our names also in this country. If I say I want to change my name, I can change it. But why should Punjab become "Punjabi Suba"? it is asked. It is asked, "How will it look if it were called Gujarati Suba or Marathi Suba or Bengali Suba?" Is there any Suba ? There is no such Suba. Now we are here in thjisi cauntry. There are so many languages in this country, and the language is derived from the name of the State. Gujarat is the name and there is the Gujarati language there. Therefore I think we should, let us, forget this altogether. Amendments have been tabled to the clauses in the Bill dealing with distribution of areas among the various units. Now some people may

[Shri Gulzarilal Nanda.] have cast reflection on this Commission *itself* and its report. There is no reason for that. What interest has this Commission one side or another ? The Commission has erred, some people have said. For every discrepancy they find, Uiey say that the Commission has erred. Would they have erred less if they had gone in line with the requirements of one State? They would have erred once more from tbe point of view of the other State. In this manner could they have made it a more acceptable document ? So I think, so far as the provisions in the Bill for purposes of allocation of areas between one unit and another are concerned, we should accept them without demur. We may not be satified. Himachal Pradesh may want Kalka. In the same manner Punjab may want some areas from Haryana. If you want something from here, it will be another reorganisation. Well, somebody asked, "Have these parties agreed ? Have they come to an agreement among themselves? Should they not be permitted to do that ?" Well, it is not one person agreeing with another, or one group agreeing with another. It has to be the State—the States concerned—as a State passing resolutions. In that case nobody can come in their way. That will be the way, no other way, no kind of a warning, no kind of an agitation; that will be a wrong to do. I should in all humility make it very clear that that will be a wrong course to adopt. It will not help. It will intensify and worsen our problems. Therefore, let it be taken in good spirit, and let a constructive approach be adopted. Then there is the question of Chandigarh. Well, I would put it on the same basis. We are having enough problems, enough headaches, enough things to do. Why should we have another Union territory in Chandigarh ? Some Member said that Chandigarh was made a Union territory so that I become Lord of Chandigarh. Possibly it was not very seriously meant, but it was said several times that we wanted to exercise our authority over Chandigarh. If the alternative is given *to* Haryana, wiH they agree? Will they agree to giving it to Punjab ? Will Punjab agree in one case ? Will Haryana agree in the other case ? If they do not, then there is no unanimous recommendation of the Commission on this subject. If there was a unanimous recommendation, we would not have departed from it. Therefore, in the best interests of all concerned,, something has been done, and 1 think this is the best thing to carry on till there is agreement between the parties.

SHRI NARINDAR SINGH BRAR : You can do the right thing. You can reject the recommendation of the Commission and you can do the right thing.

SHRI GULZARILAL NANDA: Right thing; if you were in Haryana what would be the right thing ? The right thing from Haryana's point of view is to give it to Haryana. I do not make any plea on behalf of this party or that party. We had a problem and for various reasons we thought that that was the best solution; otherwise also because another capital has to be created for another State. Here it is not a sort of . . .

SHRI NARINDAR SINGH BRAR : We want justice and nothing more.

SHRI GULZARILAL NANDA : Persuade those people. I am not saying that this is . . .

SHRI NARINDAR SINGH BRAR: Persuasion is not a proper thing. When the Government is there . . .

SHRI GULZARILAL NANDA: I think arguments will not help because if we do something which will go nearer to the heart's desire of one party . . .

SHRI NARINDAR SINGH BRAR : You do the right thing.

SHRI GULZARILAL NANDA : . . . it injures more deeply another party. Right thing; this is the right thing; other wise we would not have done. We have done it because it is the right thing.

SHRI U. S. DUGAL (Punjab): Am I to take it that everything that the Central Government does is always right ?

SARDAR RAGHBIR SINGH PANJHAZARI : Yes, certainly.

SHRI U. S. DUGAL : If everything were right, then there would not be so much trouble.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : बार बार अमेन्डमेन्ट करते हैं वही आपकी प्रतिष्ठा के लिये काफी है ।

SHRI GULZARJLAL NANDA: It may be as human beings when civil servants, Ministers consider the various problems and come to certain conclusions. These are political situations where one consideration militates against another and where a balance has to be struck as I said before. As long as our own conscience is clear and we feel convinced that we are doing it for the sake of the national good, it is the right thing. We believe it is an equitable arrangement and no question aises so far as we are concerned. If we have done a mistake it is a different thing but we have done the right thing as far as we could understand what was right and what was not right.

About the question of drawing, of lots—that is, the provisions contained in Part III, I believe—various questions were raised. Now we have acted in a particular way. We cannot be entirely dogmatic about it that there cannot be a better way of doing it. When we considered this problem we thought that this was the best solution among the various alternatives before us. We had brought some proposals but we ourselves changed them in the Lok Sabha after the discussions. We had thought of constituting the Haryana Assembly with the help of the eight Members of the Legislative Council of the Punjab, transferring them to this Assembly, thinking that there must be that number; not less than sixty is the requirement of the Constitution. We had to fulfil that requirement and we thought that would be a way out. Well it was pointed out to us and we also felt, although article 4 of the Constitution will probably be met, although this will be accommodated within that, we thought why we should make it more vulnerable on the ground of the principle of direct election. May be that election from territorial constituencies may not be considered as direct election. So we thought why not let the number 54 stand and let us apply the protection afforded by article 4 for the purpose of that smaller number. We thought that . . .

شری عبدالغنی : آرٹیکل ۴— آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ۶۰ سے کم کریں - وہ تو شیڈول ۱ اور شیڈول ۴ کو آپ کر سکتے ھیں - اس کو نہیں کر سکتے ھیں - آپ آئین میں امینڈمینٹ کئے بغیر نہیں کر سکتے -

†[श्री अब्दुल ग़नी : आर्टिकल चार आप को इस की इजाजत नहीं देता कि आप 60 से कम करें । वह तो शिड्यूल 1 और शिड्यूल 4 को आप कर सकते हैं । इसको नहीं कर सकते हैं । आप आईन में अमेंडमेंट किये बगैर नहीं कर सकते ।]

SHRI GULZARILAL NANDA : The hon. Member also must have read article 4. I have read it many times. And we have made use of it a number of times in the previous measures of reorganisation; in connection with Bombay and other places where reorganisation occurred we had recourse to this i article and it has given us no trouble. On that ground I feel very secure.

Then the Legislative Council itself Well, I had . . .

شری عبدالغنی : مسٹر وائس چیر مین—اگر یہ بات تھی تو آپ نے پھر ۳۷۰—اے آرٹیکل کیوں بنایا جب ناگا لینڈ بنایا تو اس میں کیوں امینڈمینٹ لائے - آئین میں اگر آپ آسانی سے امینڈ مینٹ کر سکتے تھے آرٹیکل ۴ کے ماتحت آپ کرتے تو پھر ناگا لینڈ کی دفعہ کے لئے کیوں امینڈ مینٹ لانا پڑا - وھاں ۴۸ ممبر تھے ۶۰ نہیں تھے کیوں لائے ۳۷۰—اے ؟

†[ ] Hindi transliteration.

†[श्री अब्दुल ग़नी : मिस्टर वाइस चेयर मेन, अगर यह बात थी तो आपने फिर 370 ए आर्टिकल क्यों बनाया ? जब नागालैण्ड बनाया तो इसमें क्यों अमेंडमेंट लाये । आईन में अगर आप आसानी से अमेंडमेंट कर सकते थे, आर्टिकल 4 के मातहत आप करते तो नागालैण्ड की दफ़ा के लिये क्यों अमेंडमेंट लाना पड़ा ? वहां 48 मेंम्बर थे 60 नहीं थे । क्यों लाये 370 ए?]

SHRI GULZARILAL NANDA: This matter was raised in the Lok Sabha; it was raised here also. We have consulted the best legal opinion, apart from the fact that the reading of the Constitution is very clear to my mind. As you, Sir, pointed out, if there is an issue of Constitution we only go by our best judgment and our best judgment is that it is perfectly right.

Then on the ques lion of Legislative Council itself, it was argued, why have it. I had a feeling personally also why when the State is reduced to this size we should have a Legislative Council. There it was in the Constitution. We could have changed that also but the general sense of the people concerned was that it should be retained. Well, like a number of other things, it is open to the new States to alter this. Let them alter it if they like. It is not that we are going to say that this is a fixed thing and it cannot be changed.

Then the question of the Speaker was raised. Why have we kept a provision by which the Speaker will continue to function ? Now the Speaker can continue to function as long as he has the confidence of the House but I do not raise that technical issue. The point is, this was borrowed again from the previous Reorganisation Act. This had been done in the previous Act also. Therefore there was a tradition, there was a precedent and we followed that. It could be otherwise also but there was no reason to adopt a line different from what we have taken so far. Then this was reinforced by another argument against this provision : why not have the Chief Minister similarly ? But we have kept the Assembly while the Council of Ministers had been set aside. The Chief Minister resigned and that was how a new position arose whereby the President took over the functions of the Assembly.

SARDAR RAGHBIR SINGH PANJHAZARI: What about Members who belong to Chandigarh ?

SHRI GULZARILAL NANDA: Of course whichever Members from Haryana have been dropped, why did we not drop the Members from Chandigarh ? Well,. Chandigarh is a small place but that does not mean that everybody who has a name in Chandigarh must necessarily be dropped, because generally so far as the Council names are concerned it is either from the territorial constituencies or they are elect-2 P.M. ed by the Members of the Assembly. Although the addresses of those persons were there, it did not mean that their location could be just restricted to that area.

SARDAR RAGHBIR SINGH PANJHAZARI : But their names are in the voters' list.

SHRI GULZARILAL NANDA : That is true. Well, if there was any provision, possibly it could have been otherwise. But in any case Chandigarh was not going to have an Assembly of its own.

Then, the other question is that of Himachal Pradesh. I think the Members from Himachal Pradesh have done a very good work. I do not say there is anything wrong. They have influenced hon. Members here in their favour and it does not mean that I am not in favour of elevating that Union territory to the level of a State. Now, it is not something done offhand. There are various other Union territories also. There are various considerations which have to be kept in view. It has a very large revenue deficit and that part of Punjab, which has gone to them, although it has great economic possibilities, is also a deficit area. Now, one has to look at what is going to happen. I do not know, if I were a Member from that Union territory, whether I would just jump into this and say : "Let me have a State and take away all the several crores of rupees from me." But I do not say

t[ ] Hindi transliteration.

anything as a final disposal of this question. It could not be done immediately in any case.

Then, I come to the scale of representation. I can understand one may not be satisfied with what one gets and one might want more. Yes. Here I have got the figures and I need not take the time of the House by repeating all those figures. Even as it is, it is in a very favourable position in this respect. Take Lok Sabha, for example. Against 8,80,000 which is the general average, in this case it is 4.7 lakhs. As regards the Assembly, although their proportion will be diminished somewhat, it is going to be still in a much more favourable position than the other areas. Even with the present representation, Himachal Pradesh is entitled to one seat in Lok Sabha for every 4.7 lakhs of population as against the all-India average of 8.8 lakhs. The proportion for the Assembly works out to 47,000 in Himachal Pradesh against 97,000 in Haryana and 1,09,000 in Punjab. I think it is good enough.

SHRI C. L. VARMA : There is a difference between hill areas and plains.

SHRI GULZARILAL NANDA : But there is a big differential in numbers and in ratio. It cannot be considered that we have treated the hill areas in the same way as other areas. That is why this weightage has been given. Another important point is . . .

DR. ANUP SINGH : May I ask one question about the Haryana Assembly ? The number which is going to be included in the Bill is 54, whereas the Constitution requires it to be not less than 60. How is that situation to be met 7

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): I think he has already replied to that point. You were not here. You please go ahead.

SHRI GULZARILAL NANDA : But he is here now in time for another point and that is about the lots, by which he is affected. Now, why did we not have all the names and no lots ? The hon. Member, Diwan Chaman Lall, is not here. He says that he came to meet me and I was not in my house, but he forgets that he came to me when I was in my room and we had a long talk on various things. Possibly he forgot about this. Then, I do not know whether I should bring out all the effort that I made to secure the content of hon. Members being put in one place or the other, so that this lot business could be avoided. I did try it and I approached Diwan Chaman Lall and the hon. Member there also I approached.

شری عبدالغنی : انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لاٹری کیوں رکھیں - انہوں نے یہ کہا کہ آپ دونوں میں فرق کیوں رکھتے ہیں - شری نیکی رام اور شری سرجیت سنگھ کے لئے ایک راستہ اور باقی ممبروں کے لئے لاٹری - انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے -

† [श्री अब्दुल ग़नी : उन्होंने यह नहीं कहा कि लाटरी क्यों रखें। उन्होंने यह कहा कि आप दोनों में फर्क क्यों रखते हैं। श्री नेकीराम और श्री सुरजीत सिंह के लिए एक रास्ता और बाकी मेम्बरों के लिये लाटरी। उन्होंने इसकी मुखाल्फत नहीं की है।]

SHRI GULZARILAL NANDA : If there is no opposition to lots being taken, then I have nothing to answer. The fact is there are two Members from Haryana in the first category who have their names in Haryana. Now, we can have only one in this category. Now, one of them has to be chosen. Let us be clear again. There is some kind of apprehension that henceforth someone will be in Haryana and someone will be in Punjab. It is no such thing. The word used is "deemed". We have to see this and we have to distribute this number. The same Members continue, but because of the allocation they have to be provided here or there. It is just a national arrangement. If a Member, as a result of taking a lot, is assigned

t[ ] Hindi transliteration.

[Shri Gulzarilal Nanda.]

to Haryana, he should not be afraid of it, saying that the Haryana people may not want him. Well, next time they may choose him or not. There is no need for him to depend upon these persons. He can give his name from any part of the State or any other State. He will be elected from that area. He does not depend upon them. Therefore, let there be no fear on that account. After all when particularly Diwan Chaman Lall felt that there should be only one Punjab, he should not be afraid of being either here or there. For him there snould be no such thing.

Now, I come to the question of common links. I would like to remove a misunderstanding about it. Why is it understood as if the persence of common links is a kind of detraction ? There is throughout the wholeness of the units. We have decided, when we introduced this institution of Zonal Councils to have more and more links, to have more and more collaboration, because on the one side for certain purposes or reasons there have to be separate units and on the other side for the purpose of national solidarity and unity there have to be more and more links. That is one reason. Another point is this. Do these links help or hinder the interests of *s* particular unit? Do they affect them adversely? Do we simply fight shy of being anywhere near one another or of having anything in common ? There is partition between brothers and then should there be nothing in common at all ? Why is that kind "of doubt ? Coming to the units, each one of them, I will explain about the High Court. Immediately there was no other way. We have to continue this. Anybody wiH recognise that you cannot immediately put it up. You will have enough time to do that. I will not recommend it now. Later on let the States do whatever they want to do.

I have a few points more. There is the Bhakra dam. Somehow the Central Government can do the defence of the country, the Central Government can attend to the finances of the country and if the Central Government comes into the picture for the sake of doing something more effectively, efficiently because of the bigness of the project,, because of the several units involved, why should you object to it ? Somebody says let Punjab go On doing it in this way; the others do not permit it. For the purpose of harmonious operation of it there is no other way.

Then about the universities and the various units, these units should be given two or three years as the reorganisation takes place. Meanwhile the two different units try to develop their own institutions. But if suddenly you have a break—the institutions as they are to serve the whole of the State, this part and that part—if you cut them, there are excessive facilities in one and deprivation of them in the other. It serves no purpose at all. I do not want to go into details. In some cases it has been specified that some things can be done even before the appointed day, some things will be done within a year, like that it has been there. You can do it more quickly, more speedily also. The Wakf Board—it was the hon. Member's point—it is already provided for generally. For the Gurdwara it is yet to be done. As there is an all-India legislation for this,—Wakf Board—it was not necessary,

I take leave of you, Mr. Vice-Chairman, and conclude. I might have other feelings in my mind, but I would not do that. Again very briefly I would plead with the Members of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh that they will still continue fo function and live as brothers and jointly try to improve the assets in the new State which they have got. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA) : The question is :

> "That the Bill to provide for the re-organisation of the existing State of Punjab and for matters connected therewith, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHAROAVA): We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHAROAVA) : There are five amendments. I would request the hon. Members to be brief in their remarks in moving the amendments.

SHRI GULZARILAL NANDA : Remarks have already been made on both sides. Let there be no remarks.

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.] SHRI ABDUL GHANI : I move :

1. "That in sub-clause (b) of clause 2, for the words and figures 'the 1st day of November, 1966' the words tnd figures 'the 1st day of March, 1967' be substituted."

SHRI U. S. DUGAL : I move :

2. "That is clause 2, for sub-clause (m), the following be substituted, namely :—

'(m) "successor State", in relation to the existing State of Punjab, means the State of Punjab or Haryana, and includes also the transferred territory;'."

SHRI ABDUL GHANI : I move :

3. "That in sub-clause (n) of clause 2, for the words 'Union territory of Himachal Pradesh' the words 'State of Himachal Pradesh' be substituted."

SHRI NARINDAR SINGH BRAR : I move :

40. "That at page 2, lines 15-16, the words 'the Union in relation to the Union territory of Chandigarh and' be deleted."

The questions were proposed.

شری عبدالغنی : میڈم — میرا امینڈمینٹ یہ ہے کہ یہ جو اسٹیٹ ظہور میں آ رہی ہیں ان کی تاریخ یکم نومبر ۱۹۶۶ کی بجائے یکم مارچ ۱۹۶۷ کی جائے - اس کے لئے تین کارن ہیں - ایک یہ ہے کہ میں ہوم منسٹر صاحب کو سننے کے بعد بھی اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ہریانہ میں ۴۵ ممبروں کی اسمبلی نہیں بنا پائینگے جیسا کہ میرا یقین ہے - یہ کہینگے کہ آرٹیکل ۴ ہمیں اجازت دیتا ہے کونسیکونشل یا کسی اور بنا پر لیکن میں ایسا نہیں مانتا ہوں اگر ایسا ممکن تھا تو جب ناگالینڈ کی یہ اسمبلی بنانے لگے تھے تو انہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ یہ امینڈ مینٹ لاتے اور اس میں یہ امینڈ مینٹ لائے - انہوں نے اس وقت اس میں امینڈ مینٹ کرکے کنسٹی ٹیوشن کی وفاداری کی - پارلیمنٹ کنسٹی ٹیوشن کو بنانے کے لئے ہے پارلیمنٹ کنسٹی ٹیوشن کو گرانے کے لئے نہیں ہے - کنسٹی ٹیوشن نے اجازت دی ہے کہ کم سے کم ۶۰ اور زیادہ سے زیادہ ۵۰۰ ممبر ہونے چاہئیں - پھر باقی رپرزنٹیشن آف دی پیوپلس ایکٹ ہے اور اس میں یہ جیسا چاہیں جتنی سیٹیں چاہیں اتنی کریں - میں سمجھتا ہوں کہ اسوقت اگر یہ یکم نومبر کی تاریخ رکھتے ہیں تو یہ ایک ایسی غلطی ہوگی جس سے جو ان کا مقصد ہے کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہریانہ، پنجاب اور ہماچل اسٹیٹس اپنی ترقی کریں پھلے پھولیں ان میں پیار ہو وہ پورا نہیں ہو پائے گا - نمبر دو جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بل ایسا ہے جس میں انہیں امینڈ مینٹ کرنا پڑے گا - میں نندہ جی سے یہ عرض کرنا

آف دیر اون وشیز، جو وہ چاہتے ہیں اس کے حساب سے خوبصورتی کے ساتھ ساری باتیں کی جائیں اور دونوں اسٹیٹوں کے جو مسئلے ہیں جن کو کانگریس کے بھائیوں نے اٹھایا ہے اور اپوزیشن کے بھائیوں نے بھی اٹھایا ہے وہ ٹھیک طور پر حل کئے جائیں ۔ میری مودبانہ درخواست ہے کہ وہاں جو ابھی رول چل رہا ہے گورنر کا اس کے ہوتے ہوئے وہاں کوئی آسمان نہیں گر پڑے گا بلکہ اس سے کوئی نہ کوئی بھلائی ہی ہونے والی ہے ۔ منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو موقعہ نہ دیں اور اس طرح یہ ڈیموکریسی نہیں ہوگی ۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں ڈیموکریسی کہاں رہی ہے ۔ کیا کانگڑہ کے ان بھائیوں کو آپ وہی لجسلیٹو اسمبلی کے پورے حقوق دینگے ۔ جو ان کو حاصل تھے ؟ آپ ان کو ہماچل میں ایسی جگہ ڈالدیتے ہیں جس کو آپ نے پوری اسٹیٹ نہیں بنایا اور اسکو اسمبلی کے پورے حقوق حاصل نہیں ہیں ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو وہاں نہیں ڈالئے ۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ڈیموکریسی کا نام لے کر آپ ایسی کوئی بات نہ کریں ۔ تو میں پھر یہ عرض کرونگا کہ یکم مارچ تک وہاں راشٹرپتی کا رول رہنے دیا جائے اور تب تک آپ اپنی تمام

[شری عبدالغنی]

چاہتا ہوں کہ دفعہ (۲) ۲۹ جو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کا خرچہ جو ہے وہ اسٹیٹیں جو ہوں وہ برداشت کرینگی ۔ اگر یہ کنسٹی ٹیوشن کے آرٹیکل ۲۲۹— ۲۳۰ اور ۲۳۱ کو دیکھینگے تو اس میں یہ صاف ہے کہ جہاں ہائی کورٹ ہوگا اور ایسی شکل میں جو دو تین اسٹیٹوں کا ہے اس کا خرچہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا ۔ وہاں کا ہائی کورٹ چنڈی گڑھ میں ہوگا اور چنڈی گڑھ سینٹر کے ماتحت ہے تو ابھی یہ چاہے جو کچھ سوچیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی غلطیاں رہ گئی ہیں اور ان کو دور کرنا مناسب ہوگا ۔ میں چیلنج تو نہیں کرتا کہ یہ بل ضرور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں رد کر لیا جائے گا لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں یہ بھولنا نہیں چاہئے کہ جس طرح سے آئین جاننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آرٹیکل — ۳ کے ماتحت ان کو حق ہے کہ وہ جہاں چاہیں کنسٹی ٹیوشن کا النگھن کریں وہاں ایسے آدمی بھی بیٹھے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات چل نہیں سکتی ۔ اگر یہ چل سکتی ہوتی تو ناگالینڈ کے بارے میں ان کو امینڈمینٹ لانا نہیں پڑتا ۔ یہ میری درخواست ہے کہ ''ان دی انٹرسٹ

ترٹیاں دور کر لیں - اس بل میں بھی بہت سی ترٹیاں ہیں اور ان کو بھی واضح کرنے کی میں کوشش کرونگا جب موقعہ آئے گا - چاہے وہ مانیں نہ مانیں لیکن میرا یقین ہے کہ یہ ہائی کورٹ بھی مانے گا اور سپریم کورٹ بھی مانے گا کہ اس میں ایسی ترٹیاں ہیں جو آئین کا النگھن کرتی ہیں - آئین کی بات کو نہیں مانتی ہیں اور اس سے نقصان ہونے والا ہے -

†[**श्री अब्दुल गनी** : मेडम, मेरा एमेंडमेंट यह है कि यह जो स्टेट जहूर में आ रही हैं उनकी तारीख यकम नवम्बर 1966 की बजाए यकम मार्च, 1967 की जाए । इसके लिए तीन कारण हैं । एक यह है कि मैं होम मिनिस्टर साहब को सुनने के बाद भी इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हरयाना में 54 मेम्बरों की असेम्बली यह नहीं बना पाएंगे जैसा कि मेरा यकीन है, यह कहेंगे कि आर्टीकल 4 हमें इजाजत देता है । कान्सीक्वैंश्यल या किसी और बिना पर, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं अगर ऐसा मुमकिन था तो जब नागा लैंड की यह असेम्बली बनाने लगे थे तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि यह एमेंडमेंट लाते और इसमें यह एमेंडमेंट लाए । उन्होंने उस वक्त इसमें एमेंडमेंट करके कांस्टीट्यूशन की वफ़ादारी की । पार्लियामेंट कांस्टीट्यूशन को बनाने के लिए है पार्लियामेंट कांस्टीट्यूशन को गिराने के लिए नहीं है । कांस्टीट्यूशन ने इजाजत दी है कि कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500 मेम्बर होने चाहिए । फिर बाकी रिप्रिजेंटेशन आफ दी पीपल एक्ट है और इसमें यह जैसा चाहें जितनी सीटें चाहें उतनी करें । मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर यह यकम नवम्बर की तारीख रखते हैं तो यह एक ऐसी गलती होगी जिस से जो उनका मकसद है कि बड़ी खूबसूरती के साथ हरयाना पंजाब और हिमाचल स्टेट्स अपनी तरक्की करें, फले फूलें, उनमें प्यार हो वह पूरा नहीं हो पाएगा ।

नवम्बर दो जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि यह बिल ऐसा है जिसमें उन्हें एमेंडमेंट करना पड़ेगा । मैं नन्दा जी से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि दफा 29(2) जो है उसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट का खर्चा जो है वह स्टेट्स जो हों वह बर्दाश्त करेंगी । अगर यह कांस्टीट्यूशन के आर्टीकल 229, 230, 231 को देखेंगे तो उसमें यह साफ है कि जहां हाई कोर्ट होगा और ऐसी शकल में जो दो तीन स्टेटों का है उसका खर्चा उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा । वहां का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में होगा और चंडीगढ़ सेंटर के मातहत है तो अभी यह चाहे तो कुछ सोचें लेकिन मैं यह समझता हूं कि इसमें बहुत सी गलतियां रह गई हैं और उनको दूर करना मुनासिब होगा । मैं चेलेंज तो नहीं करता कि यह बिल जरूर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रद्द किया जाएगा लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें यह भूलना नहीं चाहिए कि जिस तरह से आइन जानने वाले यहां बैठे हुए हैं, जो उनको मशवरा देते हैं कि आर्टीकल 4 के मातहत उनको हक है कि वह जहां चाहें कांस्टीट्यूशन का उल्लंघन करें वहां ऐसे आदमी भी बैठे हैं जो यह समझते हैं कि यह बात चल नहीं सकती । अगर यह चल सकती होती तो नागालैण्ड के बारे में उनको एमेंडमेंट लाना नहीं पड़ता । यह मेरी दरख्वास्त है कि इन दी इन्ट्रेस्ट आफ देयर औन विशिज़ जो वह चाहते हैं उसके हिसाब से खूबसूरती के साथ सारी बातें की जाएं और दोनों स्टेटों के जो मसले हैं जिनको कांग्रेस के भाइयों ने उठाया है और अपोज़िशन के भाइयों ने भी उठाया है वह ठीक तौर पर हल किए जाएं । मेरी मोदबाना दरख्वास्त है कि वहां जो अभी रूलचल रहा है गवर्नर का उसके होते हुए वहां कोई आसमान नहीं गिर

†[ ] Hindi transliteration.

[श्री अब्दुल ग़नी]

पड़ेगा बल्कि उससे कोई न कोई भलाई ही होने वाली है। मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि हम उनको मौका न दें और इस तरह से यह डेमोक्रेसी नहीं होगी। मैं कहता हूं कि यहां डेमोक्रेसी कहां रही है। क्या कांगड़ा के इन भाइयों को आप वही लेजिस्लेटिव असेम्बली के पूरे हकूक देंगे जो उनको हासिल थे ? आप उनको हिमाचल में ऐसी जगह डाल देते हैं जिसको आपने पूरी स्टेट नहीं बनाया और उसको असेम्बली के पूरे हकूक हासिल नहीं हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप उनको वहां नहीं डालिए। लेकिन मैं आप से कहता हूं कि डेमोक्रसी का नाम ले कर आप ऐसी कोई बात न करें। तो मैं फिर यह अर्ज करूंगा कि यकम मार्च तक वहां राष्ट्रपति का रूल रहने दिया जाए और तब तक आप अपनी तमाम त्रुटियां दूर कर लें। इस बिल में भी बहुत सी त्रुटियां हैं और उनको भी वाजिहे करने की मैं कोशिश करूंगा जब मौका आएगा चाहे वह माने न माने लेकिन मेरा यकीन है कि यह हाई कोर्ट भी मानेगा और सुप्रीम कोर्ट भी मानेगा कि इसमें ऐसी त्रुटियां हैं जो आइन का उल्लंघन करती हैं। आइन की बात को नहीं मानती हैं और इससे नकसान होने वाला है।]

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Dugal, please be very brief and De relevant to the amendment only.

SHRI U. S. DUGAL : I have four or five amendments which are quite indentical. So with your permission, if you agree, I would say that we take them together. They are Nos. 2, 4, 5, 6, 8, 9 and 10.

THE DEPUTY CHAIRMAN : But we are on clause 2. You can comment on them if you want. You need not speak on them again later.

SHRI U. S. DUGAL : Madam, the hon. Home Minister was pleased to declare in the Lok Sabha and in the Rajya Sabha about the formation of a Boundary Commission whose terms, I may say, are ambiguous and they were based on the 1961 census which was based completely on a communal basis. The original formula which has been accepted by the Rajya Sabha and the Lok Sabha not been taken into consideration.

I might further add that it had already been decided to include Chandigarh in the Punjabi Suba because Sardar Niranjan Talib, a member of the Punjab Assembly, was already sitting from Chandigarh in the Punjabi region. Since the terms of reference are ambiguous, the Boundary Commission in fact could not be impartial. So, my submission is this that justice should be done and various other places where there are predominantly Punjabis, should be taken into the Punjabi Suba.

SHRI GULZARILAL NANDA : Madam, I need not take up the time of the House in repeating what I have just now said. I have nothing more to add because no fresh point has been made.

श्री सी० एल० वर्मा : उपसभापति महोदया, मैं माननीय होम मिनिस्टर जी का बहुत मशकूर हूं कि कम से कम एक बात तो महसूस की गई . . . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN : The Minister had already replied.

SHRI C. L. VARMA : I have got the amendment.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Which one ?

SHRI C. L. VARMA : Number 40.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Rather, yours is No. 41.

श्री सी० एल० वर्मा : अगर हिमाचल प्रदेश को इस वक्त स्टेटहुड दें तो ज्यादा मुश्किलात महसूस होती हैं डेफिसिट बजट की वजह से। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि डेफिसिट बजट का कारण एक और है कि वहां पर दूसरे स्टेट्स के पैटर्न पर अफसर रखे जाते हैं। अफसर कैसे हैं ? मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में 60 से ऊपर क्लास टू के अफसर हैं, 20-25 क्लास वन के अफसर हैं। कोई आलू का एक्सपर्ट है, कोई अदरक

का एक्सपर्ट है । इसी तरह से दूसरे डिपार्टमेंट्स में देख लीजिए । डिस्ट्रिक्ट कोई 25 हजार का है, कोई 40 हजार का है, कोई डेढ़ लाख का है । उस डिस्ट्रिक्ट लेवल में सब आई० ए० एस० के अफसर हैं । सब प्रोवेशनर्स हिमाचल प्रदेश को दे दिए जाते हैं, उनके एक्सपेंसेज हमारी तरफ आ जाते हैं । अगर ठीक तरह से डिस्ट्रिक्ट्स को आर्गेनाइज किया जाय तो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा एक-चौथाई रह जायगा । ये सब की सब बातें होम मिनिस्ट्री की तरफ से होती हैं । मैं आपसे यह अपील करूंगा कि इस सिलसिले में खर्च जो है वह कम किया जा सकता है अगर होम मिनिस्ट्री करना चाहे ।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चोरड़िया : उपसभापति महोदया, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है यह ट्रांसफर टेरीटरी के बारे में है । हमारा अमेंडमेंट यह है कि जो हिस्सा हिमाचल प्रदेश को दिया जा रहा है उसमें जो शब्द ऊपर कहा गया है 'यूनियन टेरीटरी' वह हट जाय । यूनियन टेरीटरी' हटाने का प्रमुख कारण यह है कि हिमाचल प्रदेश के लोग भी यह चाहते हैं कि उनको एक स्टेट का स्टेटस दिया जाय और वहां की जनसंख्या भी अब बढ़ चुकी है । इसके अलावा पंजाब का कुछ पहाड़ी हिस्सा भी — कल ही यहां बहस हुई थी — हिमाचल में मिलाना चाहते हैं । अब यह बात जरूर है कि जो राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से गृह मंत्रालय की हुकूमत है वह कुछ नहीं कहेगी, मगर वहां एक प्रजातन्त्री हुकूमत हो और वहां के लोग जब चाहते हैं कि अब 'यूनियन टेरीटरी' हटे और उनको स्टेट का स्टेटस दिया जाय तो ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकार किया जाय ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

1. "That in sub-clause (b) of clause 2, for the words and figures 'the 1st day of November, 1966' the words and figures 'the 1st day of March, 1967' be substituted."

The motion was negatived.

SHRI U. S. DUGAL : Madam Deputy Chairman, I wish to withdraw my amendment No. 2.

**Amendment No. 1 was, by leave, witlidrawn.*

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

3.'That in sub-clause (n) of clause 2, for the words 'Union territory of Himachal Pradesh' the words 'State of Himachal Pradesh' be substituted.".

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

4.'That at page 2, lines 15-16 the words 'the Union in relation to the Union territory of Chandigarh and' b_e deleted."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3*—Formation of Haryana State*

SHRI U. S. DUGAL: Madam, I move :

4. "That in clause 3, for item (a) of sub-clause (1), ihe following be subs'ituted, namely :—

'(a) Hissar excluding Sirsa tah-sil, Tohana Sub-tahsil and Ratia. Block, Rohlak, Gurgaon, Karnal excluding Sahabad Police Station and Guhla sub-tahsil and Mahendragarh districts;'."

5. "That in clause 3, for item (c) of sub-clause (1), the following be substituted, namely :—

*For text of the amendment, *vide* col. 6475 *supra.*

[Shri U. S. Dugal.]

'(c) Ambala excluding Sadar Police Station, Jagadhri and Narain-garh tahsils of Ambala districts;'."

6. "That in clause 3, items *(d)* and *(e) oi* sub-clause (1) be deleted."

8. "That in clause 3, for sub-clause (3), the following be substituted, namely :—

'(3) The territories referred to in clause (c) of sub-section (1) shall form a separate district to be known as Ambala district in the State of Haryana.' "

SHRI ABDUL GHANI: Madarn, I move:

7. "That in clause 3, after item (c) of sub-clause (1), the following item be inserted, namely :—

'(/) Fazilka tahsil of Ferozepur district*."

The questiotis were proposed.

SHRI U. S. DUGAL : Madam, I have already said what I had to say.

شری عبدالغنی : میرا امینڈمینٹ بالکل سادھارن ہے - جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ پنجاب اسٹیٹ بنانے کا سہرا اکالیوں کو ہے اور ہریانہ اسٹیٹ بنانے کا سہرا - آئی مے بی رونگ - اور (*Interruption.*) ہو سکتا ہے کہ آپ کا خیال ٹھیک ہوگا - مگر یہ سہرا تو چودھری دیوی لال اور ان کے ساتھیوں کے سر ہے - وہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ فاضلکا ہندی بولنے والا علاقہ ہے اس لئے اسکو ہریانہ میں بھیج دیا جائے اور انکو یہ بھی اتفاق ہے کہ جو پنجابی بولنے والے ٹکڑے ہیں وہ پنجاب کو دے دیئے جائیں - اس میں میرا امینڈ مینٹ بالکل سادھارن ہے ایسا ہے جس چیز کو کمیشن نے بھی ایگری کیا ہے - میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات جو کمیشن نے اچھی کی ہے جس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے ہوم منسٹر صاحب اس کو قبول کرینگے -

†[**श्री अब्दुल ग़नी** : मेरा एमेंडमेंट बिल्कुल साधारण है । जैसा मैंने पहले कहा था कि पंजाब स्टेट बनाने का सेहरा अकालियों को है और हरयाना स्टेट बनाने का सेहरा (*Interruption.*) आई में बी रोंग, और हो सकता है कि आप का ख्याल ठीक हो मगर यह सेहरा तो चौधरी देवी लाल और उनके साथियों के सिर है । वे दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फाजिलका हिन्दी बोलने वाला इलाका है इसलिए उसको हरयाना में भेज दिया जाए और उनको यह भी इत्तफाक है कि जो पंजाबी बोलने वाले टुकड़े हैं वे पंजाब को दे दिए जाएं । इसमें मेरा एमेंडमेंट बिल्कुल साधारण है, ऐसा है, जिस चीज को कमीशन ने भी एग्री किया है । मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात जो कमीशन ने अच्छी की है जिस में कोई झगड़ा नहीं है, हमारे होम मिनिस्टर साहब इसको कबूल करेंगे ।]

THE DEPUTY CHAIRMAN : Are you accepting them ?

SHRI GULZARILAL NANDA : No.

SHRI U. S. DUGAL : Madam, I withdraw amendments Nos. 4, 5, 6 and 8.

‡*Amendments Nos.* 4, 5, 6 *and* 8 *were, by leave, withdrawn.*

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

7. "That in clause 3, after item (*e*) of sub-clause (1), the following item be inserted, namely :—

'(*f*) Fazilka tahsil of Ferozepur district,'."

The motion was negatived.

†[ ] *Hindi transliteration.*

‡For text of the amendments, *vide* cols. 6484-6485 *supra.*

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted. Clause 3 *was added to the Bill.*

Clause A—Formation of Union territory of Chandigarh

SHRI U. S. DUGAL: Madam, I move :

9. "That for the existing clause 4, the following be substituted, namely :

'4. On and from the appointed day, Chandigarh comprising of the territories of Manimajra and Manauli Kanungo circles of Kharar tahsil of Ambala district in the existing State of Punjab as are specified in the Second Schedule shall form part of the State of Punjab (Punjabi Suba) and the city of Chandigarh shall be the capital of the State of Punjab.'"

The question was proposed.

SHRI U. S. DUGAL : Madam, I withdraw my amendment.

** Amendment No,* 9 *was, by leave, withdrawn.*

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That clause 4 stand part *at* the Bill."

The motion was adopted. Clause 4 *was added to the Bill.*

Clause 5—*Transfer of territory from Punjab to Himachal Pradesh*

SHRI NARINDAR SINGH BRAR : Madam, I move :

47. "That at pages 3 and 4, lines 34 to 36 and 1 to 10, respectively, be deleted."

The question was put and the motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 *was added to the Bill.*

Clause 6—*State of Punjab and territorial divisions thereof*

SHRI U. S. DUGAL: Madam, I move :

12. "That in sub-clause (1) " of clause (6), for the words 'other than those specified in sub-section (1) of section 3, section 4 and sub-section (1) of section 5' the words 'other than those included in the territories of Haryana and Himachal Pradesh along with Ganganagar district of the State of Rajasthan' be substituted."

SHRI ABDUL GHANI: Madam, I move :

13. "That in sub-clause (2) of clause 6, for the words 'Rupar dis trict' the words 'Fatehgarh Sahib dis trict' be substituted."

SHRI U. S. DUGAL: Madam, I move :

14. "That in clause 6, after sub clause (2), the following sub-clause be inserted, namely :—

'(3) On and from the appointed day, the name of the State of Punjab shall be "Punjabi Suba".'"

The questions were propossd.

شری عبدالغنی (پنجاب) : میرا اس میں بہت چھوٹا سا امینڈمینٹ ہے ۔ ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا کیا جو آنند پور صاحب کو ڈسٹرکٹ قرار دیا ۔ یہاں یہ چاہتے ہیں کہ روپڑ کو ڈسٹرکٹ قرار دیں ۔ روپڑ بالکل ایک سائڈ میں ہے اور جب سے ہم ہسٹری پڑھتے چلے آ رہے ہیں تب سے ہم جانتے ہیں کہ فتح گڑھ صاحب کا بڑا درجہ چلا آ رہا

•For text of the amendment, *vide* col. 6487 *supra.* L124RS/66—\

ہوگا تمام علاقے کا۔ کھمان تھانہ اور کھرڑ تھانہ اور روپڑ تھانہ اور کھنہ کا آدھا تھانہ ملا کر فتح گڑھ صاحب ڈسٹرکٹ رکھا جائے۔ ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔

†[**श्री अब्दुल गनी** : मेरा इसमें बहुत छोटा सा एमेंडमेंट है। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा किया जो आनन्द पुर साहब को डिस्ट्रिक्ट करार दिया। यहां यह चाहते हैं कि रोपड़ को डिस्ट्रिक्ट करार दें। रोपड़ बिल्कुल एक साइड में है और जब से हम हिस्ट्री पढ़ते चले आ रहे हैं, तबसे हम जानते हैं कि फतेहगढ़ साहब का बड़ा दर्जा चला आ रहा है, बड़ा तारीखी मुकाम है। फतेहगढ़ साहब एन सेंटर में है। खन्ना खरड़ और रोपड़ को मिला दिया जाए तो बहुत उम्दा है। गुरु गुविन्द सिंह महाराज के बच्चे वहां शहीद हुए और वह एक ऐसी जगह है जो पहले फतेहगढ़ साहब की कचहरी के लिये ले ली गई थी ताकि उसको डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। वह एक अहम मरकजी मुकाम है, लिहाजा फतेहगढ़ ही मौजूं व मुफीद रहेगा कि वह जिले का सदर मुकाम बनाया जाए।

तो मेरा इसमें कोई मजहबी जजबा या इखलाकी पहलू नहीं है बल्कि चूंकि हमेशा सरकार की यह पालिसी रही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वह हो जहां आसानी से लोग आ सकें और इसी बिना पर चंडीगढ़ बनाया गया था क्योंकि शिमला बिल्कुल एक तरफ था और काफी इसमें दिक्कत आती थी तो मैं इस लिहाज से भी चाहता हूं। क्योंकि यहां लोग आसानी से हर तरफ से आ सकते हैं और मरकजी मुकाम है और आने में आसानियां हैं।

मैं उम्मीद करता हूं कि चूंकि यह बिल्कुल साधारण तरमीम है इसको हमारे होम मिनिस्टर कबूल करेंगे और अगर इस वक्त कबूल न कर पाएं तो वह एशोरेंस ही दे दें कि इसके लिए

†[ ] Hindi transliteration.

[شری عبدالغنی]

ہے۔ بڑا تاریخی مقام ہے۔ فتح گڑھ صاحب عین سینٹر میں ہے۔ کھنہ۔ کھرڑ اور روپڑ کو ملا دیا جائے تو بہت عمدہ ہے۔ گورو گوبند سنگھ صاحب مہاراج کے بچے وہاں شہید ہوئے اور وہ ایک ایسی جگہ ہے جو پہلے فتح گڑھ صاحب کی کچہری کے لئے لی گئی تھی تاکہ اس کو ڈسٹرکٹ بنایا جائے۔ وہ ایک اہم مرکزی مقام ہے لہذا فتح گڑھ ہی موزوں و مفید رہے گا کہ وہ ضلع کا صدر مقام بنایا جائے۔

تو میرا اس میں کوئی مذہبی جذبہ یا اخلاقی پہلو نہیں ہے بلکہ چونکہ ہمیشہ سرکار کی یہ پالیسی رہی ہے کہ ایڈمنسٹریٹیو سینٹر وہ ہو جہاں آسانی سے لوگ آ سکیں اور اسی بنا پر چنڈی گڑھ بنایا گیا تھا کیونکہ شملہ بالکل ایک طرف تھا اور کافی اس میں دقت آتی تھی۔ تو میں اس لحاظ سے بھی چاہتا ہوں۔ کیونکہ یہاں لوگ آسانی سے ہر طرف سے آ سکتے ہیں اور مرکزی مقام ہے اور آنے میں آسانیاں ہیں۔

میں امید کرتا ہوں کہ چونکہ یہ بالکل سادھارن ترمیم ہے اس کو ہمارے ہوم منسٹر قبول کرینگے اور اگر اس وقت قبول نہ کر پائیں تو وہ اشورنس ہی دے دیں کہ اس کے لئے کچھ بعد میں ہو جائیگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی بھلا

कुछ बाद में हो जाएगा । तो मैं मसझता हूं कि काफी भला होगा तमाम इलाके का । खमान थाना और खरड़ थाना और रोपड़ थाना और खन्ना का आधा थाना मिला कर फतेहगढ़ साहब डिस्ट्रिक्ट रखा जाए ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है ।]

श्री गुलजारीलाल नन्दा : इसमें मैं कोई एतराज खड़ा नहीं कर रहा हूं मगर इस बिल में इसके लिये गुंजाइश नहीं थी क्योंकि इस बिल में जो टुकड़े हो गये, जो बटवारे की वजह से हिस्से कट गये, उनको इकट्ठा कर के कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव फार्म देना था इसलिये वह आनन्दपुर साहिब आया हुआ है लेकिन इस चीज को तो टच नहीं किया गया है इसलिये यह बात इसमें दाखिल हो नहीं सकती ।

SHRI U. S. DUGAL : Madarn, I beg leave to withdraw my amendment No. 12.

'Amendment No. 12 *was, by leave, withdrawn.*

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

13. "That in sub-clause (2) of clause 6, for the words 'Rupar district' the words 'Fatehgarh Sahib dutrict' be substituted. "

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

14. "That in clause 6, after sub clause (2), the following sub-clause be inserted, namely :—

'(3) On and from the appointed day, the name of the State of Punjab shall be "Punjabi Suba".'"

The motion was negatived.

SHRI U. S. DUGAL : Madam, I have not spoken on it and it is lost. I only spoke up to amendment No. 10, and not 14.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I am sorry. I did not know that you wanted to apeak.

•For text of the amendment, *vide* col. 6488 *supra.*

SHRI U. S. DUGAL : Through you I would request the hon'ble Home Minister to give me a definite reply whether my request is going to be agreed to or not. This is the only change.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The Minister has already replied that he il not accepting any of these amendments.

SHRI U. S. DUGAL : If this simple request of ours is not acceptable, I would stage a walk-out.

(At this stage hon'ble Shri U. S. Dugal and Shri Narindar Singh Brar left the House)

SOME HON. MEMBERS : Here, here.

THE DEPUTY CHAIRMAN : I do not think any remarks are necessary from this side. Let us move on in the proper parliamentary fashion. Now, I put clause 6 to the vote.

The question is :

"That Clause 6 stand part of th* Bill."

The motion was adopted.

Clause 6 was *added to the Bill.*

Clause 7—*Amendment of the First Schedule to the Constitution.*

SHRI V. M. CHORDIA : Madarn : I move :

50. "That at page 5,_ after line 36, the following be inserted; namely : —

'18. Himachal Pradesh : The territories .specified in sub-section (1) of section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966.'"

51. "That at page 6, lines 3 to 8 be deleted."

(The amendments also stood In thf names of Sarvashri C. L. Varma and Sundar Singh Bhandari)

the questions were proposed.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चोरड़िया : उपसभापति महोदया, इसमें जो संशोधन चाहा गया है वह इसलिये है कि जिस तरह से हरि-

[श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया]

याणा को एक स्टेट का स्टेट्स दिया है उसी तरह से हमारा आबजेक्ट यह था कि हिमाचल प्रदेश को भी एक स्टेट का स्टेट्स दिया जाय। पहले भी अमेंडमेंट दिया था। इस पर विशेष चर्चा करना नहीं चाहता क्योंकि वह अमेंडमेंट लास्ट हो गया, फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री महोदय इस पर विचार करें और हिमाचल प्रदेश को भी एक स्टेट का स्टेट्स देने की कृपा करें।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Would you like to reply ?

SHRI GULZARILAL NANDA : Nothing more than what I have already said.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is :

50. "That at page 5, after line 36, the following be inserted, namely :—

'18. Himachal Pradesh : The territories specified in sub-section (1) of section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966.'"

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

51. "That at page 6, lines 3 to 8 be deleted."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That clause 7 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 7 *was added to the Bill.*

Clause 8 *was added to the Bill.*

Clause 9—Amendment of the Fourth Schedule to the Constitution

SHRI V. M. CHORDIA : Madam, I move :

53. "That at page 6, after line 29, the following be inserted, namely ;—

22. Chandigarh ... IV

55. "That at page 6, line 34, for the figure '228' the figure '229' be substituted."

{The amendments also stood in the name of Shri Sundar Singh Bhandari.)

The questions were propoMd.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : इसमें संशोधन के द्वारा यह चाहा गया है कि चंडीगढ़ के रहने वालों को भी, जिस को कि यूनियन टेरीटरी माना जा रहा है, उनको भी राज्य सभा में अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिले। हमने कई अधिकार यूनियन टेरीटारीज को दे रखे हैं आर्टिकल 80 के अंतर्गत उनकी सारी लिस्ट कांस्टीट्यूशन में है। भारतवर्ष में यूनियन टेरीटरीज के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनका कि प्रतिनिधित्व नहीं है। तो मेरा नम्र निवेदन है कि चंडीगढ़ का भी एक प्रतिनिधि रहे या मंत्री महोदय कम से कम यह आश्वासन दें कि यूनियन टेरीटरीज के लोग बाई-रोटेशन, कुछ वर्षों के बाद, क्रम के अनुसार राज्य सभा में भेज सकें इसी आशय से संशोधन रखा है और नं० 55, कान्सीक्वेन्शल है।

श्री गुलजारीलाल नन्दा : चंडीगढ़ के सिवाय और भी यूनियन टेरीटरीज है जिनका रिप्रेजेन्टेशन नहीं है। आगे के लिये जो आपका सुझाव है वह सोचा जा सकता है।

SHRI V. M. CHORDIA : I beg leave of the House to withdraw my amendment Nos. 53 and 55.

**The amendments were, by leave, withdrawn.*

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That clause 9 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 9 *was added to the Bill,*

Clauses 10 to 12 *were added to the* Bill.

•For text of the amendments, *vide* cols. 6493.6494 *supra.*

Clause 13—*Provisions as to Legislative Assemblies*

SHRI ABDUL GHANI: I move :

20. "That in sub-clause (1) of clause 13, for the word 'fifty-four' the word 'fifty-six* be substituted."

SHRI V. M. CHORDIA : I move :

56. "That at page 7, line 25, for the word 'fifty-four' the word 'seventy' be substituted."

57. "That at page 7, lines 25-26, for the word 'eighty-seven' tbe word* 'one hundred and twenty-two' be iuo-itituted."

58. "That at page 7, line 31. for the figures and words '4A. Haryana . . . 54' the figures and words '4A. Haryana ... 70' be substituted."

(The amendment Nos. 56, 57 *and* 58 *also stood in the name of Shri Sundar Singh Bhandari.)*

Th: questions were proposed.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : उप-सभापति, महोदया,यह जो संशोधन रखा है वह जो लेजिस्लेटिव असेम्बलीज बनेंगी, उनमें कितने-कितने सदस्य रहें, उसके बारे में है। एक तो संविधान की मूल व्यवस्था है कि कम से कम किसी भी विधान सभा में 60 सदस्य से कम नहीं होंगे और जिसको हम आर्टिकल 4 के अंतर्गत रहते हुये, उसकी परवाह न करके 54 की व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि जो वहां पर सदस्य हों उनमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेम्बर हैं उनको जोड़ कर पूरी विधान सभा बनायी जानी चाहिये और उनकी संख्या पूरी करनी चाहिये। इसी दृष्टि से पंजाब के लिये जोड़ा है कि वहां 122 सदस्य हो जायें, हरियाना में 77 सदस्य और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह से सदस्य बढ़ाये हैं। तो यह इस दृष्टि से है कि हम उन लोगों को प्रतिनिधित्व करने का पूरा अधिकार दें और हमारे संविधान में जो आशय है उसको पूरा कर सकें और उसकी व्यवस्था कर सकें। आशा है मंत्री महोदय को यह स्वीकार होगा।

<u>شری عبدالغنی</u> : میڈم——ہم دفعہ ۱۳ میں تو ۸۷ اور ۵۴ دیکھتے ہیں اور دفعہ ۲۴ میں ہم دیکھتے ہیں ۸۱—۱۰۴ اور ۶۰ - میں سمجھتا ہوں یہ بات پھر آ کر غلط ہو جاتی ہے - جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ پہلے تو رپرزنٹیشن آف دی پیوپل ایکٹ ہم مانتے ہیں کہ اس کے مطابق بننا ہے لیکن ۲۴ دفعہ میں جو کرتے ہیں اس میں نہیں بنا رہے ہیں - دونوں میں جو جھمیلا ہوتا ہے اس کو ختم کرکے کیوں نہیں ایک کرتے ؟ یکم نومبر کو کرنا ہے تو ابھی کر لیں - اگر اس کا بھی ٹائم مدت تک بڑھا لیا تھا یہاں بھی جلدی کرا لیں الیکشن کرا لیں - سوا پانچ کر دیں - بجائے پانچ سال کے - یہ دونوں مشکلات ہو جائینگی کہ ۲۴ دفعہ جو ہے اس میں اور اس میں مت بھید ہو جائے گا اور خواسخواہ ایک نئی پریشانی ہوگی - میرا یقین ہے اس پر آپ وچار کرینگے -

†[**श्री अब्दुल ग़नी** : मेडम, हम दफा 13 में तो 87 और 54 देखते हैं और दफा 24 में हम देखते हैं 81, 104 और 60। मैं समझता हूं यह बात फिर आकर गलत हो जाती है। जैसा मैंने पहले अर्ज किया था कि पहले तो रिप्रिजेंटेशन आफ दी पीपल एक्ट हम मानते हैं कि उसके मुताबिक बनना है लेकिन 24 दफा में जो करते हैं उसमें नहीं बना रहे हैं। दोनों में जो झमेला होता है उसको खत्म करके क्यों नहीं एक करते ? यकम नवम्बर को करना है

†[ ] Hindi transliteration.

[श्री अब्दुल गनी]

तो अभी कर लें । अगर उसका भी टाइम मुद्दत तक बढ़ा लिया था यहां भी जल्दी करा लें, इलेक्शन करा लें । सवा पांच कर दें बजाए पांच साल के । यह दोनों मुश्किलात हो जायेंगी कि 24 दफा जो है उसमें और इसमें मतभेद हो जाएगा और ख्वाहमख्वाह एक नई परेशानी होगी । मेरा यकीन है इस पर आप विचार करेंगे ।)

श्री गुलजारीलाल नन्दा : ऐसा मुश्किलात के बारे में सोच लिया है, जो कुछ यह बताया जा रहा है वह ज्यादा मुसीबत पैदा करेगा ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is :

56. "That at page 7, line 25, for the word 'fifty-four' the word 'seven ty' be substituted."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

57. " That at page 7, lines 25-26, for the word 'eighty-seven' the words 'one hundred and twenty-two' be sub stituted."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

58. "That at page 7, line 31, for the figures and words '4A. Haryana .... 54' the figures and words '4A. Haryana-------70' be substituted."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is:

20. "That in sub.clause (1) of clause 13, for the word 'fifty-four' the word 'fifty-six' be substituted." *The motion was negatived.*

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

'That clause 13 stand part of tht Bill."

The motion was adopted. clause 13, for *th*$_e$ word fifty-four' *Clauses* 14 *and* 15 *were added to the BUI.*

THE DEPUTY CHAIRMAN : Thcit is an amendment for a new clause 15A.

New Clause ISA

SHRI V. M. CHORDIA : I move :

59. "That at page 8, after line 28, the following new clause be inserted, namely :

*15A(l)(a) The sixteen persons specified in the Seventh Schedule who are members of the Legislativt Council of the existing State of Punjab shall on and from the appointed day, become members of the Legislative Assembly of the State of Haryana.

(2) The remaining thirty-five persons who are members of tht Legislative Council of the existing State of Punjab shall on and from the appointed day become members of the Legislative Assembly ot tht State of Punjab.' "

(The amendment also stood in the name of Shri Sundar Singh Bhandari.)

मेरे संशोधन का आशय यही है उपसभापति महोदया कि हम यह नहीं चाहते कि पंजाब में भी एक लेजिस्लेटिव काउन्सिल बने और जिस तरह से मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, वही व्यवस्था पंजाब के लिये भी हम चाहते हैं कि पंजाब में भी काउंसिल न हो और जो सदस्य हों उनको लेजिस्लेटिव असेम्बली का मेम्बर माना जाय अभी और बाद में रेप्रेजेन्टेशन आफ द पीपुल ऐक्ट के अंतर्गत जो काम किया जाय वह जल्दी किया जाय । इस आशय से संशोधन है । खर्चा भी न बढ़े काम भी हो जाय, इस दृष्टि से हम चाहते हैं मंत्री महोदय इसको स्वीकार करें ।

The question was proposed.

شری عبدالغنی : میڈم——میری عرض یہ ہے کہ نئی اسٹیٹیں بن رہی ہیں وہ اگر چاہیں ریکویسٹ کریں سینٹرل گورنمنٹ کو کہ وہاں کے لئے یہ شرط لائیں تو میں سمجھتا ہوں مناسب

ہوگا بجائے اس کے کہ زبردستی ایک پر لاگو کریں کیونکہ ان کو آپ بے ممبر آف دی ہاؤس ضرور بنانا ہے - میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی بات ایسے نہیں مانتے امینڈمینٹ نہیں مانتے تو ویسے ہی مان لیں - وہ رکھنا چاہیں رکھیں نہ رکھنا چاہیں نہ رکھیں - ان پر بوجھا کیوں ڈالا جا رہا ہے -

†[श्री अब्दुल गनी : मेडम मेरी अर्ज यह है कि नई स्टेटें बन रही हैं वह अगर चाहें रिक्वेस्ट करें सेंटर गवर्नमेंट को कि वहां के लिये यह शर्त लाए तो मैं समझता हूं मुनासिब होगा बजाए इसके जबरदस्ती एक पर लागू करें क्योंकि उनको आपने मेम्बर आफ दी हाउस जरूर बनाना है। मैं समझता हूं कि अगर इतनी बात ऐसे नहीं मानते, एमेंडमेंट नहीं मानते तो वैसे ही मान लें। वह रखना चाहें, रखें, न रखना चाहें, न रखें। उन पर बोझा क्यों डाला जा रहा है?]

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

59. "That at page 8, after line 28.

the following new clause be inserted, namely :

'15A(l)(a) The sixteen persons specified in the Seventh Schedule who are members of the Legislative Council of the existing State of Punjab shall on and from the appointed day, become members of the Legislative Assembly of the State of Haryana.

(2) The remaining thirty-five persons who are members of the Legislative Council of the existing State of Punjab shall on and from the appointed day become members of the Legislative Assembly of the State of Punjab.'"

The motion was negatived.

t[ ] Hindi transliteration.

Clauses 16 *and* 17 *were added to tht Bill.*

Clause 18 *Speakers and Deputy Speakers*

SHRI V. M. CHORDIA : I move :

60. 'That at page 9, for the existing clause 18, the following be substituted, namely :

'18. (1) As soon as may be after the appointed day, the Legislative Assembly of Haryana shall choose a member of that Assembly to be the Speaker of that Assembly and another remember of that Assembly to be the Deputy Speaker of that Assembly.

(2) As soon as may be after the appointed day, the Legislative Assembly of Punjab shall choose a member of that Assembly to be the Speaker of that Assembly and another member of that Assembly to be the Deputy Speaker of that Assembly'."

(The amendment also stood in the name of Shri Sundar Singh Bhandari.)

मंत्री महोदय ने जनरल डिसकशन के पश्चात् जो उत्तर दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि हमने यहां भी पुरानी परम्परा चलाई कि इसी तरह से स्पीकर और डिपुटी स्पीकर की व्यवस्था की। मैं एक नम्र निवेदन कर दूं कि यह आपस में काफी खींचातानी के पश्चात् बाउन्डरी कमीशन ने सारे निर्णय करके स्टेट्स बनाये, यह कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में जाने वाला है। ऐसी स्थिति में जब हम प्रजातंत्र के सिद्धांत को मानते हैं तो क्यों नहीं हम वहां की विधान सभा के सदस्यों को अधिकार दें कि वे चाहे जिसको स्पीकर बनाएं, डिपुटी स्पीकर बनाएं। हम यह प्रावधान रखकर क्यों अपने सिर पर जिम्मेदारी ले कि जो पहले स्पीकर थे उन्हीं को स्पीकर रखेंगे, डिपुटी स्पीकर रखेंगे, फलानी जगह का स्पीकर, डिपुटी स्पीकर रखेंगे।

सरदार रघुबीर सिंह पंजहजारी : यह पहले महाराष्ट्र में आप पास कर चुके हैं।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चोरड़िया : आप खड़े होकर पूछेंगे तो मैं इसका बहुत सारा जवाब दूंगा । उपसभापति महोदया, यदि कभी हम कोई बात कर बैठे तो क्या अब भी जरूरी है । हमने तो पंजाब का टुकड़ा होना नहीं चाहा था, हमने यहां एक कानून बनाया था फिर हम अपने टुकड़े करने लग गये, हमने गोल्ड कन्ट्रोल के खिलाफ आवाज उठाई थी, फिर एक बार पास होने के बाद वह क्यों सुधारने के लिये हमारे पास लाया गया । पहले बड़े फख्र के साथ कहते थे बड़ा अच्छा काम किया अब उसको पाप मानने लग गये । तो परिस्थिति के हिसाब से, देश और काल के हिसाब से हमें परिवर्तन करना चाहिये और करेंगे और अगर मैरिट के आधार पर हमारे पंजहजारी साहब चाहते हों कि यह डिमोक्रेसी के सिद्धांत के प्रतिकूल पड़ेगा और हम उनको चुनाव का अधिकार न दें, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरी सरीखी बुद्धि उनको दो । मैं चाहता हूं कि जब हम वहां के लोगों की असेम्बली बना रहे हैं तो उन लोगों को इस बात का अधिकार दिया जाय कि वे अपने स्पीकर चुन सकें, अपने डिप्टी स्पीकर चुन सकें । यह बात होनी चाहिये कि वे चुन कर आयें और इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं हो सकता । तो यह बात क्यों नहीं उनके ऊपर छोड़ दी जाती है और इस तरह का अधिकार क्यों लिया जा रहा है ? इसी आशय से मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया था और आशा है कि श्री पंजहजारी तथा अन्य सदस्य मेरे इस संशोधन का समर्थन करेंगे ।

The question was proposed.

श्री गुलजारीलाल नन्दा : थोड़े से समय के लिए यह व्यवस्था है । आगे भी ऐसा होता रहा है और इसमें कोई खास सवाल नहीं है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

60. "That at page 9, for the existing clause 18, the following be substituted namely :

'18. (1) As soon as may be after the appointed day the Legislative Assembly of Haryana shall choose a member of that Assembly to be the Speaker of that Assembly and another member of that Assembly to be the Deputy Speaker of that Assembly.

(2) As soon as may be after the appointed day, the Legislative Assembly of Punjab shall choose a member of that Assembly to be the Speaker of that Assembly and another member of that Assembly to be the Deputy Speaker of that Assembly.' "

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That clause 18 stand part of (he Bill."

The motion was adopted.

Clause 18 *was added to the Bill*

Clause 19 *was added to the Bill.*

Clause 20—*Legislative Council of Punjab*

THE DEPUTY CHAIRMAN : The two amendments to this clause are both negative amendments. Therefore I shall put clause 20 to vote.

SHRI V. M. CHORDIA : I am not moving the amendments, but I want to speak on both the amendments simultaneously.

यह जो दो प्रावधान किये गये हैं उसका आशय यह है कि हमारे यहां पर लेजिस्लेटिव कौंसिल बने । मेरा नम्र निवेदन है कि जब हम खर्च की इतनी बातें करते हैं, हम यह चाहते हैं कि हमारे यहां पर खर्च न बढ़े, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिये । सब प्रांतों में ऐसा है, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में लेजिस्लेटिव कौंसिल नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इस तरह का प्रावधान इसमें न करें क्योंकि इससे व्यर्थ का खर्च बढ़ेगा । इस आशय से मैं इसका विरोध करता हूं । ऐसा सोचकर आप इसे वापस ले लें और इस वक्त इसे पारित न करें ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That clause 20 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 20 *was added to the Bill.*

Clauses 21 *to 24 were added to the Bill.*

Clause 25—*Delimitation of constituencies*

SHRI C. L. VARMA : I move :

68. "That at page 12, lines 17-18, the words 'existing boundaries of administrative units' be deleted."

जो मेरा अमेन्डमेंट है वह यह है कि " 'existing boundaries of administrative units' be deleted." जब यह इलाका पंजाब का हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, जैसा कि माननीय मंत्री जी को खुद मालूम है कि जब हम कालका से शिमला को चलते हैं तो दो, दो फर्लांग के अन्दर कभी पंजाब का हिस्सा आता है और कभी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा आता है । इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिहाज से और कान्स्टीट्यूएन्सी के लिहाज से हमें इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा । अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वोटरों को कोई फायदा नहीं होगा । पहले भी इस तरह की तकलीफ हुई थी और हो सकता है कि दूसरे इलाकों में और दूसरे जिलों में इस तरह की तकलीफ हो लेकिन जहां तक महासू और शिमला का सवाल है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से कुछ न कुछ मिलाना ही होगा ।

The question was proposed.

श्री गुलजारीलाल नन्दा : कान्स्टीट्यूएन्सी अमेन्ड करने की बात इसमें नहीं आती है ।

SHRI C. L. VARMA : I beg leave to withdraw my amendment No. 68.

**Amendment No.* 68 *was, by leave, withdrawn.*

*For text of the amendment, *vide* col. 6503 *supra.*

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is ;

"That clause 25 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 25 *was added to the Bill.*

Clauses 26 *to* 28 *were added to the Bill.*

Clause 29—*Common High Court for Punjab, Haryana and Chandigarh*

THE DEPUTY CHAIRMAN : There is an amendment.

SARDAR RAGHBIR SINGH PANJHAZARI : Before that I raise a point of order, because this clause 29 is *ultra vires* the Constitution of India and because it says in sub-clause 29. (2) :

"The expenditure in respect of salaries and allowances of the Judges of the common High Court shall be allocated amongst the Staets of Punjab and Haryana and the Union in such proportion as the President may, by order, determine."

Now this provision runs counter to the provision in article 231 of the Constitution of India inasmuch as the common High Court contemplated in this Bill will be in the Union territory of Chandigarh. As such the expenditure in subclause 29. (2) should be met from the Consolidated Fund of India, and not met from the Funds of the States of Punjab and Haryana also.

चूंकि प्रिन्सिपली हाईकोर्ट चंडीगढ़ में होगा और वह यूनियन टैरीटरी में है, इसलिए सारे

THE DEPUTY CHAIRMAN : There is also an amendment on this, but the mover is not here.

شری عبدالغنی : میں پھر ہوم منسٹر صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر ایک ایسی دفعہ ہے جس پر ضرور چیلنج کرنا پڑے

[شری عبدالغنی]

گا - میں آپ سے عرض کرنا چاهتا هوں که اگر هم اس وقت چیلنج نہیں کر سکتے هیں کیوں که لوک سبها اٹھ گئی هے اور امینڈمینٹ کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتے هیں تو انہیں بھروسه دلانا چاهئے که اس کے لئے کوئی راسته نکالا جائے گا - اگر ایسا نہیں کیا جائیگا تو همیں چیلنج کرنا پڑے گا -

†[श्री अब्दुल गनी : मैं फिर होम मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि इस पर एक ऐसा दफा है जिस पर जरूर चेलेंज करना पड़ेगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हम इस वक्त चेलेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोक सभा उठ गई है और एमेंडमेंट को डिलीट नहीं कर सकते हैं तो उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए कि इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो हमें चेलेंज करना पड़ेगा।]

SHRI GULZARILAL NANDA: There is no question, of anything being *ultra vires* because, so far as the expenditure is concerned, the expenditure will be met by the Central Government and that is not a matter which is a matter of nay constitutional violation. I think the provision that has been made here is subject to the same protection which we get from aricle 4.

SARDAR RAGHBIR SINGH PANJ-HAZARI : In this question, Madam . ..

THE DEPUTY CHAIRMAN : After the Minister has spoken.

SARDAR RAGHBIR SINGH PANJ-HAZARI: I still raise my point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN : It cannot be now. Earlier you have had your say and the Minister had his say. Now I put clause 29 to the vote.

The question is :

"That clause 29 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 29 *was added to the Bill.*

SHRI ABDUL GHANI : Can we not raise a point of order ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : What point

میڈم ــــ کیا هم پوائنٹ آف آرڈر ریز نہیں کر سکتے هیں - اگر هم کر سکتے هیں تو آپ آئین کی دفعه دیکھ لیجئے - یه آئین میرے پاس هے اور اس کو پڑھ لیجئے -

†[श्री अब्दुल गनी : मेडम, क्या हम पाइन्ट आफ आर्डर रेज नहीं कर सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं तो आप आईन की दफा देख लीजिये, यह आईन मेरे पास है और इसको पढ़ लीजिये।]

SARDAR RAGHBIR SINGH PANJ-HAZARI : It is *ultra vires* the Constitution.

شری عبدالغنی : تو میں کہنا چاهتا هوں که اس سے تو آئین کا النگھن هو جائے گا -

†[श्री अब्दुल गनी : तो मैं कहना चाहता हूं कि इससे तो आईन का उल्लंघन हो जायेगा।]

of order ? This is a constitutional matter in which the Chair is not concerned. The Minister has replied and there can be no point of order after that. I have already put the clause to vote and it has been adopted.

Clause 30 way *added to the Bill.*

Clause 31—*Special provision relating to Bar Council and Advocates*

SHRI C. L. VARMA: Madarn, 1 move :

69. "That at page 14, lines 32-33, the words 'and Himachal Pradesh' be deleted."

उपसभापति महोदया, हमारी इस वक्त मुश्किल यह है कि हिमाचल प्रदेश की बार कौंसिल चंडीगढ़ में है और हाई कोर्ट उसका दिल्ली में होने वाला है । तो यह जो हमारी मुश्किल है इसको अगर माननीय मिनिस्टर साहब ठीक कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी ।

The question was proposed.

SHRI GULZARILAL NANDA: I am not accepting the amendment.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Are you pressing the amendment, Mr. Varma?

SHRI C. L. VARMA : 1 beg leave of the House to withdraw my amendment.

** Amendment No.* 69 *was, by leave, withdrawn.*

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That clause 31 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 31 was *added to the Bill.*

Clauses 32 *to* 47 *were added to the Bill.*

Clause 48—*Land and Goods*

SHRI ARJUN ARORA : Madam. 1 move :

71. "That at page 20, lines 11-12, for the words 'pass to the State of Punjab' the words 'be distributed among the three successor States on the basis of their population' be substituted."

*For text of the amendment, *vide* col. 6507 *supra.*

KUMARI SHANTA VASISHT : Madam, I move:

72. "That at page 20, lines 11-12, for the words 'pass to the State of Punjab' the words 'pass to the successor States on the basis of respective population :' be substituted."

(The amendment also stood in the names of Dr. Salig Ram and Shri Jagannath Prasad Pahadia.)

Th; questions were proposed.

SHRI ARJUN ARORA : Madarn, my amendment relates to clause 48 of the Bill. This clause 48 is part of Part VI relating to apportionment of assets and liabilities.

The clause, as drafted and presented by the Home Ministry, says :

"(1) Subject to the other provisions of this Part, all land and all stores, articles and other goods belonging to the existing States of Punjab shall,—

(a) if within that State, pass to the successor State in whose territories they are situated; or

(b) if outside that State, pass to the State of Punjab :"

This is the relevant portion. I have no objection whatsoever to part (a) where it says that the land, stores, articles and other goods belonging to the existing State of Punjab shall, if within that State, pass to the successor State in whose territories they are situated but I object to sub-caluse (b) which says that if they are ou'side that State, they shall pass to the State of Punjab. My amendment seeks to correct this and it says that the words "pass to the State of Punjab" be substituted by the words "be distributed among the three successor States on the basis of their population". I do not know how the Home Ministry which was obviously assisted by the Law Ministry has proposed such an unjust distribution of die assets of the existing State of Punjab by saying that anything outside the State of Punjab shall go only to one of the three successor States. Now the Home Minister, if not the Home Minister at least the Minister of State in the Ministry

[Shri Arjun Arora.]

of Home Affairs, knows the civil law. He probably knows the law of inheritance which lays dow$_n$ that the assets are to be distributed among all the successors. Why do you, therefore, provide that one particular asset will be distributed among the three successors while the other part of the assets will go only to the elder brother ?

DR. GOPAL SlNGH : The law of primogeniture.

SHRI ARJUN ARORA : The law of primogeniture is a feudal law. Dr. Gopal Singh, of course, belongs to the feudal society, if not a slave society.

DR. GOPAL SINGH : You belong to the feudal society.

SHRI ARJUN ARORA : He says he belongs to the feudal society.

DR. GOPAL SINGH : I said you belong to the feudal society.

SHRI ARJUN ARORA : Not I; I belong to a modern socialist society.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Be brief; this is an amendment.

SHRI ARJUN ARORA : Madam, 1 must meet the interruptions. The law of primogeniture is a feudal law under which the eldest son of the Rajah inherited the crown. I believe that Mr. Nanda is a good socialist Congressman; he does not belong to the feudal society and I hope he does not want to make the elder brother the successor of all the property or most of the property. So what has been said about the distribution of land, stores and other things within the State of Punjab should in equity be applied to land, stores and other things—and liabilities also if any—which are outside the State. I hope the Home Minister will accept this amendment of mine which is based on well-accepted principles of equity and Justice and which corresponds to the law of inheritance which is in force in the country. I must say, Madam, I am not partial to any part of the Punjab.

SHRI ABDUL GHANI : Although you are a Punjabi.

SHRI ARJUN ARORA : I am not a Punjabi; Punjab is my *sasural.* If at all, I am partial to Punjab but even amongst relations I believe in the principles of equity and justice and I earnestly urge upon the Home Minister to accept my amendment.

KUMARI SHANTA VASISHT: I have also the same amendment as that of Mr. Arora. As I said earlier aho, the assets and liabilities should be divided according to the population of each successor State. The lands, goods and other articles that belong to the Punjab State now should be divided on the basis of population among Haryana, Punjab and Himachal area and I think this is very important. This Bill has been framed in a very great hurry and the Committee had the big problem of dividing the assets and liabilities amongst the various States. Since many small mistakes would be noticed I urged upon the hon. Minister to kindly examine all these things and see that proportionally on the basis of population all the successor States get these assets.

AN. HON. MEMBER : It is a very sensible suggestion.

डा० शालिग्राम (पंजाब) : मैं एक बात कहना चाहता हूं । हमारे बड़े भाइयों ने कुछ चीजें हमसे छिपा ली हैं । जब छिपी हुई चीजें रोशनी में आएं तो मेरी मिनिस्टर साहब से यह दरखास्त है कि उन चीजों का भी वैसा बंटवारा कर दें जैसा और का कर रहे हैं ।

SHRI GULZARILAL NANDA : Taking the various clauses of this Part together, the answer to the questions raised is available in Part VI, if we read one clause along with several others. I may inform the hon. Member that there is clause 54 regarding public debts. Now, the public debts will be the debt of the States of Punjab Now, if one sees only this clause then he would see as if all the debts are to be apportioned to Punjab. There are further arrangements. When something is immediately taken over by one of the units, then further arrangements are made as to how it has to be apportioned later on. Similarly, in this case

there is a proviso to clause 48 for the purpose of the distribution of stores, articles and goods, *i.e.,* the Central Government may issue such directions as it thinks for a just and equitable distribution of the goods. In the first stage it is supposed to pass to the State of Punjab. Later on it is for distribution, etc. Now, there are other clauses, *viz.,* 64 and 65. By agreement any claim can be made and settled by the States concerned, under clause 64. Under clause 65, within three years there is an arrangement for equitable distribution. It is not intended that these buildings or lands or other things, which may be outside the State, are going to pass to and remain with Punjab. It is intended that tbey have to be redistributed on equitable lines and for that the Central Government is ultimately responsible.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Arora, are you withdrawing your amendment ?

SHRI ARIUN ARORA : The Home Minister ...

THE DEPUTY CHAIRMAN : After the Minister's reply, no question is permitted. Are you withdrawing your amendment No. 71 ?

SHRI ARIUN ARORA : The Minister's reply is not clear.

THE DEPUTY CHAIRMAN : It is not a proper procedure after the amendment has been replied to.

SHRI ARJUN ARORA : If he gives an assurance, I will withdraw it.

SHRI GULZARILAL NANDA: There is my assurance.

SHRI ARIUN ARORA : If he accept my amendment in spirit ...

SHRI GULZARILAL NANDA That is there.

SHRI ARJUN ARORA : Madam, beg leave to withdraw my amendmenl

'Amendment No. 71 *was, by leav. withdrawn.*

KUMARI SHANTA VASISHT : On his assurance, I withdraw my amendment. Madam, I beg leave to withdraw my amendment.

"Amendment No. 72 *was, by leave, withdrawn.*

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That clause 48 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 48 way *added to the Bill.*

Clauses 49 *to* 53 *were added to the Bill.*

Clause 54—*Public debt*

SHRI ABDUL GHANI : Madam, I move :

73. "That at page 24, line 20, after the word 'for' the words 'Irrigation Projects including' toe inserted."

74. "That at page 24, line 36, after the words 'expenditure on' the words 'Irrigation Projects including' be inserted."

The questions were proposed.

شری عبدالغنی : میڈم——اس پر میری بڑی سادھارن گذارش ہے - یہ پنجاب اور ہریانہ کے لوگوں کی موت اور زندگی کا سوال ہے - اریگیشن میں اس لئے لایا ہوں کیوں کہ اس میں بھاکڑہ اور بیاس کے لنک کا تو ذکر کر دیا - راوی پر جو بنا رہے ہیں جس میں راجستھان اور کشمیر کا بھی حصہ ہوگا میری درخواست ہے کہ یہ اس پر بالکل چپ ہیں اس میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا -

[شری عبدالغنی]

گوڑگاؤں میں بد قسمتی سے یا خوش قسمتی سے سیکولرزم پایا جاتا ہے - ۲ لاکھ کے قریب مسلمان بھی بستے ہیں ویسے ہریانہ کی آبادی کا وہ ۱۵ فی صدی حصہ ہیں - اس کو پانی نہیں مل سکتا جب تک یہ لفظ نہ رکھیں اور آب پاشی کی بجائے دوسرا رکھیں - میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حصہ ہے وہ محروم ہو جاتا ہے - اس میں راجستھان، کشمیر، ہریانہ اور پنجاب سبھی حیرانی میں رہینگے کہ کس طرح سے یہ بات چلنے والی ہے - مجھے تو کسی نہ کسی طرح کا اشورنس نہیں دینگے کیونکہ میں ارجن اروڑا نہیں ہوں - یہ بڑی بھول ہو گئی ہے کہ اس میں باقی کا ذکر نہیں آیا نروانا پروجکٹ کا اور راوی پروجکٹ کا - اس لئے کوئی راستہ نکالئے سب کے ساتھ ٹھیک ویوہار ہو کیونکہ نروانا پروجکٹ میں پنجاب کا بھی حصہ ہوگا ہریانہ کا بھی ہوگا - پنجاب پر کتنا بوجھ پڑے گا یا ہریانہ کو کتنا بوجھ اٹھانا پڑے گا - راوی پروجکٹ سے کتنا ہریانہ کو ملے گا کتنا راجستھان کو اور کتنا کشمیر کو اس پر چپ ہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالئے -

†[**श्री अब्दुल गनी** : मेडम, इस पर मेरी बड़ी साधारण गुजारिश है । यह पंजाब और हरियाना के लोगों की मौत और जिन्दगी का सवाल है । इरिगेशन में इसलिए लाया हूं क्योंकि इसमें भाखड़ा और ब्यास के लिंक का तो जिक्र कर दिया । रावी पर जो बना रहे हैं जिस में राजस्थान और काश्मीर का भी हिस्सा होगा मेरी दरख्वास्त है कि यह इस पर बिल्कुल चुप हैं इसमें क्या होगा और क्या नहीं होगा ।

गुड़गांव में बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से सैक्यूलरिज्म पाया जाता है । 2 लाख के करीब मुसलमान भी बसते हैं वैसे हरियाना की आबादी का वह 15 फीस दी हिस्सा हैं । उसको पानी नहीं मिल सकता जब तक यह लफ्ज न रखें और आबपाशी की बजाए दूसरा रखें । मैं समझता हूं कि यह जो हिस्सा है वह महरूम हो जाता है । इस में राजस्थान, काश्मीर, हरियाना और पंजाब सभी हैरानी में रहेंगे कि किस तरह से यह बात चलने वाली है । मुझे तो किसी न किसी तरह का एशोरेंस नहीं देंगे क्योंकि मैं अर्जुन अरोड़ा नहीं हूं । यह बड़ी भूल हो गई है कि इसमें बाकी का जिक्र नहीं आया । नरवाना प्रोजेक्ट का और रावी प्रोजेक्ड का । इसलिये कोई रास्ता निकालिये सब के साथ ठीक व्यवहार हो क्योंकि नरवाना प्रोजेक्ट में पंजाब का भी हिस्सा होगा हरियाना का भी होगा । पंजाब पर कितना बोझ पड़ेगा या हरियाना को कितना बोझ उठाना पड़ेगा । रावी प्रोजेक्ट से कितना हरियाना को मिलेगा, कितना राजस्थान को और कितना काश्मीर को, इस पर चुप हैं कोई न कोई रास्ता निकालिए ।]

श्री गुलजारी लाल नन्दा : इसमें रास्ता है । यह बहुत बड़ी चीज है । इसके लिये खास इन्तजाम है । बाकी जो केपिटल वर्क्स हैं उनका भी इसके साथ इन्तजाम है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Are you pressing your amendments ?

شری عبدالغنی : جب وہ کہتے ہیں کہ انتظام ہو جائے گا تو مجھے کیا ہے - میرا کام تو توجہ دلانا ہے -

[ ] Hindi transliteration.

†[श्री अब्दुल गनी : जब वह कहते हैं कि इन्तजाम हो जायेगा तो मुझे क्या है, मेरा काम तो तवज्जो दिलाना है ।]

Madam, I beg leave to withdraw my amendments.

* *Amendments Nos.* 73 *and* 74 *were, by leave, withdrawn.*

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That clause 54 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 54 *was added to the Bill.*

Clauses 55 *to* 66 *were added to the Bill.*

Clause 67—*Provisions as to certain Corporations*

SHRI V. M. CHORDIA : Madam, I move :

75. "That at pages 29 and 30, lines 36 to 38 and 1 to 27, respectively, be deleted."

{The amendment also stood in the name of Shri Sundar Singh Bhandari.)

SHRI M. P. BHARGAVA (Uttar Pradesh) : It is negative.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : माननीय भार्गव साहब ने कहा कि निगेटिव है । मेरा नम्र निवेदन है कि मैं आधा ही मिटवाना चाहता हूं । इसलिये इसको पूरा निगेटिव नहीं कहा जा सकता ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : It is not negative.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया: भार्गव साहब ने कहा, इसलिये मैंने आपके माध्यम से उत्तर दिया । उपसभापति महोदया, अब यह जो संशोधन दे रहा हूं वह इस आशय से दे रहा हूं कि तीन हिस्सों के बीच एक लिन्क कायम रखें उस दृष्टि से हमारे शासन ने चाहा कि चंडीगढ़ को अलग रखा जाय, हाई कोर्ट एक रखा जाय । ऐसी स्थिति में सिंचाई और बिजली के दोनों बोर्ड भी कायम रहें तो क्या आपत्ति है । इसमें कोई कठिनाई विशेष आने वाली है तो बाद में विचार करें । आज से ही कानून में प्रावधान कर दें जबकि इसके बारे में पंजाब सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पेज 48, पैराग्राफ 134 में लिखा है :—

"A legalistic approach to a complex problem on the just solution which depends the prosperity of many territorial units, would be impermissible. Having carefully considered the problem, we are of the view that constitution of Joint Boards, one for irrigation and another for power, of the beneficiary States and the State which is the source of supply of water and power, having authority to lay down policies and execute them, consistently with the legitimate needs of the States concerned, under the supervision of the Central Government may be a practical solution of the problem raised by the division of the territory into separate units in which the canal and power supply lines are situated."

तो इस दृष्टि से दोनों के बीच में लिंक रखने के लिए है, जैसा कि हमारे शासन का भी आशय है और दोनों प्रान्तों का विभाजन करने वालों का भी आशय है और इसी आशय से हाई कोर्ट भी रखा है । तो क्या कारण है कि धारा 67 में उपधारा (3) और (4) रख कर के अभी से उन बोर्ड्स को अलग करें, उनका फंक्शन अलग तय कर लें और एक अलग व्यवस्था करें ।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि पूरी धारा 67 का मैं विरोध नहीं करता, उपधारा (1) और (2) आप रख सकते हैं लेकिन उपधारा (3) और (4) को डिलीट कर दें क्योंकि अभी जितने लिंक रख सके, रखें । इसी वजह से मैंने संशोधन रखा है और आयोग की रिपोर्ट भी वैसी ही है ।

The question was proposed.

t[J Hindi transliteration.

*For text of the amendments, *vide* col. 6512 *supra.*

SHRI GULZARILAL NANDA : Our approach is certainly in the same spirit, but in the case of the Electricity Board those considerations would not apply. The administration of the main powerhouse would be with the Bhakra Board. This Electricity Board is only for distribution. It is not necessary that the distribution should be with the same body.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is ;

75. "That at pages 29 and 30., lines 36 to 38 and 1 to 27 respectively, be deleted."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is :

"That clause 67 *stand part of the Bill."*

The motion was adopted.

Clause 67 *was added to the Bill.*

Clouses 68 *and* 69 *were added to the*

شری عبدالغنی : میڈم——میرا ایک پوائنٹ آف آرڈر ہے اگر کوئی امینڈ مینٹ موو ہو گیا ہو اور اسکے بعد وہ ممبر حاضر نہ ہوں تو اسکے لئے کیا ہو سکتا ہے - اس پر کیا اس کا اثر پڑتا ہے - یہ کیا آپ فرمائینگی ؟

†[श्री अब्दुल गनी : मेडम, मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है अगर कोई अमेंडमेंट मूव हो गया हो और उसके बाद वह मेम्बर हाजिर न हों तो उसके लिये क्या हो सकता है ? इस पर इसका क्या असर पड़ता है । यह क्या आप फरमायेंगी ?]

THE DEPUTY CHAIRMAN : These were not moved at all.

Clauses 70 *to* 77 *were added to the BM.*

Clause 78*—Rights and liabilities in re. gard to Bhakra-Nangal and Beas Projects* THE DEPUTY CHAIRMAN : There is one amendment. That is barred. But you can speak on it, Mr. Ghani.

شری عبدالغنی : میڈم——امینڈمینٹ یہ ہے کہ آپ یہ بیاس اور ستلج کا ذکر کرتے ہیں لیکن راوی کا ذکر نہیں کرتے - میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ راوی کے پروجکٹ کا ذکر نہیں کیا - یہاں جو پانی کا ذکر کیا ہے اس میں بیاس اور ستلج کا تو ہے لیکن راوی کا نہیں ہے حالانکہ راوی کے پانی سے ہریانہ کو بھی، راجستھان کو بھی اور کشمیر کو بھی فائدہ پہنچتا ہے - تو اس لئے میں نے یہ کہا ہے کہ ستلج اور بیاس کے ساتھ ساتھ راوی کو بھی شامل کیا جائے - میرا خیال ہے کہ یہ بالکل سادھارن بات ہے اور اس کو تو قبول ہی کر لینگے -

†[श्री अब्दुल गनी : मेडम, एमेंटमेंट यह है कि आप यह व्यास और सतलुज का जिक्र करते हैं लेकिन रावी का जिक्र नहीं करते । मैंने पहले भी यह कहा था कि रावी के प्रोजेक्ट का जिक्र नहीं किया । यहां जो पानी का जिक्र किया है उसमें व्यास और सतलुज का तो है लेकिन रावी का नहीं है । हालांकि रावी के पानी से हरियाना को भी, राजस्थान को भी और काश्मीर को भी फायदा पहुंचता है । तो इसलिए मैंने यह कहा है कि सतलुज और व्यास के साथ साथ रावी को भी शामिल किया जाए । मेरा ख्याल है कि यह बिल्कुल साधारण बात है और उसको तो कबूल ही कर लेंगे ।]

t[ ] Hindi transliteration.

श्री गुलजारी लाल नन्दा : यह साधारण बात नहीं है क्योंकि जो अगले जमाने में, अगले 50, 100 वर्षों में, नये प्राजेक्ट्स बनेंगे उनकी बात है, उनको भी दाखिल कर लेने की जरूरत नहीं है । अभी तो इस समय जो प्राजेक्ट हैं उन्हीं का इसमें जिक्र है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That clause 78 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 78 *was added to the Bill.*

Clause 79—*Bhakra Management Board*

SHRI ABDUL GHANI: I move :

83. "That at page 40, line 10, after the word 'Ferozepur' the words Madhopur and Upper Bari Doab Canal up to the off-take of Madhopur Beas link and Madhopur Beas link' be inserted."

یہ بھی پانی کے ہی بارے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ۱۰۰ سال کے بعد ایک صدی کے بعد جو بنے گا اس کے لئے ہم کیا کریں ۔ میرا کہنا ہے کہ جو قومیں زندہ ہوتی ہیں وہ تو چار چار سو سال تک کا سوچتی ہیں ۔ یہ کانگریس سرکار ہی ہے کہ نت نئی ترمیمیں لاتی ہے اور لا کرکے اپنے ہی بلوں کو اپنی ہی باتوں کو ٹھکراتی ہے ۔

†[यह भी पानी के ही बारे में है ? कहते हैं कि 100 साल के बाद, एक सदी के बाद जो बनेगा उसके लिए हम क्या करें । मेरा कहना है कि जो कौमें जिन्दा होती हैं वह तो चार-चार सौ साल तक का सोचती हैं । यह कांग्रेस सरकार ही है कि नित नई तरमीमें लाती है और ला करके अपने ही बिलों को, अपनी ही बातों को ठुकराती है ।]

†[ ] Hindi transliteration.

The question was proposed.

श्री गुलजारी लाल नन्दा : अभी तो आज की ही बात लानी है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is ;

83. "That at page 40, line 10, after the word 'Ferozepur' the words Madhopur and Upper Bari Doab Canal up to the off-take of Madhopur Beas link and Madhopur Beas link' be inserted."

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That clause 79 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 79 *was added to the Bill.*

Clauses 80 *to* 97 *were added to the Bill.*

The First Schedule was added to the Bill.

The Second Schedule was added to the Bill.

The Third Schedule was added to the Bill.

The fourth Schedule

SHRI ABDUL GHANI: I move :

36. "That in the Fourth Schedule, for paragraph 1, the following be substituted namely :—

'1. Of the three sitting members whose term of office will expire on the 2nd April, 1968, such one as the Chairman of the Council of States may determine by drawing lot, shall be deemed to have been elected to fill one of the seats allotted to the State of Haryana and the other two sitting members shall

[Shri Abdul Ghani.]

be deemed to have been elected to fill two of the seats allotted to the State of Punjab.'"

I also move :

37. "That in the Fourth Schedule, for paragraph 2, the following be substituted, namely :—

'2. Of the four sitting members whose term of office will expire on the 2nd April, 1970, namely Shri Anup Singh, Shri Jagat Narain, Shrimati Mohinder Kaur and Shri Uttam Singh Dugal, Shri Jagat Narain shall be deemed to have been elected to fill one of the seats allotted to the State of Haryana and the oiher three sitting members shall be deemed to have been elected to fill three of the seats allotted *to* the State of Punjab.' "

The questions were proposed.

شری عبدالغنی : میڈم——یہ ایک ایسی سمسیا ہے جس کا جواب جس طرح سے نندہ جی نے دیا اس سے میں قطعی سٹسفائڈ نہیں ہوں - میرا جو سنشودھن ہے وہ تو میں چھوڑ دوں گا کیونکہ انہیں منظور نہیں کرنا ہے لیکن جو میرا مقصد ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے - آج نندہ جی نے جو جواب دینے کی کوشش کی اس میں انہوں نے امتیاز کیا ہے اپنے ممبروں میں - شری اٹوال کو اور شری نیکی رام جی کو کہتے ہیں ایک سیدھا ہریانہ میں جائے گا - ایک پنجاب اسٹیٹ میں جائے گا لیکن باقیوں کی لاٹری آئیگی - مجھے لاٹریوں سے جھگڑا نہیں ہے لیکن کیا کوئی دنیا میں ایسی مثال پیش کر سکینگے کہ اس طرح سے پارلیمنٹ نر پاپ کر دیا ہو کہ ایک ہی کیٹیگری کے ممبر ہیں - کسی نے ۱۹۶۸ کے بعد جانا ہے - کسی نے ۱۹۷۰ میں جانا ہے - کسی نے ۱۹۷۲ میں جانا ہے اور یہ اپنے آپ ان کو خیال آتا ہے کہ ان میں سے دو کو تو اس ڈھنگ سے یہاں یہاں بھیج دیں باقیوں کو لاٹری کے ذریعے سے - میں مان سکتا ہوں یہ کہتے ہیں جن کی جہاں جائیدادیں ہوں جہاں ان کے ووٹ ہوں وہاں جائیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس میں انہوں نے جو امتیاز رکھا ہے ایک فرق رکھا ہے ایک شیڈولڈ بنانے کے وقت وہ نہ عقل کی کسوٹی، نہ انصاف کی کسوٹی پر نہ آئین کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے ان کا کیا ادھیکار ہے - میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے——یدی آپ پر ہی چھوڑ دیں تو آپ کہینگے نندہ صاحب کی بڑی بھول ہوئی یا نندہ صاحب کے روپ میں ہند سرکار کی بڑی بھول ہوئی دونوں میں فرق ہوا - وہ کس طرح سے ڈرائینگے - وہ نہیں ڈرا سکتے وہ کنسٹی ٹیوشن کی کوئی دفعہ نہیں پیش کر سکتے جس دفعہ کی تحت وہ اپنا کوئی ایسا ہل لا سکتے ہیں - وہ اس طرح کا فرق کرینگے کہیں لاٹری ہوگی کہیں لاٹری نہیں ہوگی تو اس کے لئے ان کو اپنا شیڈول واپس لینا چاہئے یا سب کی لاٹری کرائیں - اگر

یہ نہیں ہو تو ایک اصول قائم کریں جس اصول کی بنا پر جس کی جائیداد ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی وہ اپنی اپنی جگہ جائینگے - جس کی ہمارے جیسے کی جائیداد نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو وہ تو ان کی بات مان لینگے - میں سمجھتا ہوں اس میں ان کی بڑی بھول ہوئی ہے - اس لئے اس کو بدلنا چاہئے - اسی میں ان کا فائدہ ہے اور اسی میں ہندوستان کا فائدہ ہے -

†[**श्री अब्दुल गनी** : मेडम, यह एक ऐसी समस्या है जिसका जवाब जिस तरह से नन्दा जी ने दिया उससे मैं कतई सेटिस्फाइड नहीं हूं । मेरा जो संशोधन है वह तो मैं छोड़ दूंगा क्योंकि उन्हें मंजूर नहीं करना है । लेकिन जो मेरा मक़सद है वह बड़ा इम्पोर्टेन्ट है । आज नन्दा जी ने जो जवाब देने की कोशिश की उसमें उन्होंने इम्तयाज़ किया है अपने मेम्बरों में । श्री अटवाल को और श्री नेकी राम जी को कहते हैं एक सीधा हरियाना में जाएगा, एक पंजाब स्टेट में जायगा लेकिन बाकियों की लाटरी आएगी । मुझे लाटरियों से झगड़ा नहीं है लेकिन क्या कोई दुनिया में ऐसी मिसाल पेश कर सकेंगे कि इस तरह से पार्लियामेंट ने पास कर दिया हो कि एक ही केटेगरी के मेम्बर हैं, किसी ने 1968 के बाद जाना है, किसी ने 1970 में जाना है, किसी ने 1972 में जाना है और यह अपने आप उनको ख्याल आता है कि उनमें से दो को तो इस ढंग से यहां यहां भेज दें बाकियों को लाटरी के जरिए से । मैं मान सकता हूं कि यह कहते हैं जिनकी जहां जायदादें हों, जहां उनके वोट हों, वहां जाएं वह तो समझ में आता है लेकिन इसमें उन्होंने जो इम्तयाज़ रखा है एक फर्क रखा है एक शिड्यूल बनाने के वक्त वह न अकल की कसौटी पर, न इन्साफ की कसौटी पर, न आईन की कसौटी पर पूरा उतरता है । उनका क्या अधिकार है ? मेरा अर्ज़ करने का मतलब यह है कि किसी भी तरह से—यदि आप पर ही छोड़ दें तो आप कहेंगे नन्दा साहब की बड़ी भूल हुई या नन्दा साहब के रूप में हिन्द सरकार की बड़ी भूल हुई दोनों में फर्क हुआ । वह किस तरह से डराएंगे । वह नहीं डरा सकते, वह कांस्टीट्यूशन की कोई दफा नहीं पेश कर सकते जिस दफा के तहत वह अपना कोई ऐसा बिल ला सकते हैं । वह इस तरह का फर्क करेंगे कहीं लाटरी होगी, कहीं लाटरी नहीं होगी तो इसके लिए उनको अपना शिड्यूल वापिस लेना चाहिए या सब की लाटरी कराएं । अगर यह नहीं हो तो एक असूल कायम करें जिस असूल की बिना पर जिसकी जायदाद इधर होगी या उधर होगी वह अपनी अपनी जगह जाएंगे । जिसकी हमारे जैसे की जायदाद न इधर हो न उधर हो वह तो उनकी बात मान लेंगे । मैं समझता हूं इसमें उनकी बड़ी भूल हुई है इसलिए उसको बदलना चाहिए । इसी में उनका फायदा है और इसी में हिन्दुस्तान का फायदा है ।]

सरदार राम सिंह (उत्तर प्रदेश) : मैं इसकी ताईद करता हूं ।

श्री गुलजारीलाल नन्दा : मैं जवाब तो दे चुका हूं । एक नाम जो अब दिया गया वह तो खास पंजाब के हैं ही, बाकी पहले दो नाम पहली केटेगरी के हैं, वे हरियाना के हैं, उनमें से एक को दिया जाना है । तो "ड्रा आफ लाट" के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, कोई एग्रीमेन्ट भी नहीं हुआ । तो इसमें कोई बात खिलाफ जाती है मैं नहीं मानता । इसकी आगे दलील तो हो चुकी है ।

DIWAN CHAMAN LALL : May I . . .

†[ ] Hindi transliteration.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The Minister has replied. I would like the procedure to be followed. After the Minister has replied, I do not think that we should invite any further comments on it.

The question is :

36. "That in the Fourth Schedule, for paragraph 1, the following be sub stituted, namely :—

'1. Of the three sitting members whose term of office will expire on the 2nd April, 1968, such one as the Chairman of the Council of States may determine by drawing lot, shall be deemed to have been elected to fill one of the seats allotted to the State of Haryana and the other two sitting members shall be deemed to have been elected to fill two of the seats allotted to the State of Punjab.'"

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

37. "That in the Fourth Schedule, for paragraph 2, the following be sub stituted, namely :—

'2. Of the four sitting members whose term of office will expire on the 2nd April, 1970, namely, Shri Anup Singh, Shri Jagat Narain, Shrimati Mohinder Kaur and Shri Uttam Singh Dugal, Shri Jagat Narain, shall be deemed to have been elected to fill one of the seats allotted to the State of Haryana and the other three sitting members, shall be deemed to have been elected to fill three of the seats allotted to the State of Punjab.' "

The motion was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is ;

"That the Fourth Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Fourth Schedule was added to the mil.

The Fifth Schedule was added io the Bill

The Sixth Schedule

THE DEPUTY CHAIRMAN : Amendment No. 96 is a negative amendment. Mr. Chordia, you can speak ou it.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया: धारा 21 पारित हो चुकी है । अब इस संशोधन को मूव करने से मुझे संतोष नहीं है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That the Sixth Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Sixth Schedule was added to th: Bill.

The Seventh Schedule was added to the Bill.

The Eighth Schedule was added to the Bill.

The Ninth Schedule was added to thi Bill.

The Tenth Schedule was added to the Bill.

The Eleventh Schedule was added to the Bill.

The Twelfth Schedule was added to the Bill.

The Thirteenth Schedule was added to the Bill.

The Fourteenth Schedule was added to the Bill.

The Fifteenth Schedule was added to the Bill.

The Sixte.mth Schedule

डा० शालिग्राम : मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें इस बिल में दर्ज कर दी गई हैं । यहां जो बड़े-

बड़े इम्पोर्टेण्ट प्रिंटिंग प्रेसेज हैं वे नहीं आए । में वजीर साहब का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता था ।

श्री गुलजारीलाल नन्दा : इसमें और इन्स्टीट्यूशन एड करने की बात है । उसका इंतजाम यूं भी हो सकता है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

"That the Sixteenth Schedule itand part of the Bill."

The motion was adopted.

Ths Sixteenth Schedule was added to the Bill.

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI GULZARILAL NANDA : Madam, I move :

"That the Bill be passed."

The question was proposed.

DIWAN CHAMAN LALL: Madam, on this third reading, may 1 reply to the hon. Home Minister in regard to myself and Moulvi Abdul Ghani ? I notice that what thg Home Minister said was that in regard to clause 1 of the Fourth Schedule, the choice has been left to the Chairman to decide which one of the two members shall go to Haryana, which one will go to Punjab. I draw his attention to clause 2 of the Fourth Schedule. In that he has not adopted this particular method. What he has done is this. He has put all the four names and said that there shall be a lot drawn by the Chairman of this House as to which one of these people shall go to Punjab and which one will go to Haryana. Now, why has he not adopted the same procedure in regard to clause 1 of the Fourth Schedule? Why has he made a difference. Now if you look at clause 3 again—that is what I was trying to point out to him—Clause 3 is entirely different, the procedure that he has adopted is entirely different from that which he has adopted in clauses 1 and 2. The procedure adopted in clause 3 is entirely different. I submit that there is discrimination in regard to this matter. Why he has done it, I do not know. I do not know, why. My hon. friend the Home Minister did it. For what reason did he do it, I do not know. And I am quite certain that none of the Members involved in this matter knows exactly why that was done, why Mr. Atwal was allotted to Punjab and the others were handed over to tbe choice of the Chairman by ballot that has to be held in regard to this particular matter. And when he says that it was the choice of choosing one of the two, the choice was also of choosing one of the four in clause 2. What happened in clause 2 was that all these four names were handed over to the ballot. Why were not all the three names handed over to the ballot as far as claose I is concerned ? There is no answer to this, there is really no answer to this why it was done, why different procedures were adopted. Ther$_e$ is no answer to this.

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : माननीया उपसभापति महोदया, तीसरे वाचन के समाप्त हो जाने के बाद यह बिल कानून के रूप में परिणत हो जायेगा । यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अपने देश में धीरे-धीरे करके बहुत से राज्य और रियासतें बनती चली जा रही हैं । पहले भी हमारे यहां बहुत से राज्य थे, उनको मिटाकर हमने थोड़े राज्य किये, लेकिन उसके बाद अब हमारी सरकार इस बात पर तुली हुई है कि और बहुत से राज्य धीरे-धीरे बनते चले जाएं, इसके चार संभावित परिणाम होने वाले हैं, एक परिणाम यह है कि निश्चित रूप से जनता के ज्ञान में यह बात आ गई है कि हमारा केन्द्रीय शासन बहुत कमजोर है । दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार की गलती पाकिस्तान के निर्माण के समय पर हमने की थी वह दूसरी बार फिर हम कर रहे हैं, धर्म के आधार पर प्रदेश का बंटवारा कर रहे हैं । तीसरी गलती यह है कि आगे चलकर हम पंजाब का राज्य जो कि एक शक्तिशाली राज्य होना चाहिये

[श्री निरंजन वर्मा]

था, वह और छोटा हो चला है । उसका परिणाम यह होगा कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा बफर स्टेट जो लोग होने देना चाहते थे या होने वाला था वह हो गया और एक छोटा-सा राज्य बीच में आने वाला है ।

महोदया, जैसा कि योरुप के हतिहास में हुआ है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक छोटा-सा टुकड़ा है, वहां पर जर्मनवाले लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, फ्रांस वाले लोग फ्रांस की भाषा बोलते हैं । इस जगह का नाम राइन लैंड है और यह राइन नदी के किनारे पर बसा हुआ है और यहां पर बहुमूल्य खदानें हैं । इसके बाद में संसार के दो बड़े युद्ध हो चुके हैं, लेकिन वह न कभी इधर हुआ और न कभी उधर हुआ । इस तरह से अंग्रेजों के समय में उन्होंने रूस और हिन्दुस्तान के बीच में अफगानिस्तान को एक बड़ा बफर स्टेट बनाया हुआ था । लेकिन आज दुःख के साथ कहा जाता है कि हमारी सरकार ने हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई बफर स्टेट नहीं बनाया है और न ही कोई बड़ा राज्य ही बना पाई है । उसने उल्टे जो सरहद पर बड़ा राज्य था उसको छोटा कर दिया है । हमारे योग्य मंत्री जी, श्री नन्दा जी, कहते हैं कि हमने एक बड़ी भारी विजय प्राप्त करली है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने निश्चित रूप से कुछ थोड़े से व्यक्तियों के सामने झुककर अपनी कमजोरी और शासन की कायरता बतलाई है । इसलिए हम उनसे यह संकल्प लेना चाहेंगे कि भविष्य में इस तरह के और छोटे छोटे राज्य नहीं बनने पायेंगे किसी भी दबाव में आकर, जिससे कि हमारा यह भारतवर्ष ही नष्ट न हो जाय । हमारी मंत्री जी से यही प्रार्थना है और यही हमारी मांग भी है ।

شری عبدالغنی : میڈم ڈپٹی چیرمین—اس تھرڈ اسٹیج میں کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا بل آیا ہو جس میں آئین کے ساتھ اتنی بے انصافی کی گئی ہو اور آئین کے خلاف باتیں کی گئی ہوں اور سادھارن انصاف کی خلاف باتیں کی گئی ہوں جیسا کہ دیوان صاحب نے ایکسپلین کیا یہ ایک ایسا بل ہے جس کو کسی بھی اسٹیج پر لاگو نہیں ہونا چاہئے اور نہ ان کے اوپر بوجھا ہی بڑھانا چاہئے - ہم زبردستی اس بل کے ذریعہ ہائی کورٹ کا خرچہ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں اگر ہم آرٹیکل ۲۲۹ اور ۲۳۱ کو دیکھیں تو اس سے یہ بات جمتی نہیں ہے جو کہ یہ بل میں بات لائی جا رہی ہے - بہر حال آپ کرنا چاہتے ہیں - آپ کی زیادہ تعداد ہے بے شک کیجئے لیکن آپ کو کوئی بھی ہسٹورین معاف نہیں کرے گا کیونکہ آپنے اپنی تعداد اور زیادتی کے ساتھ اس بل کو پاس کرا دیا ہے - لیکن میرا یقین ہے - ''آئی ایم شیور،، کہ لوگ اس کو نہیں مانیں گے - اور سپریم کورٹ تک گورنمنٹ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا - تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے اور ہماری سرکار کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے - لیکن آپ تعداد اور زیادتی کی وجہہ سے جو چاہے من

رہ گئے کہ ان کی اسٹیٹ کہاں ہے تو مجھے ڈر ہے کہ پنجاب کے بارے میں جس طرح افراتفری میں جلدی میں آپ نے یہ بل پاس کرکے ایک نئی اسٹیٹ بنا رہے ہیں اس کو پھر ختم نہ کر دیں - مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے اور ڈر بھی ہے اور ڈر اس وجہہ سے ہے کہ تمام ملک کے ۷ حصوں کے ۷ سٹیٹ بن سکتے تھے مگر آپ نے کئی بنا دئے اور زبانوں کی آڑ لے کر بنائے ہیں - مجھے خطرہ ہے کہ آپ کل کہیں اسی زبان کے بہانے سے جموں و کشمیر کے بھی ٹکڑے نہ کر دیں - پہلے ہی کشمیر کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں اور اب پھر سے جموں کشمیر کو ڈوگری زبان کے آدھار پر ، کشمیری زبان کے آدھار پر اور لداخ کو چونکہ وہاں پر بودھ لوگ بستے ہیں ان کی زبان کے آدھار پر اس طرح کے تین چھوٹے ٹکڑوں میں کہیں بانٹ دیں گے کیونکہ فرقہ پرست ایسی آوازیں اٹھا رہے ہیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہوگی - آپ علاقہ جیسے کہتے ہیں ہندی بولنے والوں کا تو اس میں بہار بھی ہے یو - پی - بھی ہے راجستھان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مدھیہ پردیش بھی ہے تو ان سب ہندی بولنے والوں کی ایک اسٹیٹ کیوں نہیں بنائی - ان کو الگ الگ علاقوں میں کیوں بانٹ میں آئے کر لیں لیکن مجھے ڈر ہے کہ آگے ایسا نہ ہو کہ یہ زبان کے آدھار پر جو کچھ اس سمے چل رہا ہے وہ آگے بھی چلتا رہے کیونکہ زبانیں ہم نے مانی ہیں - اگر زبان کے بارے میں ہریانہ والوں نے کہا کہ نہیں ہریانہ ملنا چاہئے اور اکالی بھائی چاہتے تھے کہ ان کا پنجابی صوبہ بننا چاہئے تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی لیکن اگر اس بنا پر اردو زبان بولنے والے کہتے کہ ان کی ایک ریاست ہو جیسے مغربی یو - پی - کیونکہ اردو زبان نے آزادی کے لئے سب سے زیادہ کام کیا ہے - لیکن زبان تو اردو ہے اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ مغربی یو - پی - میں ہندو مسلمان سب لوگ تقریباً ۱۰۰ فی صدی اردو بولتے ہیں اور ان کی زبان اردو ہے تو کل وہ کہینگے کہ ہم کو الگ ریاست دی جائے تو آپ کہینگے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ فرقہ پرست ہیں اور اسی لئے اسی قسم کی یہ آواز اٹھاتے ہیں - حالانکہ زبانوں کے آدھار پر آپ نے ریاستیں بنائی ہیں اور یہ ہریانہ اور پنجابی صوبہ بھی اسی بنا پر بنایا جا رہا ہے مجھے ان سے یہ بھی ڈر ہے کیونکہ انہوں نے پہلے وندھیہ کا اسٹیٹ بنایا ، مدھیہ بھارت کا اسٹیٹ بنایا ، پیپسو بنایا ، جو من میں آیا کیا اور جب چاہا ڈولی میں ڈال کر لڑکی کو باہر نکال دیا - اور لوگ دیکھتے

کشمیر کے بارے میں پوری پوری سوچ سمجھ اور فراخ دلی سے کام لینا چاہئے کیونکہ کشمیر کے لوگ محبت سے خود ہمارے ساتھ آئے تھے اور یہ بات شری نندہ جی کو سمجھ لینی چاہئے - کہ شیخ صاحب ریاست کو ہندوستان کے ساتھ لائے اور اب نندہ جی اسکو بانٹنے کی فکر میں ہیں - نندہ جی تو اتنے ہی حصہ کو جو ہمارے ساتھ ہے غنیمت سمجھے ہیں اور اس دوسرے حصہ کو ساتھ نہیں لا رہے ہیں وہ شیخ عبداللہ کی وجہہ سے ملا ہے چاہے انہیں جیل میں ڈال رکھا ہے لیکن وہ سب سے بڑے محب وطن ہیں اور انہیں جیل میں ڈال رکھا ہے انہیں رہا کرنا چاہئے - وہی سارا کشمیر ہمارے ساتھ رکھ سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں - مگر نندہ جی غنیمت سمجھتے ہیں جتنا کشمیر آ گیا ہے اتنا ہی کافی ہے کیونکہ باقی کے لئے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی - آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہی کافی ہے فرقہ پرست اب ایسی آوازیں اٹھا رہے ہیں - کہ ہماچل پردیش کے ساتھ جموں کو ملا دیجئے لداخ کو ملا دیجئے اور اسی طرح سے دہلی کو چھوڑ دیجئے-مجھے ڈر ہے کہ کہیں سرکار ایسا نہ کرے کیونکہ وہ زبان کا بہانہ لے کر پھر آئے گی کہ ایسا کر دو وہ اپنی زیادہ تعداد کے بھروسہ ہم سے اس طرح کی بات منوائینگے تو میں سمجھتا

[شری عبدالغنی]

دیا - میری سمجھ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ علاقوں کو کچھ حصوں میں بانٹ دیا جائے لیکن یہ زبان کے آدھار پر آپ نے ایک علاقہ کو کچھ حصوں میں بانٹ دیا یہ ٹھیک نہیں ہے - اسی طرح مجھے یہ ڈر ہے کہ آپ لوگ زبان کے آدھار پر کل کہیں کشمیر کو بھی نہ بانٹ دیں مجھے آپ کی اس سرکار سے سخت گلہ ہے - سخت شکایت ہے کیونکہ اس نے سب سے اچھے اور بہت بڑے وطن دوست اور بہادر ساتھی کو بلا وجہ نظر بند کر رکھا ہے - یہ وہی بہادر شیخ عبداللہ ہے جس کی رہنمائی میں سارے کشمیر نے ہمارا ساتھ دیا تھا اور اس وقت اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی تھی کہ پاکستان کیا کہتا ہے اس نے پاکستان کا مقابلہ کیا اور اس وقت جتنا جموں و کشمیر ہمارے پاس ہے وہ اس کی وجہ سے ہے اور جو حصہ آزاد کشمیر کہلاتا ہے اور پاکستان کے قبضے میں ہے اگر ہم پوری طرح شیخ صاحب کا ساتھ دیتے تو وہ بھی ہمارے ساتھ آ جاتا مگر اس کے حصول کی کوئی کوشش نہیں کی - اسکی واپسی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا - اسکے واپس لینے کے لئے تاشقند معاہدے میں شرط نہیں رکھوائی - مجھے ڈر ہے کہ کشمیر کے بارے میں ایسا حال نہ کریں جس سے ہماری ہانی ہو اور ہمارا نقصان ہو - جموں و

ہوں کہ اگر آپ نے اس طرح کی بات کی تو اس سے دیش کا نقصان ہوگا - اس لئے اس اسٹیج پر صرف یہی گذارش کرونگا کہ اگر آپ کو دیش سے پیار ہے ، اگر آپ نیشنل انٹیگریشن چاہتے ہیں ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ چین اور پاکستان ہی نہیں جو بھی ظالم ہمارے دیش کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا ہم اس کا مقابلہ کرینگے اس کی آنکھ نکال دینگے - تو پھر آپ کو یہ صوبہ جاتی پیار اور زبان کے پیار جیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تیاگنا ہوگا آج نہیں تو کل تیاگنا ہوگا ضرور چھوڑنا ہوگا - بڑا دل کرنا ہوگا - میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بل ہے وہ آئین کے خلاف ہے دیش کے ہت کے خلاف ہے اور یہ کہکر میں اس بل کی مخالفت کرتا ہوں -

†[**श्री अब्दुल गनी** : मेडम डिप्टी चेयरमेन, इस थर्ड स्टेज में कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं थी लेकिन बदकिस्मती यह है कि शायद ही कोई ऐसा बिल आया हो जिस में आईन के साथ इतनी बेइन्साफी की गई हो और आईन के खिलाफ बातें की गई हों और साधारण इन्साफ की खिलाफ बातें की गई हों जैसा कि दिवान साहब ने एक्सप्लेन किया। यह एक ऐसा बिल है जिसको किसी भी स्टेज पर लागू नहीं होना चाहिए और न उनके ऊपर बोझा ही बढ़ना चाहिए । हम जबरदस्ती इस बिल के जरिए हाईकोर्ट का खर्चा उनके ऊपर डाल रहे हैं । अगर हम आर्टिकल 229 और 231 को देखें तो इससे यह बात जमती नहीं है कि जो बिल में यह बात लाई जा रही है । बहरहाल, आप करना चाहते हैं । आपकी ज्यादा तादाद है, बेशक कीजिए लेकिन आप को कोई भी हिस्टोरियन माफ नहीं करेगा क्योंकि आपने अपनी तादाद और ज्यादती के साथ इस बिल को पास करा दिया है । लेकिन मेरा यकीन है , आई एम श्योर, कि लोग इसको नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक गवर्नमेंट का कोई साथ नहीं देगा । तो मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का कोई साथ देने वाला नहीं है और हमारी सरकार के पास कोई जवाब भी नहीं है । लेकिन आप तादाद और ज्यादती की वजह से जो चाहे मन में आए कर लें लेकिन मुझे डर है कि आगे ऐसा न हो कि यह जबान के आधार पर जो कुछ इस समय चल रहा है वह आगे भी चलता रहे क्योंकि जबानें हमने मानी हैं । अगर जबान के बारे में हरयाना वालों ने कहा कि इन्हें हरयाना मिलना चाहिए और अकाली चाहते थे कि उनका पंजाबी सूबा बनना चाहिए तो यह बात समझ में आ सकती थी लेकिन अगर इस बिना पर उर्दू जबान बोलने वाले कहते कि उनकी एक रियासत हो जैसे मगरबी यू० पी० क्योंकि उर्दू जबान ने आज़ादी के लिए सब से ज्यादा काम किया है, लेकिन जबान तो उर्दू है और यह बिल्कुल हकीकत है कि मगरबी यू० पी० में हिन्दू-मुसलमान सब लोग तकरीबन 100 फीसदी उर्दू बोलते हैं और उनकी जबान उर्दू है तो कल वह कहेंगे कि हमको अलग रियासत दी जाए तो आप कहेंगे कि यह मुसलमान जो हैं यह फिरका-परस्त हैं और इसीलिए इस किस्म की यह आवाज उठाते हैं । हालांकि जबानों के आधार पर आप ने रियासतें बनाई है और यह हरयाना और पंजाबी सूबा भी इस बिना पर बनाया जा रहा है । मुझे इनसे यह भी डर है क्योंकि उन्होंने पहले विन्ध्या का स्टेट बनाया, मध्य भारत का स्टेट बनाया, पेप्सू बनाया जो मन में आया और या जब

†[ ] Hindi transliteration.

[श्री अब्दुल ग़नी]

चाहा डोली में डाल कर लड़की को बाहर निकाल दिया । और लोग देखते रह गये कि उनकी स्टेट कहां है । तो मुझे डर है कि पंजाब के बारे में जिस तरह अफरातफरी में, जल्दी में, आपने यह बिल पास कर एक नई स्टेट बना रहे हैं उसको फिर खत्म न कर दें । मुझे इस बात की खुशी भी है और डर भी है और डर इस वजह से है कि तमाम मुल्क के 7 हिस्सों के 7 स्टेट बन सकते थे मगर आपने कई बना दिए और जबानों की आड़ लेकर बनाए हैं । मुझे खतरा है कि आप कल कहीं इसी जबान के बहाने से जम्मू व काश्मीर के भी टुकडे न कर दें । पहले ही काश्मीर के दो टुकड़े हो चुके हैं और जब फिर जम्मू व काश्मीर को डोगरी जबान के आधार पर, काश्मीरी जबान के आधार पर और लद्दाख की चूंकि वहां पर बौद्ध लोग बसते हैं उनकी जबान के आधार पर इस तरह के तीन छोटे टुकड़ों में कहीं बांट देंगे क्योंकि फिरकापरस्त ऐसी आवाजें उठा रहे हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यह अच्छी बात नहीं होगी । आप इलाका जैसे कहते हैं हिन्दी बोलने वालों का तो उसमें बिहार भी है, यू० पी० भी है, राजस्थान भी है और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश भी है तो उन सब हिन्दी बोलने वालों की एक स्टेट क्यों नहीं बनायी । उनको अलग अलग इलाकों में क्यों बांट दिया । मेरी समझ में यह बात आ सकती है कि इलाकों को कुछ हिस्सों में बांट दिया जाए लेकिन यह जबान के आधार पर आप ने एक इलाके को कुछ हिस्सों में बांट दिया यह ठीक नहीं है । इसी तरह मुझे यह डर है कि आप लोग जबान के आधार पर कल कहीं काश्मीर को भी न बांट दें ।

मुझे आपकी इस सरकार से सख्त गिला है, सख्त शिकायत है क्योंकि इसने सब से अच्छे और बहुत बड़े वतन दोस्त और बहादुर साथी को बिला वजह बन्द कर रखा है यह वही बहादुर शेख अब्दुल्ला है जिसकी राहनुमाई में सारे काश्मीर ने हमारा साथ दिया था और उस वक्त उस ने इस बात की परवाह नहीं की थी कि पाकिस्तान क्या कहता है । इसने पाकिस्तान का मुकाबला किया और इस वक्त जितना जम्मू व काश्मीर हमारे पास है वह उसकी वजह से है । और जो हिस्सा आजाद काश्मीर कहलाता है और पाकिस्तान के कब्जे में है अगर हम पूरी तरह शेख साहब का साथ देते तो वह भी हमारे साथ आ जाता मगर इसके हसूल की कोई कोशिश नहीं की । इसकी वापसी का कोई मुतालबा नहीं किया । इस के वापस लेने के लिए ताशकन्द मुआहिदे में शर्त नहीं रखवाई । मुझे डर है कि काश्मीर के बारे में ऐसा हाल न करें जिस से हमारी हानि हो और हमारा नुकसान हो । जम्मू व काश्मीर के बारे में पूरी पूरी सोच समझ और फराख़ दिली से काम लेना चाहिए क्योंकि काश्मीर के लोग मुहब्बत से खुद हमारे साथ आए थे और यह बात भी श्री नन्दा जी को समझ लेनी चाहिए कि शेख साहब रियासत को हिन्दुस्तान के साथ लाए और अब नन्दा जी उसको बांटने की फिकर में हैं । नन्दा जी तो उतने ही हिस्से को जो हमारे साथ है, गनीमत समझते हैं और इस दूसरे हिस्से को साथ नहीं ला रहे हैं । ताहम काश्मीर का जो हिस्सा हमारे साथ है वह शेख अब्दुल्ला की वजह से मिला है चाहे उन्हें जेल में डाल रखा है लेकिन वह सब से बड़े मुहिब्बे वतन हैं और उन्हें जेल में डाल रखा है, इन्हें रिहा करना चाहिए वही सारा काश्मीर हमारे साथ रख सकते हैं और ला सकते हैं मगर नन्दा जी गनीमत समझते हैं जितना काश्मीर आ गया है उतना ही काफी है क्योंकि बाकी के लिए उन्होंने आवाज नहीं उठाई । आप यह न समझें कि यही काफी है फिरका-परस्त अब ऐसी आवाजें उठा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के साथ जम्मू को मिला दीजिए, लद्दाख को मिला दीजिए और

इसी तरह से वैली को छोड़ दीजिए । मुझे डर है कि कहीं सरकार ऐसा न करे क्योंकि वह जबान का बहाना लेकर फिर आएगी कि ऐसा कर दो वह अपनी ज्यादा तादाद के भरोसे हम से इस तरह की बात मनवायेंगे तो मैं समझता हूं कि अगर आपने इस तरह की बात की तो इससे देश का नुकसान होगा । इसलिए इस स्टेज पर सिर्फ यह गुजारिश करूंगा कि अगर आपको देश से प्यार है, अगर आप नेशनल इंटिग्रेशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि चीन और पाकिस्तान ही नहीं जो भी जालिम हमारे देश की तरफ आंख उठा कर देखेगा हम उसका मुकाबला करेंगे उसकी आंख निकाल देंगे । तो फिर आपको यह सूबा, जाती प्यार और जबान के प्यार जैसी छोटी छोटी चीजों को त्यागना होगा, आज नहीं तो कल त्यागना होगा, जरूर छोड़ना होगा, बड़ा दिल करना होगा । मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो बिल है वह आईन के खिलाफ है, देश के हित के खिलाफ है और यह कहकर मैं इस बिल की मुखालफत करता हूं ।]

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : उपसभापति जी, मेरी इच्छा के विरुद्ध यह पंजाब का पुनर्गठन किया जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार के पास कोई चारा नहीं था । हमारी सरकार को यह चीज मजबूरन स्वीकार करनी पड़ी और पंजाब का बंटवारा करना पड़ा । हम सब राज्यसभा के सदस्यों को अपनी सदिच्छा उन्हें भेजनी चाहिये ताकि हरियाणा और पंजाब का सूबा खूब फले फूले, तरक्की करे और दोनों आपस में मिलकर रहें ।

चंडीगढ़ के बारे में कुछ धमकियां आई हैं । बाहर से भी धमकियां आई और यहां भी धमकियां दी गई और हमारे सदन के एक माननीय सदस्य श्री पंजहजारी जी ने गृह मंत्री जी के ऊपर छींटाकसी भी की तथा उन्हें कमजोर बतलाया । लेकिन यह बात सही नहीं है । जहां तक चंडीगढ़ को यूनियन टैरीटरी में रखने की बात है, कमिशन के दो सदस्यों की इस बारे में एक राय थी और एक सदस्य की एक राय थी । इसलिए कमिशन ने इस चंडीगढ़ को पंजाब को न दिया बल्कि बहुमत से हरियाणा को दिया । इसलिए सरकार ने सोच समझकर पंजाब और हरियाणा सूबों को बराबर के स्तर पर इस बारे में रखा । यह बात ठीक है कि दोनों की राजधानी वहां पर हो, लेकिन श्री नन्दा जी के बारे में यह कहना कि उन्होंने कमजोरी दिखलाई है, उचित मालूम नहीं देता है । वह बहुत स्ट्रांग हमारे होम मिनिस्टर हैं । यहां काश्मीर की समस्या की बात आई, पाकिस्तान की बात आई, चीन की भी बात आई । हमारे नन्दा जी का बराबर रुख यही रहा है कि यह बड़े मजबूत रहे हैं, लेकिन इन पर भी इल्जाम लगाये गये हैं । हमारी सरकार पर भी इल्जाम लगाये गये हैं । इस लिये अब आगे यदि कोई धमकी हो, चाहे वह संत फतेह सिंह की तरफ से हो या किसी की तरफ से हो, हमारी सरकार किसी धमकी के आगे झुके नहीं । ईस्टर्न जोन से भी ऐसी धमकी की बातें हो रही हैं, मिज़ो, नागालैंड और खासी जयंतिया हिस्से वाले भी धमकी की बातें कर रहे हैं और अभी गनी साहब ने भी कहा कि जम्मू और काश्मीर का भी इसी तरह से बंटवारा होगा । मैं यह नहीं कहता कि स्टेट्स का फार्मेशन नहीं होना चाहिये, लेकिन आगे आप को उस तरह से कोशिश करनी चाहिये जैसी कि आसाम में आवाज उठ रही है कि आसाम का भी बंटवारा होना चाहिये । वहां यह आवाज उठनी चाहिये कि आसाम, मनीपुर, त्रिपुरा, नेफा और नागालैंड को मिल जुल कर बार्डर का एक संगठित स्टेट बनना चाहिये । दिनोंदिन यह हवा जोर पकड़ रही है । लेकिन जहां धमकी दी जा रही है वहां यदि आपने शुरू में कमजोरी दिखलाई तो झगड़े हो सकते हैं, डंडे चल सकते हैं और दुकानें वगैरह जल सकती हैं । वोट लेने के लिये बहुत सी बातें हो सकती हैं । मैं सरकार को खबरदार कर देना चाहता हूं कि आसाम में दिसम्बर में कुछ सत्याग्रह शुरू होने वाला है और इधर

[श्री शीलभद्र याजी]

ऐसी वीकन्ड पालिसी रही है जिससे हमें कभी कभी झुकना पड़ता है। इस लिये ऐसी कमजोर पालिसी को छोड़ कर के, थोड़ा मुस्तैदी के साथ और मजबूती के साथ हमारी सरकार को अपना काम करना चाहिये। अब जैसे चंडीगढ़ को ही ले लीजिये। चंडीगढ़ के सम्बन्ध में जो आप निर्णय ले चुके हैं, उसको अगर कोई बदलवाना चाहे, तो उसको आप बदलें नहीं।

दूसरी बात यह है कि जब आपने पंजाब का बंटवारा किया है तो पंजाब की जितनी प्रापर्टी पंजाब से बाहर है, चाहे वह किसी भी स्टेट में हो, वह हरियाना को मिलनी चाहिये, पंजाब को मिलनी चाहिये और जब हिमाचल को आपने चार डिस्ट्रिक्ट्स दिये हैं तो उसको भी मिलनी चाहिये। इसमें सरकार को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। सब का समानता-पूर्वक बंटवारा करना चाहिये। रावी नदी के बारे में भी समस्या आई है। सरकार को इस पर सोचना चाहिये और जिस तरह से भाखरा नंगल का प्रबन्ध किया गया है, उसी तरह से इसका भी कोई उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ दिल से नहीं, लेकिन जो हालात पैदा हो गये हैं उनको देखते हुये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI M. P. BHARGAVA : Madam, I take this opportunity of wishing all prosperity to the newly created States of Punjab and Haryana and the extended Union territory of Himachal Pradesh and the newly created Union territory of Chandigarh. I will be failing in my duty if I do not protest against some of the remarks made by my hon. friend Shri Khobaragade during his speech. He comes from a big State himself, a big State like Maharashtra, and I do not know on what basis he demanded a division of the States of Uttar Pradesh and Bihar.

SHRI GULZARILAL NANDA : I took an hour, much longer than I had intended, in making a reply to the debate. I have, in the course of my reply, dealt with all the questions. Some of them were raised again here like reorganisation, creation of new units and also Chandigarh and it was stated that we are answerable for that. I will only say just one word about the matter which seems to have greatly upset my friend Diwan Chaman Lall. He seems to be, I shall not say unduly, worried about it. It was open to us to follow the course, which he suggested. The course that we have adopted here wai. also open to us. There is a good reason. Categories one, two and three do not stand on the same footing. About category one there was this question of having one Member to be allotted to Punjab. Surjeet Singh was already known to be in Punjab and among the two, Abdul Ghani and Diwan Chaman Lall, one had to be allocated to Punjab, deemed to be there again. Therefore, the question of bringing in Surjeet Singh also for the purpose of drawing this lot was not necessary. This is the answer. There is no discrimination. Here the reason, that may not be good enough for the hon. Member. Number three is also the same—one Member belonging to the area of Himachal Pradesh and one to Haryana. There was no need for a lot.

I will conclude with the expression of the hope and prayer that the two unit* which are being created will prosper, make rapid progress and develop cooperative, neighbourly and friendly relations among themselves.

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is :

'That the Biil be passed."

The motion was adopted.

STATEMENT *RE* STARRED QUESTION NO. 678 ANSWERED ON THE 26TH AUGUST, 1966

DR. KARAN STNGH'S PROPOSAL ON KASHMIR

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI GULZAWLAL NANDA) : Madam, in reference to the Starred Question No. 678 answered in this